● वर्ष : 17 ● अंक : 125 ● मूल्य : 02 रुपया मात्र ● पृष्ठ : 08

LKS

RNI NO.: DELHIN / 2008 / 23928

www.loktantrakishaan.com

दैनिक लोकतंत्र की शान

दिल्ली से प्रकाशित रविवार 22 फरवरी 2026 लोकतंत्र का स्तंभ

भारत-ब्राजील का पांच वर्षों में 20 अरब डॉलर से अधिक व्यापार का लक्ष्य

एजेंसी। नई दिल्ली

भारत और ब्राजील ने अगले पांच वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को 20 अरब डॉलर से अधिक बढ़ाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करते हुए रक्षा, ऊर्जा, डिजिटल प्रौद्योगिकी, महत्वपूर्ण खनिज और स्वास्थ्य सहित 10 प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की है। दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में शीघ्र सुधार और आतंकवाद के खिलाफ सख्त वैश्विक कार्रवाई की आवश्यकता पर भी जोर दिया। ब्राजील ने भारतीय वीजा धारकों के लिए व्यापारिक वीजा की सीमा 10 साल तक बढ़ा दी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज़ इनासियो लूला दा सिल्वा के बीच शनिवार को हैदराबाद हाउस में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में यह जानकारी दी गई। वार्ता के दौरान व्यापार, ऊर्जा, रक्षा, कृषि, जलवायु कार्रवाई, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), सेमीकंडक्टर, महत्वपूर्ण खनिज और वैश्विक दक्षिण के मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि दोनों नेताओं ने एक समावेशी और बहुध्रुवीय विश्व

10 प्रमुख क्षेत्रों पर सहमति

व्यवस्था के लिए अपने दृष्टिकोण को दोहराया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र, विशेष रूप से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधार का भी आह्वान किया। दोनों नेताओं ने आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक उड़ान को मजबूत करने के लिए अपनी मजबूत प्रतिबद्धता व्यक्त की। दोनों नेताओं ने स्पष्ट किया कि भारत और ब्राजील अगले पांच वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को 20 अरब डॉलर से आगे ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार केवल आंकड़ों का विषय नहीं, बल्कि पारस्परिक विश्वास और मजबूत रणनीतिक साझेदारी का प्रतीक है। बैठक के दौरान स्टील से जुड़े खनिज पदार्थों की आपूर्ति शृंखला को सुरक्षित और सुदृढ़ बनाने, डिजिटल सहयोग के लिए कार्ययोजना तैयार करने, फिल्म एवं मीडिया क्षेत्र में संयुक्त परियोजनाओं को बढ़ावा देने तथा पारंपरिक ज्ञान के आदान-प्रदान पर सहमति बनी। इसके अलावा स्वास्थ्य, एमएसएमई, उद्यमिता, मास कम्युनिकेशन, महत्वपूर्ण एवं दुर्लभ खनिज, ऊर्जा संक्रमण और औद्योगिक साझेदारी जैसे क्षेत्रों में कुल 10 बिंदुओं पर समझ विकसित की गई।

व्यापारिक वीजा की अवधि 10 वर्ष तक बढ़ाने की घोषणा

ब्राजील ने भारतीय वीजा धारकों के लिए व्यापारिक वीजा की अवधि 10 वर्ष तक बढ़ाने की घोषणा भी की। संयुक्त वक्तव्य में प्रधानमंत्री मोदी ने प्रौद्योगिकी और नवाचार को भविष्य की साझेदारी का आधार बताते हुए कहा कि एआई, सुपर कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर और ब्लॉकचेन जैसे क्षेत्रों में सहयोग को प्राथमिकता दी जाएगी। ब्राजील में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की दिशा में काम चल रहा है। दोनों देशों ने इस बात पर सहमति जताई कि प्रौद्योगिकी समावेशी होनी चाहिए और विकास का सेतु बननी चाहिए। ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग को मजबूत स्तंभ बताते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि हाइड्रोकार्बन के साथ-साथ नवीकरणीय ऊर्जा, एथेनॉल ब्लेंडिंग और सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल जैसे क्षेत्रों में भी साझेदारी बढ़ाई जाएगी। हरित विकास के लिए दोनों देशों की प्रतिबद्धता साझा है। महत्वपूर्ण खनिज और रेयर अर्थ से जुड़े समझौतों को उन्होंने सुदृढ़ आपूर्ति शृंखला निर्माण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया। कृषि क्षेत्र में क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर, प्रिसिजन फार्मिंग और बायो फर्टिलाइजर पर सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी। स्वास्थ्य एवं फार्मा क्षेत्र में भारत से ब्राजील को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाओं की आपूर्ति बढ़ाने तथा पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में सहयोग को भी आगे बढ़ाया जाएगा। मोदी ने कहा कि भारत और ब्राजील इस बात पर एकमत हैं कि आतंकवाद और उसके समर्थक पूरी मानवता के शत्रु हैं तथा इसके खिलाफ एकजुट वैश्विक कार्रवाई आवश्यक है। वर्तमान वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए अंतरराष्ट्रीय संस्थानों में सुधार अपरिहार्य है और संवाद तथा कूटनीति ही समाधान का मार्ग है। वहीं राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा ने संयुक्त पत्रकार वार्ता में कहा कि दोनों देश अपनी 20 वर्ष पुरानी रणनीतिक साझेदारी को क्रियान्वयन के नए चरण में ले जा रहे हैं।

ज्वलंत मुद्दा | संपादकीय

अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने बताए ट्रंप के अधिकार,टैरिफ रद्द

अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका दिया है। अमेरिका की सर्वोच्च अदालत की 9 जजों की खंडपीठ ने 6 जजों के बहुमत से राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा पिछले 1 साल मैं जिन देशों के ऊपर टैरिफ लगाया गया था, उसको अवैध करार दिया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अधिकांश देशों पर टैरिफ लगाकर समझौते के लिए जो दबाव बनाया जा रहा था। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार राष्ट्रपति को इस तरह से टेरिफ़ लगाने का कोई अधिकार ही नहीं था। इसके बाद भी डोनाल्ड ट्रंप ने आपातकालीन अधिकारों का प्रयोग करके, सारी दुनिया के देशों को डरा-धमकाकर मनमाफिक तरीके से समझौते करना चाहते थे। इसमें कुछ हद तक डोनाल्ड ट्रंप सफल भी हो गए हैं। भारत जैसे बड़े राष्ट्र को उन्होंने अपने शिकंजे में कस लिया है। भारत के साथ उन्होंने द्विपक्षी व्यापार मे टैरिफ को लेकर समझौता करने में सफल रहे हैं।

इसी तरह का समझौता उन्होंने कई अन्य देशों के साथ भी पिछले कुछ महीनो में किए हैं। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा टैरिफ का भय दिखाकर जो समझौते किए हैं। उस समझौते में कहीं ना कहीं ट्रंप का परिवार का फायदा शामिल है। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के मित्र देशों और दुनिया के अन्य देशों में टैरिफ का भय दिखाकर अमेरिका के राष्ट्रीय हितों और अमेरिका की साख को एक बड़ा नुकसान पहुंचाने का काम किया है। इसके साथ ही टेरिफ़ के कारण अमेरिका की महंगाई बढी है, अमेरिका के व्यापारियों को बड़ा नुकसान हुआ है। टैरिफ के कारण सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका को भोगना पड़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने। इसके बाद अमेरिकी कानून के अनुसार वह तीसरी बार राष्ट्रपति नहीं बन सकते हैं। एक तरह से उन्होंने अपने दूसरे कार्यकाल का फायदा अपने परिवार को पहुंचाने के लिए, जो रणनीति अपनाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के निर्णय की समीक्षा कर उसे पूरी तरह से अवैध करार कर दिया है।

सुप्रीम कोर्ट का कहना है इस तरह के अधिकार केवल संसद को प्राप्त हैं। राष्ट्रपति को कुछ अधिकार आपातकालीन स्थितियों के लिए दिए गए थे। टेरिफ़ का निर्णय विषम परिस्थिति मे किसी एक या दो राष्ट्रों के साथ हो सकती थी। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने इस कानून के तहत आपातकालीन अधिकार का इस्तेमाल करके मनमाने तरीके से टेरिफ़ लगाए गए हैं। वह अधिकारों का दुरुपयोग है। अमेरिका के व्यापारी यह मुकदमा विभिन्न अदालतों में लड़ते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे। सभी अदालत से ट्रंप को मुंह की खानी पड़ी थी। टैरिफ लगाए जाने के बाद अमेरिका में महंगाई बढ़ रही थी। अमेरिका के व्यापारियों के व्यापारिक हित प्रभावित हो रहे थे।

सैयद जकी हैदर | सम्पदक/प्रकाशक
MOBE NO.9911371802
EMAIL. SYEDZAKIHAIDER786@GMAIL.COM

संक्षिप्त समाचार

जम्मू-कश्मीर में सड़क किनारे रखा था आईईडी, सुरक्षाबलों ने की आतंकी साजिश नाकाम

श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के गांदरबल में सड़क के किनारे ही इंप्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस (आईईडी) मिला है। कोहेस्तान कॉलोनी के पास ही गुलाब शेख मोहल्ले में इसे सड़क किनारे एक बैग में रखा गया था। हालांकि एजेंसियों को इसकी जानकारी मिल गई और बम निरोधक दस्ते ने पहुंचकर इसे निष्क्रिय कर दिया। एक दिन पहले ही बारामुला जिले के जांबाजपोरा इलाके में आईडी मिला था। सेना ने आईईडी मिलने के बाद इसे निष्क्रिय कर दिया। सेना का कहना है कि यह आतंकियों की साजिश है। बता दें घाटी में सुरक्षाबलों की सतर्कता और एजेंसियों के अलर्ट के चलते कई हादसे टाले गए हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली में आतंकी खतरे की आशंका संबंधी खुफिया जानकारी मिलने के बाद शनिवार को लाल किले के आसपास के इलाके और चांदनी चौक के कुछ हिस्से समेत प्रमुख धार्मिक और ऐतिहासिक स्थलों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है।

भारत के लिए नियम तोड़ने को तैयार इजरायल, देगा सीक्रेट हथियारों का बड़ा जखीरा

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25-26 फरवरी को इजरायल की दो दिवसीय महत्वपूर्ण यात्रा पर जा रहे हैं। वैश्विक भू-राजनीति के तेजी से बदलते समीकरणों के बीच यह यात्रा भारत और इजरायल के बीच रक्षा और सामरिक साझेदारी को एक अभूतपूर्व ऊंचाई पर ले जाने वाली मानी जा रही है। इस दौरे का मुख्य केंद्र भारत की सुरक्षा प्रणाली को अभेद्य बनाना और अत्याधुनिक रक्षा तकनीकों का हस्तांतरण है। हालांकि इस यात्रा के दौरान किसी एक बड़े रक्षा सौदे पर औपचारिक हस्ताक्षर होने की संभावना कम है, लेकिन इसका मुख्य कारण यह है कि दोनों देशों के बीच रक्षा संबंध अब किसी एक सौदे तक सीमित न रहकर एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया बन चुके हैं। विशेषज्ञों का अनुमान है कि अगले कुछ वर्षों में यह द्विपक्षीय रक्षा सहयोग 10 अरब अमेरिकी डॉलर के विशाल आंकड़े को पार कर जाएगा। सूत्रों के अनुसार, इस बार इजरायल अपनी सबसे गोपनीय और अत्याधुनिक रक्षा तकनीकें भारत के साथ साझा करने पर सहमत हो गया है। इसमें हाई-टेक लेजर डिफेंस सिस्टम और स्टैंड-ऑफ मिसाइल सिस्टम जैसे घातक हथियार शामिल हैं।

ब्राजील के राष्ट्रपति लूला का राष्ट्रपति भवन में स्वागत, दोनों देशों के बीच बैठक

एजेंसी। नई दिल्ली

ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा का राष्ट्रपति भवन में स्वागत किया गया। इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और पीएम नरेंद्र मोदी भी मौजूद थे। दोनों नेताओं के बीच दिल्ली के हैदराबाद हाउस में बैठक हुई। यह मुलाकात दोनों देशों के बीच व्यापारिक समझौते को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम साबित हो सकती है, जिसमें क्रिटिकल मिनरल्स, रेयर अर्थ्स, डिफेंस, एनर्जी और एआई जैसे क्षेत्रों पर खास फोकस किया गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ब्राजीली राष्ट्रपति लूला 18 से 22 फरवरी तक भारत के राजकीय दौरे पर हैं। भारत-ब्राजील संबंधों पर लुला ने कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार सिर्फ 15 अरब डॉलर है, जिसे 30-40 अरब तक बढ़ाना चाहिए। वे 260 ब्राजीलियाई व्यवसायियों के साथ आए हैं ताकि अंतरिक्ष, रक्षा, फार्मा जैसे क्षेत्रों में साझेदारी हो। एयरोस्पेस कंपनी एम्ब्रेयर भारत में प्लांट खोलेगी। दोनों देश ग्लोबल साउथ के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं और उदाहरण पेश कर सकते हैं। लुला ने यह बात एक इंटरव्यू में कही थी। शनिवार को पीएम मोदी और ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला डी सिल्वा के बीच होने वाली द्विपक्षीय मुलाकात में क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ्स पर एक अहम समझौते पर हस्ताक्षर होने की संभावना है।

सरकार-उद्योग-समाज के समन्वय से ही होगा रूपांतरणः उपराष्ट्रपति

एजेंसी। नई दिल्ली

उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि देश के समग्र रूपांतरण के लिए सरकार, उद्योग और समाज के बीच सशक्त समन्वय अनिवार्य है तथा यही विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने का आधार बनेगा। उपराष्ट्रपति शनिवार को यहां भारत मंडपम में एक मीडिया ग्रुप के कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत की विकास यात्रा के इस परिवर्तनकारी दौर में ऐसा सहयोग और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्होंने पिछले एक दशक में देश की प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत विश्व की दसवीं अर्थव्यवस्था से चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है और तीसरे स्थान की ओर अग्रसर है। संरचनात्मक सुधारों, समावेशी विकास, डिजिटल संपर्क, वित्तीय समावेशन और आधारभूत ढांचे के विस्तार से 25 करोड़ से अधिक नागरिक अत्यधिक गरीबी से बाहर आए हैं और देशभर में नई आकांक्षाएं जगी हैं। उन्होंने कहा कि विकास के अगले चरण में सरकार, उद्योग और नागरिक समाज के बीच गहन साझेदारी की आवश्यकता है। उनके अनुसार कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) अब परिधि का विषय नहीं बल्कि राष्ट्रीय प्रगति का केंद्रीय स्तंभ बन चुका है, जहां उद्यम और संवेदना का संगम होता है। 'आत्मनिर्भर भारत' और 'विकसित भारत @ 2047' के दृष्टिकोण का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि विकास व्यापक, समावेशी और टिकाऊ होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सीएसआर के माध्यम से सार्वजनिक शिक्षा को सुदृढ़ किया जा सकता है, दूरदराज क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाया जा सकता है, उद्योग-संरेखित कौशल विकास को बढ़ावा दिया जा सकता है, महिला-नेतृत्व वाले उद्यमों को समर्थन दिया जा सकता है तथा नवीकरणीय ऊर्जा और जलवायु अनुकूल पहल के जरिए हरित परिवर्तन को गति दी जा सकती है।

9 महीने में ईडी ने 32,500 करोड़ की संपत्ति की अटैच, सबसे ज्यादा अनिल अंबानी ग्रुप की

नई दिल्ली। इस वित्त वर्ष के पहले 9 महीने में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) 32,500 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच कर चुकी है। केंद्र सरकार के दस साल का रिकॉर्ड देखें तो अटैच की गई जमीन-जायदाद में 8 गुना से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। इस साल सबसे बड़ी गाज अनिल अंबानी समूह पर गिरी, जिसकी 5600 करोड़ की संपत्ति अटैच की गई। इसके अलावा क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड में 4190 करोड़ रुपए, पर्ल ग्रुप पोंजी के 3436 करोड़ रुपए और यूनाइटेड रियल एस्टेट के 1000 करोड़ रुपए की संपत्तियां भी इस दायरे में आई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल की तुलना में इस बार 141फीसदी अधिक संपत्ति अटैच की गई है। एजेंसी कुल मिलाकर अब तक 1.55 लाख करोड़ की संपत्ति अटैच कर चुकी है, जो एक साल के गृह मंत्रालय के बजट के बराबर है। इसमें बैंक खाते, एफडी, शेयर, वाहन, लग्जरी आइटम, कॉर्पोरेट प्रॉपर्टी और इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो शामिल हैं। पीएमएलए की शुरुआती जांच के बाद संपत्ति जब्त की गईं और न्यायिक प्रक्रिया के आधार पर कोर्ट में अटैचमेंट सही भी पाए गए लेकिन बड़ी बाधा अदालती प्रक्रिया लगातार खिंचते जाने की है और मामले पर फैसला आने तक संपत्ति फ्रोजन हालत में रहती है।

जेपी नड्डा ने सीआरआई कसौली में की नई टीडी वैक्सीन लॉन्च

सोलन। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने शनिवार को हिमाचल प्रदेश के सोलन जिला स्थित केंद्रीय अनुसंधान संस्थान (सीआरआई) कसौली में टीटनेस और एडल्ट डिफ्थीरिया (टीडी) वैक्सीन का औपचारिक शुभारंभ किया। यह स्वदेशी वैक्सीन सीआरआई के वैज्ञानिकों के प्रयासों से विकसित की गई है और अब इसे राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जाएगा। इस अवसर पर मंत्री ने कहा कि यह टीडी वैक्सीन किशोरों, वयस्कों तथा गर्भवती महिलाओं को टीटनेस और डिफ्थीरिया जैसी गंभीर बीमारियों से सुरक्षा प्रदान करेगी। उन्होंने बताया कि यह वैक्सीन पूर्व में उपयोग की जा रही टीटनेस टॉक्सॉइड (टीटी) वैक्सीन का स्थान लेगी, जिससे डिफ्थीरिया के विरुद्ध भी अतिरिक्त सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी। मंत्री ने कहा कि भारत दवाओं और वैक्सीन निर्माण के क्षेत्र में विश्वस्तरीय पहचान बना चुका है और इसमें सीआरआई कसौली की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। लगभग 120 वर्षों के इतिहास वाले इस संस्थान ने देश के सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने में अहम योगदान दिया है।

अमेरिका ने 10 फीसदी ग्लोबल टैरिफ किया लागू, भारत को भी देना होगा!

एजेंसी। नई दिल्ली

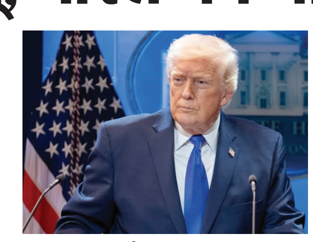

अमेरिका ने 10फीसदी ग्लोबल टैरिफ लागू कर दिया है। व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने इसकी पुष्टि की है कि यह टैरिफ तब तक प्रभावी रहेगा जब तक कोई अन्य कानूनी प्राधिकरण लागू नहीं किया जाता। भारत भी इस नई व्यवस्था के तहत 10फीसदी टैरिफ चुकाने वाले देशों में शामिल होगा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अधिकारी से पूछा गया कि क्या भारत को 10फीसदी टैरिफ देना होगा और क्या यह आईईईपीए के तहत लगाए गए पुराने टैरिफ की जगह लेगा तो उन्होंने साफ कहा कि हां, 10 फीसदी तब तक लागू रहेगा, जब तक कोई अन्य प्राधिकरण लागू नहीं होता। अधिकारी ने सभी व्यापार साझेदारों को अमेरिका के साथ हुए व्यापार समझौतों का पालन करने की सलाह दी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यह फैसला ऐसे समय आया है, जब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप प्रशासन को बड़ा झटका दिया। कोर्ट ने कहा कि 1977 के आईईईपीए कानून के तहत राष्ट्रपति को व्यापक आयात शुल्क लगाने का स्पष्ट अधिकार नहीं है। संविधान के मुताबिक यह शक्ति कांग्रेस के पास है। सीजेआई तीन न्यायाधीशों ने बहुमत का समर्थन किया। वहीं कई ने असहमति जताई और प्रशासन की शक्तियों का समर्थन किया। इस फैसले से अरबों डॉलर के रेसिप्रोकल" और टैरिफ अमान्य हो गए हैं। अनुमान है कि सरकार को 130 से 175 अरब डॉलर तक की वसूली पर रिफंड दावों का सामना करना पड़ सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भयानक और लुडिक्रस बताया। उन्होंने कहा कि मैं आईईईपीए के तहत 1 डॉलर भी नहीं ले सकता।

लाल किला सहित देश के कई बड़े मंदिर आतंकियों के निशाने पर, सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर

एजेंसी। नई दिल्ली

खुफिया एजेंसियों ने राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली सहित देश के कई बड़े शहरों में आतंकी हमले की आशंका को देखते हुए एक बड़ा अलर्ट जारी किया है। ताजा खुफिया इनपुट्स के अनुसार, पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले और अन्य प्रमुख शहरों के प्रसिद्ध मंदिरों को निशाना बनाने की साजिश रच रहा है। इस खतरे को देखते हुए देश भर के संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त कर दी गई है। खुफिया रिपोर्टों के अनुसार, आतंकी संगठन का मुख्य उद्देश्य भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक स्थलों और धार्मिक केंद्रों को निशाना बनाकर सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना और देश में दहशत का माहौल पैदा करना है। विशेष रूप से अयोध्या, वाराणसी और मथुरा जैसे धार्मिक महत्व वाले शहरों के प्रमुख मंदिरों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। अंदेशा जताया गया है कि आतंकी लाल किले के आसपास के क्षेत्रों और पुरानी दिल्ली के घनी आबादी वाले चांदनी चौक इलाके में मौजूद मंदिरों में इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस के जरिए धमाके करने की कोशिश कर सकते हैं। सुरक्षा सूत्रों के मुताबिक, यह साजिश 6 फरवरी को इस्लामाबाद की एक मस्जिद में हुए धमाके के प्रतिशोध के रूप में रची गई है। पाकिस्तान ने उस घटना के लिए निराधार रूप से भारत पर आरोप लगाए थे, जिन्हें भारत सरकार ने पूरी तरह खारिज कर दिया था। अब खुफिया सूचनाओं से संकेत मिले हैं कि लश्कर के आतंकी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं। इनपुट्स मिलने के बाद दिल्ली पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने संवेदनशील क्षेत्रों, विशेषकर पुरानी दिल्ली और पर्यटन केंद्रों पर निगरानी बढ़ा दी है। अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती के साथ-साथ संदिग्ध वाहनों की सघन तलाशी ली जा रही है और एंटी-सैबोटेज जांच शुरू कर दी गई है। नागरिकों से भी अपील की गई है कि वे किसी भी संदिग्ध वस्तु या गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें।

एआई शिखर सम्मेलन के दौरान कांग्रेस का प्रदर्शन शर्मनाकः वैष्णव

नई दिल्ली। दिल्ली में एआई शिखर सम्मेलन'के दौरान भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के विरोध

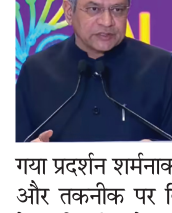

प्रदर्शन को इलेक्ट्रानिक्स एवं आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने "शर्मनाक" बताया है। वैष्णव ने शनिवार को मीडियाकर्मियों से कहा कि योजन के दौरान कल (शुक्रवार) युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की ओर से किया गया प्रदर्शन शर्मनाक है। जब पूरी दुनिया भारत की प्रगति और तकनीक पर विश्वास जता रही है, ऐसे समय में देश की छवि को नुकसान पहुंचाना दुर्भाग्यपूर्ण है। उनकी (कांग्रेस) राजनीति एंटी-यूथ (युवा-विरोधी) है और वे देश में आ रही नई तकनीक और प्रयासों के मार्ग में बाधा बन रहे हैं। उल्लेखनीय है कि एआई शिखर सम्मेलन के दौरान भारतीय युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केन्द्र सरकार के खिलाफ विरोध-प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने अपनी टी-शर्ट उतारकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के खिलाफ नारे लगाए। बाद में, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया गया।

Mfg & mkt by.. ANGEN PHARMACEU-TICALS (OPC) PRIVATE LIMITED

Distributorship ke liye contact Karen .
(9315755133 / ya email Karen)
angenpharmaceuticals@gmail.com

खास खबर

सुभाष नगर मेट्रो रेड लाइट के पास हादसा, स्कूटी सवार युवक की मौत

लोकतंत्र की शानः नई दिल्ली। पश्चिमी दिल्ली के तिलक नगर थाना क्षेत्र में शनिवार तड़के एक दर्दनाक सड़क हादसे में 25 वर्षीय युवक की मौत हो गई। घटना सुभाष नगर मेट्रो रेड लाइट के पास, नजफगढ़ रोड पर राजौरी गार्डन की ओर जाने वाली लेन में हुई। पुलिस के अनुसार तड़के 3:26 बजे दुर्घटना और एक युवक के घायल होने की सूचना पीसीआर कॉल के माध्यम से तिलक नगर थाना पुलिस को मिली। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। घटनास्थल पर दोनों वाहन क्षतिग्रस्त हालत में मिले। हादसे में घायल युवक की पहचान रघुबीर नगर निवासी हेम शंकर (25) के रूप में हुई। पुलिस युवक को तुरंत दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वह ई-स्कूटी पर सवार था और एक निजी डिलीवरी कंपनी में कार्यरत था। पुलिस अधिकारी के अनुसार प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि पीछे से आ रही वर्ना कार ने ई-स्कूटी को टक्कर मारी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने मौके से कार चालक मोहित कुमार (27) को पकड़ा। वह नजफगढ़ का रहने वाला और एमसीडी में ठेकेदार है। दुर्घटना में शामिल कार को जब्त कर लिया गया है। मामले में संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि हादसे के समय वाहन की रफ्तार कितनी थी और चालक नशे में तो नहीं था।

कांग्रेस ने मोदी सरकार की विदेश नीति पर उठाए सवाल, अमेरिका के साथ समझौते की आलोचना की

लोकतंत्र की शानः नई दिल्ली। कांग्रेस ने भारत-अमेरिका व्यापार समझौते की एक बार फिर आलोचना करते हुए मोदी सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाया है। पार्टी ने सरकार से पूछा है कि अमेरिका के साथ समझौता करने से पहले वहां के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार क्यों नहीं किया? साथ ही यह भी पूछा कि अब क्या समझौते पर पुनर्विचार होगा? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने शनिवार को केंद्र सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार नहीं करने की वजह से हम एक जाल में फंस गए। इसके चलते हमने अमेरिका को बहुत ज्यादा रियायत दे दी। व्यापार समझौते की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि हमने भारत के कृषि क्षेत्र को अमेरिकी सामानों के लिए खोल दिया, 500 अरब डॉलर की खरीद और रूस से तेल नहीं खरीदने का वादा कर दिया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को यह बताना चाहिए कि आखिर किस कारण से किसके दबाव में भारत के राष्ट्रीय हितों और रणनीतिक सहायता के साथ समझौता किया गया। उन्होंने कहा कि अभी भारत सरकार के पास समय है कि वह अपनी नींद से जागे और एक उचित व्यापार समझौता करे। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर अमेरिका के दबाव के आगे झुकते हुए इस व्यापार समझौते पर दोबारा पुनर्विचार नहीं करेंगे। उल्लेखनीय है कि अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के दुनियाभर के देशों पर लगाए गए टैरिफ को रद्द कर दिया। कोर्ट के इस फैसले से भारत पर लगा 18 प्रतिशत पारस्परिक आयात शुल्क भी अब अवैध घोषित हो गया है।

पूर्ववर्ती सरकारों की नीति स्पष्ट न होने से विकास में पिछड़ी दिल्ली : कपिल मिश्रा

लोकतंत्र की शानः नई दिल्ली। दिल्ली के कला, संस्कृति एवं भाषा मंत्री कपिल मिश्रा ने शनिवार को करावल नगर में महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं के शिलान्यास एवं उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकारों में नीति और नियत स्पष्ट न होने से दिल्ली देश की राजधानी होने के बावजूद विकास की दौड़ में पिछड़ती गई। खासकर दिल्ली में यमुनापार क्षेत्रों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं पर भी काम नहीं हुआ। पिछले एक वर्षों में व्यवस्था पूरी तरह पटरी पर लौटी और आज पूरी दिल्ली सेवा, सुशासन और अंत्योदय की योजनाओं का स्वागत कर रही है। कपिल मिश्रा ने करावल नगर के दयालपुर गांव में बाबा दयाला चौक से सादतपुर एक्सटेंशन की गली नंबर 06 तक तथा करावल नगर गांव की मुख्य मार्केट से लाल बाग मंडी तक आरसीसी सड़क निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। इन सड़कों के निर्माण से स्थानीय नागरिकों को आवागमन में सुविधा मिलेगी तथा क्षेत्र की आधारभूत संरचना सुदृढ़ होगी। कपिल मिश्रा ने तुकमीरपुर नाले की पुलिया के नव-निर्माण कार्य का उद्घाटन भी किया। यह परियोजना जल निकासी व्यवस्था को बेहतर बनाएगी और बरसात के दौरान जलभराव की समस्या से राहत दिलाएगी। इसके साथ ही क्षेत्र की यातायात व्यवस्था और जल प्रबंधन में सुधार के लिए काली घटा रोड, पश्चिमी करावल नगर में नाले की पुलिया के नव-निर्माण कार्य का भी शुभारंभ किया। कपिल मिश्रा ने कहा कि पिछले एक वर्ष में करावल नगर में अनेक विकास कार्यों को धरातल पर उतारा गया है। पहले ही वर्ष 300 करोड़ रुपये से ज्यादा की विकास योजनाओं पर काम शुरू हुआ है।

दिल्ली पुलिस की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का लोगो, वेबसाइट और न्यूजलेटर लॉन्च

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। राजधानी में नशे के खिलाफ चल रहे अभियान को नई दिशा देते हुए दिल्ली पुलिस की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का आधिकारिक लोगो, वेबसाइट और न्यूज़लेटर लॉन्च किया गया। शुक्रवार को कनॉट प्लेस के इनर सर्कल स्थित दिल्ली पुलिस प्रदर्शनी हॉल के उद्घाटन समारोह में दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने इनका औपचारिक शुभारंभ किया। कार्यक्रम में दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलचा, विशेष आयुक्त (क्राइम) देवेश चंद्र श्रीवास्तव, अन्य वरिष्ठ अधिकारी, पुलिसकर्मी और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। इस पहल को नशे के खिलाफ जंग में एक महत्वपूर्ण और रणनीतिक कदम बताया गया। शनिवार को

पुलिस मुख्यालय से मिली जानकारी के अनुसार दिल्ली पुलिस द्वारा जारी एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्सका नया लोगो सतर्कता, ईमानदारी और मादक पदार्थों के खिलाफ अडिग संकल्प का प्रतीक है। लोगो में नशे के नेटवर्क के खिलाफ सशक्त और समन्वित कार्रवाई का संदेश निहित है। अधिकारियों के अनुसार, यह प्रतीक केवल एक चिन्ह नहीं, बल्कि नशामुक्त समाज के निर्माण की दिशा में मिशन आधारित कार्यप्रणाली का प्रतिनिधित्व करता है।

वेबसाइट से अपराध नियंत्रण में मिलेगी मजबूती:एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्सकी आधिकारिक वेबसाइट https://antf.delhipolice.gov.in को एक समर्पित डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया गया है। पुलिस के अनुसार, यह पोर्टल पारदर्शिता बढ़ाने, जनसंपर्क मजबूत करने और नागरिक सहभागिता को प्रोत्साहित करने में अहम भूमिका निभाएगा।

वेबसाइट के माध्यम से

नारकोटिक्स अपराधों और अपराधियों से संबंधित जानकारी साझा की जाएगी।

डाटा के आदान-प्रदान और ट्रैकिंग की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा।

एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स की पहल, जागरूकता अभियान और उपलब्धियों की जानकारी उपलब्ध होगी।

पुनर्वास केंद्रों और कानूनी प्रावधानों से संबंधित विस्तृत विवरण दिया जाएगा।

आम नागरिकों को सूचना देने और सहयोग करने का अवसर मिलेगा।

अधिकारियों का कहना है कि इससे नारकोटिक्स अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी में तेजी आएगी।

न्यूज़लेटर से मिलेगी नियमित जानकारी:इस अवसर पर एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का आधिकारिक न्यूज़लेटर भी जारी किया गया। यह संस्थागत संचार का माध्यम होगा, जिसमें— मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सफल अभियानों की जानकारी, महत्वपूर्ण गिरफ्तारियां और बरामदगी,जागरूकता कार्यक्रमों की रिपोर्ट, नीति संबंधी अपडेट और प्रमुख उपलब्धियां शामिल की जाएंगी। पुलिस का मानना है कि यह प्रकाशन विभाग की पारदर्शिता और जवाबदेही को और मजबूत करेगा।

तकनीक और जनभागीदारी पर विशेष जोर:दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया कि नशे की समस्या केवल कानून-व्यवस्था का मुद्दा नहीं, बल्कि सामाजिक चुनौती भी है। ऐसे में तकनीक के बेहतर उपयोग, अंतर-एजेंसी समन्वय और समाज की भागीदारी के जरिए इस पर प्रभावी नियंत्रण संभव है। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का उद्देश्य न केवल तस्करों और सप्लाई चेन पर सख्त कार्रवाई करना है, बल्कि युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों से बचाने के लिए जागरूकता और पुनर्वास पर भी समान रूप से ध्यान देना है।

भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी पर आधारित पहली कॉफी टेबल बुक का भव्य विमोचन

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। भारत रत्न श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी के जीवन, विचारों एवं राष्ट्र निर्माण में उनके अमूल्य योगदान पर आधारित पहली कॉफी टेबल बुक "Atal Bihari Vajpayee: The Eternal Statesman" का विमोचन आज डॉ. अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, जनपथ, नई दिल्ली में गरिमामय समारोह के बीच संपन्न हुआ। इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उपराष्ट्रपति श्री सी. पी. राधाकृष्णन, राजस्थान के राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े, बिहार के राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान, हरियाणा के राज्यपाल श्री प्रो. आशिम कुमार घोष तथा प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ श्री डॉ. एम. एम. जोशी उपस्थिति रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े, राज्यपाल श्री आरिफ मोहम्मद खान, राज्यपाल श्री प्रो. आशिम कुमार घोष एवं श्री डॉ. एम. एम. जोशी द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। इस

अवसर पर राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े ने अपने संबोधन में कहा कि मैं स्वयं को अत्यंत सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुझे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को निकट से देखने और उनके साथ समय बिताने का अवसर प्राप्त हुआ। अटल जी भारतीय राजनीति के ऐसे युगपुरुष थे, जिन्होंने अपने विचारों, आचरण और कार्यों से लोकतंत्र को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उल्लेखनीय है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री विजय गोयल कृत यह कॉफी टेबल बुक श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सार्वजनिक जीवन, सुशासन, कूटनीतिक दृष्टि एवं साहित्यिक व्यक्तित्व को चित्रों एवं दुर्लभ दस्तावेजों के माध्यम से प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करती है। यह पुस्तक आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणास्रोत सिद्ध होगी।

कांग्रेस की मांग- अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मद्देनजर भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर रोक लगाई जाए

लोकतंत्र की शान

नई दिल्लीः कांग्रेस ने मोदी सरकार से मांग की है कि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट द्वारा टैरिफ पर आए हालिया फैसले के बाद भारत-अमेरिका व्यापार समझौते को तुरंत रोका जाए। कांग्रेस कार्यालय में पत्रकार वार्ता करते हुए कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि अब अमेरिका के साथ हालिया व्यापार समझौते को स्थगित कर दिया जाना चाहिए और मांग की कि सरकार को भारतीय किसानों की रक्षा के लिए ट्रेड डील में बदलाव करना चाहिए, क्योंकि समझौते में ही बदलाव का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि अंतरिम समझौते के फ़्रेमवर्क में यह प्रावधान है कि अगर एक देश शर्तों में बदलाव करता है, तो दूसरा देश भी ऐसा कर सकता है। उन्होंने बताया कि रेसिप्रोकल टैरिफ को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत से अमान्य कर दिया है। फैसले में साफ कहा गया है कि ट्रंप को इस प्रकार के टैरिफ लगाने का अधिकार नहीं था, क्योंकि यह अमेरिकी कानून और संविधान के खिलाफ था। कांग्रेस महासचिव ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 02 फरवरी की रात भारत के साथ व्यापार समझौते की पहली घोषणा करते हुए कहा था कि यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आग्रह पर हो रहा है। उन्होंने सवाल उठाया कि आखिर ऐसी क्या जल्दबाजी थी कि प्रधानमंत्री ने सुनिश्चित किया कि उस रात ही समझौते की घोषणा हो जाए, जबकि सबको पता था कि ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ को वहां सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है और उस पर रोक लग सकती है। उन्होंने कहा कि 02 फरवरी को ही दिन में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की ओर से सदन में दिए भाषण से ध्यान भटकाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आनन-फानन में व्यापार समझौते के लिए ट्रंप से आग्रह किया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी द्वारा पूर्व आर्मी चीफ जनरल एमएम नरवणे की पुस्तक में किए गए खुलासों को लेकर सवाल उठाने से मोदी घबरा गए थे।

व्यापार, पर्यटन और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ाने के लिए भारत-नेपाल व्यापार महोत्सव का आयोजन

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। भारत-नेपाल व्यापार महोत्सव का दूसरा संस्करण शुक्रवार को राष्ट्रीय राजधाानी नई दिल्ली में शुरू हुआ, जिसका उद्देश्य दोनों पड़ोसी देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करना, पर्यटन को बढ़ावा देना और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करना है। "लोगों को जोड़ना, द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाना" के विषय पर आधारित भारत-नेपाल व्यापार महोत्सव का उद्घाटन भारत में नेपाल के राजदूत शंकर प्रसाद शर्मा और भारत के विदेश मंत्रालय (उत्तरी प्रभाग) के अतिरिक्त सचिव मुनु महावर ने किया। इस वर्ष के व्यापार

महोत्सव में दोनों देशों के 60 से अधिक विशेषज्ञों को शामिल किया गया है, जिसमें दस से अधिक उच्चस्तरीय सत्र और नीतिगत संवाद आयोजित किए जाएंगे। राजधानी नई दिल्ली के हौज खास स्थित पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री बिल्डिंग में 20 से 22 फरवरी तक आयोजित इस महोत्सव का आयोजन भारत में नेपाली उद्यमियों के संगठन एवरेस्ट चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा नेपाल दूतावास, नेपाल पर्यटन बोर्ड और व्यापार एवं निर्यात संवर्धन केंद्र के सहयोग से किया गया है। भारत-नेपाल व्यापार महोत्सव के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए भारत में नेपाल के राजदूत शंकर प्रसाद शर्मा ने भारत में नेपाल के पर्यटन प्रचार-प्रसार को और अधिक प्रभावी बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि नेपाल के पर्यटन स्थलों का पर्याप्त प्रचार भारत में नहीं हो पाया है तथा रामग्राम जैसे ऐतिहासिक स्थलों के प्रभावी प्रमोशन की आवश्यकता है। इस महोत्सव के मुख्य आयोजक एवरेस्ट चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष युवराज बराल ने कहा कि नेपाल–भारत संबंध हजारों वर्षों से 'रोटी–बेटी' के आत्मीय रिश्ते पर आधारित हैं। व्यापार, कला-संस्कृति और फिल्म प्रदर्शन के माध्यम से संबंधों को और मजबूत करने के उद्देश्य से इस महोत्सव का आयोजन किया गया है। इस वर्ष भारत-नेपाल व्यापार महोत्सव में जलविद्युत एवं ऊर्जा साझेदारी, सीमापार व्यापार और कनेक्टिविटी, रामायण और बौद्ध सर्किट के जरिए पर्यटन एकीकरण, बैंकिंग, फिनटेक, डिजिटल अर्थव्यवस्था, मीडिया एवं सांस्कृतिक कूटनीति, युवा सहभागिता, शिक्षा, नवाचार तथा स्टार्टअप इकोसिस्टम जैसे विषयों पर 10 से अधिक उच्चस्तरीय सत्र और नीतिगत संवाद आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें 50 से अधिक विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं। पहले दिन नेपाली फिल्म गोरखा वॉरियर की स्क्रीनिंग की गई, जिसका निर्देशन मिलन चाम्लिंग राय ने किया है। इसके बाद "नेपाल–भारत संबंधों में सॉफ्ट पावर के रूप में सिनेमा की भूमिका" विषय पर पैनल चर्चा आयोजित की गई। महोत्सव में सांस्कृतिक कार्यक्रम, फिल्म प्रदर्शन, पारंपरिक कला और प्रामाणिक नेपाली व्यंजन भी प्रस्तुत किए गए हैं। 60 से अधिक स्टॉल लगाए गए हैं और 25 हजार से अधिक आगंतुकों की भागीदारी का अनुमान है।

रालोमो की राष्ट्रीय युवा इकाई ने मनाया पार्टी का तीसरा स्थापना दिवस

सचिन राज बने दिल्ली प्रदेश ईकाई के युवा अध्यक्ष

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली । राष्ट्रीय लोक मोर्चा (आरएलएम) ने शनिवार को अपना तीसरा स्थापना दिवस बड़े उत्साह और जोश के साथ मनाया। पार्टी के संस्थापक एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष, राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने पटना स्थित कैंप कार्यालय में केक काटकर इसकी शुरुआत की। वहीं दिल्ली में पार्टी कि राष्ट्रीय युवा इकाई और दिल्ली प्रदेश ने पूरे धूमधाम से पार्टी का तीसरा वर्षगाँठ मनाया। रालोमो के 3 वर्ष पूरा होने पर पूरे देश में "सघन सदस्यता अभियान" का शुभारंभ किया गया जिसमें दिल्ली प्रदेश के युवा इकाई में सैकड़ों लोगों ने पार्टी की सदस्यता ली। इस अवसर पर राष्ट्रीय युवा लोक मोर्चा ने दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष पद पर जेएनयू से पढे शहीद भगत सिंह यूथ बिग्रेड के राष्ट्रीय

अध्यक्ष सचिन राज को नियुक्त किया गया। नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष ने अपनी दिल्ली प्रदेश इकाई का गठन भी किया। जिसमें युवा दिल्ली प्रदेश के प्रधान महासचिव ललित कुमार, उपाध्यक्ष सह प्रवक्ता ललित डबास, उपाध्यक्ष मोहमद अजमल, महासचिव अंकित यादव, महासचिव मुकेश कुमार को बनाया गया। इस अवसर पर युवा राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू सिंह, प्रधान महासचिव अमित किशोर, उपाध्यक्ष रोहित रंजन, सचिव रोशन कुशवाहा और पार्टी के राष्ट्रीय मीडिया सलाहकार प्रमोद कुमार सुमन, डीके पांडेय राज उपस्थित रहे। गौरतलब है कि यह अभियान आज से शुरू होकर बिहार के सभी जिलों, प्रखंडों और गांवों तक चलाया जाएगा, जिसमें दलित, पिछड़े वर्ग, महिलाओं और युवाओं को विशेष भागीदारी देने का लक्ष्य रखा गया है। उपेंद्र कुशवाहा ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा "राष्ट्रीय लोक मोर्चा की विचारधारा सामाजिक न्याय, लोकतंत्र और विकसित बिहार के सपने पर आधारित है। कार्यकर्ताओं की मेहनत और समर्पण ही हमारी असली ताकत है। आज हमारा संकल्प है कि बिहार की हर जनता तक पहुंचकर उनके हितों के लिए मजबूत संघर्ष करेंगे।" बता दें कि आरएलएम की स्थापना 20 फरवरी 2023 को राष्ट्रीय लोक जनता दल के नाम से हुई थी, जिसे बाद में चुनाव आयोग के दिशानिर्देशों के अनुसार राष्ट्रीय लोक मोर्चा नाम दिया गया।

खेल का मैदान सार्वजनिक जीवन की प्रमुख पाठशाला : विजेंद्र गुप्ता

लोकतंत्र की शान

नई दिल्ली। 'खेल में जीत टीम की होती है लेकिन राजनीति में सच्ची जीत जनता की होनी चाहिए' यह विचार दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने शनिवार को पुणे में तीन दिवसीय 15वें भारतीय छात्र संसद के उद्घाटन भाषण के दौरान व्यक्त किए। "स्टेडियम से स्टेट्समैनशिप तकः राजनीति खेलों से क्या सीख सकती है?" विषय पर बोलते हुए, गुप्ता ने इस बात पर जोर दिया कि खेल का मैदान सार्वजनिक जीवन के लिए एक प्रमुख पाठशाला है। उन्होंने कहा कि जिस तरह एक एथलीट तिरंगे का मान बढ़ाने के लिए पसीना बहाता है, उसी तरह एक जन प्रतिनिधि को निःस्वार्थ भाव से काम करना चाहिए ताकि राष्ट्र की गरिमा अडिग रहे। विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि खेल की भावना आधुनिक राजनीति को तीन स्तंभों के माध्यम से 'संजीवनी' प्रदान करती हैः अनुशासन, टीम वर्क और खेल भावना। उन्होंने कहा कि एक स्वस्थ लोकतंत्र में संविधान ही अंतिम 'रूलबुक' है, ठीक वैसे ही जैसे खेल के नियम होते हैं। उन्होंने

युवा नेताओं से आग्रह किया कि वे राजनीतिक विरोधियों को "शत्रु" नहीं बल्कि "प्रतिस्पर्धी" के रूप में देखें। उन्होंने जोर देकर कहा कि हार को शालीनता से स्वीकार करना और विजेता का सम्मान करना एक प्रगतिशील समाज की आत्मा है। उन्होंने कहा कि एक कप्तान की परीक्षा संकट में होती है; उसी तरह, एक नेता की असली पहचान तब होती है जब देश किसी चुनौती का सामना कर रहा हो। भविष्य के रोडमैप पर प्रकाश डालते हुए विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि विकसित भारत @2047 का लक्ष्य तभी प्राप्त किया जा सकता है जब युवा अपनी ईमानदारी और फोकस को सत्ता के गलियारों में लाएं। उन्होंने जोर देकर कहा कि "विकसित भारत" के लिए एक ऐसी राजनीतिक संस्कृति की आवश्यकता है जहां योग्यता ही एकमात्र पैमाना हो और जहां "जोड़-तोड़ " की जगह "समर्पण" हो। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि धर्म, जाति और क्षेत्र की बाधाओं को तोड़कर एक राष्ट्रीय टीम के रूप में काम करने से भारत हर क्षेत्र में विश्व नेता के रूप में वैश्विक मंच पर खड़ा होने के लिए तैयार है। विजेंद्र गुप्ता ने छात्रों के समूह से आग्रह किया कि वे असफलताओं को अपने जीवन में "पूर्ण विराम" नहीं बल्कि "अल्पविराम" के समान मानें, जो तकनीक को सुधारने और मजबूती से वापसी करने का एक अवसर है। उन्होंने भारतीय छात्र संसद की सराहना करते हुए कहा कि यह एक ऐसा मंच प्रदान करता है जो चरित्र और अखंडता का निर्माण करता है, जो एक मजबूत राष्ट्र की पहचान है। उन्होंने दोहराया कि जब नेता अपने लिए खेलना बंद कर देंगे और "राष्ट्रीय टीम" के लिए खेलना शुरू करेंगे, तो वैश्विक चैंपियन बनने की भारत की यात्रा निश्चित पूरी हो जाएगी।

संक्षिप्त समाचार

एक शहर, अनगिनत हमलेः नजीबाबाद में आवारा कुत्तों की दहशत, पूर्व में रहे थाना प्रभारी तक नहीं बचे

लोकतंत्र की शान : (खिजर अहमद) नजीबाबादः नजीबाबाद शहर में आवारा कुत्तों का आतंक दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है। पिछले दो वर्षों में लगभग 100 के करीब लोग इन आवारा कुत्तों के हमलों का शिकार हो चुके हैं, जिसमें बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग शामिल हैं। हाल की घटनाओं ने स्थिति को और गंभीर बना दिया है, जहां लोग घर से बाहर निकलने से भी डरने लगे हैं। बच्चे स्कूल जाने या खेलने में हिचकिचाते हैं, जबकि बुजुर्गों पर हमले आम हो गए हैं। ताजा मामला मोहल्ला हवेली तला का है, जहां निवासी फरीद अहमद खान पर आवारा कुत्तों के झुंड ने जानलेवा हमला कर दिया। कुत्तों ने उनके पैरों को बुरी तरह फाड़ दिया और सिर व हाथ पर भी गंभीर चोटें पहुंचाईं। घटना घर के बाहर हुई, जब फरीद अहमद बाहर थे। शोर सुनकर पड़ोसियों ने हस्तक्षेप किया और कुत्तों को भगाया। घायल बुजुर्ग को तुरंत सरकारी अस्पताल समीपुर ले जाया गया, जहां उनका प्राथमिक उपचार चल रहा है। इस घटना की सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिससे इलाके में आक्रोश और दहशत का माहौल है। इससे पहले भी कई ऐसी घ

माहे रामजान के पहले जुमे की नमाजः मस्जिदों में उमड़ी भारी भीड़, पूरे मुल्क में आमनो आमान के लिये दुआएं

लोकतंत्र की शान : (खिजर अहमद) नजीबाबाद : नजीबाबाद शहर में माहे रामजान के पहले जुमे की नमाज बड़ी शांति, अकीदत और उत्साह के साथ अदा की गई। रामजान का यह पहला जुम्मा 'अशरा-ए-रहमत' के रूप में जाना जाता है, जिसमें अल्लाह की रहमत, मगफिरत और बरकतों की दुआएं मांगी जाती हैं। शहर से लेकर आसपास के गांवों तक की मस्जिदों में नमाजियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी, जिससे पूरा इलाका इबादत के रंग में रंग गया। सुबह से ही मस्जिदों की सफाई और सजावट का काम जोर-शोर से चला। अतिरिक्त सफेद चादरें बिछाई गईं, रास्तों पर चूना डाला गया और नमाजियों के लिए बेहतर इंतजाम किए गए। जुमे की नमाज से पहले इमामों ने खुतबे में रमजान की फजीलत बताई, रोजा रखने, जकात देने, गरीबों की मदद करने और गुनाहों की माफी मांगने का आह्वान किया। नमाज के दौरान मुल्क की अमन-ओ-सलामती, तरक्की और भाईचारे के लिए खास दुआएं मांगी गईं। शहर की प्रमुख मस्जिदों जैसे जामा मस्जिद पटानपुरा, नवाब नजीबुद्दौला के मकबरे वाली मस्जिद, काँटों वाली मस्जिद शफ़आत खा वाली मस्जिद पालोमेल कॉलोनी की खलीलुल्लाह ममें अदा की गई

स्टेडियम के लिए 912 लाख रूपये स्वीकृत

लोकतंत्र की शान : बाँदा : सदर विधायक के प्रयासो से सरदार बल्लभ भाई पटेल स्टेडियम के लिए 912 लाख रूपये का बजट स्वीकृत हुआ है। जल्द स्टेडियम का कायाकल्प होगा। सदर विधायक प्रकाश द्विवेदी के अथक प्रयासो से बदलते एवं आधुनिक बांदा की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम के अन्तर्गत उप्र शासन द्वारा सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम में विभिन्न विकास कार्यों के लिए 912 लाख रूपये की धनराशि स्वीकृत की गयी है तथा इसके सापेक्ष शासन द्वारा 237 लाख रूपये की धनराशि अवमुक्त की गयी है। स्वीकृत परियोजना के अन्तर्गत प्रशासनिक भवन का निर्माण, बाउंड्री वॉल का निर्माण, कैंपस का विद्युतीकरण, स्टेडियम मैदान में मिट्टी का भराव, स्विमिंग पूल का जीर्णोद्धार, बास्केटबॉल कोर्ट का नवनिर्माण, सिंथेटिक पाथवे का निर्माण आदि का कार्य कराया जायेगा। सदर विधायक द्वारा बताया गया कि इन परियोजनाओं के पूर्ण होने से जिले के युवा खिलाड़ियों को आधुनिक सुविधाएं प्राप्त होंगी, जिससे उनकी प्रतिभा को निखारने और प्रदेश व देश स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने में सहायता मिलेगी। यह पहल बांदा को एक महत्वपूर्ण खेल केंद्र के रूप में स्थापित करने की दिशा में मील का पत्थर सिद्ध होगी। सदर विधायक जी ने इन समस्त विकास कार्यों के लिए प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं खेलकूद मंत्री गिरीश यादव का हृदय से आभार एवं धन्यवाद व्यक्त किया जाता है। उनके कुशल नेतृत्व एवं दूरदर्शी सोच के परिणामस्वरूप आज बांदा खेल जगत में एक नई पहचान बना रहा है।

कुणाल अरोड़ा ने गोल्ड कोस्ट में पैरा टेबल टेनिस चैम्पियनशिप में जीता कांस्य पदक

लोकतंत्र की शान : मुरादाबाद।। मुरादाबाद शहर निवासी कुणाल अरोड़ा ने गोल्ड कोस्ट आस्ट्रेलिया में आईटीटीएफ वर्ल्ड पैरा फ्यूचर गोल्ड कोस्ट-2026 चैम्पियनशिप में काँस्य पदक जीतकर पीतलनगरी का नाम एक बार और चमका दिया है। कुणाल ने हमेशा की तरह अपनी जीत का श्रेय अपने माता पिता यशपाल अरोड़ा, सोनिया अरोड़ा एवं अपने कोच को दिया।

भारतीय किसान संघ ने विभिन्न मांगों को लेकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा

लोक तंत्र की शान प्रवीण अग्रवाल जिला प्रभारी अमरोहा

हसनपुर : शनिवार को भारतीय किसान संघ ने विभिन्न मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार के नाम संबोधित एक ज्ञापन उप जिला अधिकारी हसनपुर हिमांशु उपाध्याय को सोपा, इस मौके पर भारतीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष चंद्र प्रकाश शर्मा ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए करने की घोषणा की है लेकिन बैंक किसानों को इसका लाभ नहीं दे रहे हैं वहीं उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले दो वर्षों से 3% अनुदान राशि भी वापस नहीं की गई है, वहीं पेयजल की समस्या पर रोष व्यक्त किया गया, वक्ताओं ने कहा कि पानी की टंकियां सफेद हाथी बनी हुई है और पाइपलाइन चालू न होने के कारण ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल नहीं मिल पा रहा है साथ ही आपूर्ति विभाग पर गंभीर आरोप लगाते हुए संघ ने कहा कि पात्र राशन कार्ड को काटकर उन्हें दोबारा चालू करने के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है इसके अतिरिक्त ताहारपुर बिजली घर से सुबह श्याम होने वाली अघोषित बिजली कटौती से बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है किसान संघ ने हसनपुर से ग्राम भदौरा मार्ग की जर्जर स्थिति को सुधारने की मांग की साथ ही राजस्व विभाग की लापरवाही के चलते लंबित भूमि विवादों को शीघ्र निस्तारण करने की भी मांग रखी, इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष धर्मपाल सिंह चौहान, ओमवीर सिंह, जिला जैविक प्रमुख हरिप्रकाश राणा, ओमवीर सिंह, महिपाल सिंह, धर्मेंद्र, जबर सिंह, उमेश चंद्र, राजीव सिंह, सतीश कुमार, रोहतास सिंह, जयप्रकाश सिंह, पूर्व जिला अध्यक्ष कृष्ण कुमार शर्मा आदि सहित भारी संख्या में किसान संघ के कार्यकर्ता मौजूद रहे, वहीं संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि समस्याओं को जल्द समाधान नहीं हुआ तो किसान संघ बड़े आंदोलन को बाध्य होगा।

गुयाना के उपराष्ट्रपति ने किया रामलला का दर्शन-पूजन

परिसर में बने अन्य मंदिरों में भी जाकर शीश झुकाया डॉ. भरत जगदेव ने

लोक तंत्र की शान

अयोध्या : गुयाना के उपराष्ट्रपति डॉ. भरत जगदेव शनिवार को रामनगरी पहुंचे। उन्होंने अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ रामलला का दर्शन-पूजन किया। उन्होंने परिसर में बने अन्य मंदिरों में भी जाकर शीश झुकाया। उपराष्ट्रपति लगभग एक घंटे तक मंदिर परिसर में रहे। इस दौरान उन्होंने निर्माण कार्यों का जायजा भी लिया। भव्य-नव्य अयोध्या देखकर वे प्रफुल्लित हो उठे। इसके पहले शनिवार सुबह वे प्रतिनिधिमंडल के साथ निजी विमान से वाल्मीकि एयरपोर्ट पहुंचे। शंखनाद व कलाकारों के भावपूर्ण नृत्य के बीच एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। वहां खाद्य व रसद मंत्री सतीश चंद्र शर्मा, जिला पंचायत अध्यक्ष रोली सिंह, महापौर महंत गिरीशपति त्रिपाठी, मिल्कीपुर के विधायक चंद्रभानु पासवान, कमिश्नर राजेश कुमार, डीआईजी सोमेन वर्मा, डीएम निखिल टीकाराम फुंडे ने उनकी आगवानी की। एसपी सिटी चक्रपाणि त्रिपाठी ने बताया कि इस दौरान सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए।

अन्नदाता किसानों के साथ खड़ी रहेगी डबल इंजन सरकारः मुख्यमंत्री

लोक तंत्र की शान

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (खरीफ-2025) के अंतर्गत 2.51 लाख किसानों को 285 करोड़ रुपये की क्षतिपूर्ति राशि का वितरण किया। उन्होंने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के 3500 लाभार्थी परिवारों को भी 175 करोड़ रुपये की सहायता राशि प्रदान की। मुख्यमंत्री ने बागपत, शामली, कासगंज, भदोही में उप कृषि निदेशक कार्यालय व मृदा परीक्षण प्रयोगशालाओं, राजकीय भूमि संरक्षण केंद्र मऊरानीपुर झांसी में 50 शैय्या के छात्रावास भवन तथा लखनऊ में स्मार्ट कृषि ब्यूरो स्टूडियो इकाई का शिलान्यास भी किया। सीएम योगी ने होली की शुभकामनाएं देते हुए किसानों को आश्वस्त किया कि डबल इंजन सरकार मजबूती के साथ उनके साथ खड़ी रहेगी। उन्होंने विश्वास जताया कि अन्नदाता किसान उन्नत खेती के माध्यम से प्रदेश की समृद्धि में योगदान देते रहेंगे।

460 करोड़ रुपये किसानों के खाते में पहुंचे, बिचौलियों की भूमिका समाप्त –सीएम योगी ने कहा कि कल ही उत्तर प्रदेश सरकार का 2026-27 का बजट पारित हुआ है। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से बजट के माध्यम से प्रदेश के युवाओं, महिलाओं, किसानों, गरीबों के लिए ढेर सारी योजनाएं पास कराई गई हैं। जब बजट होता है तो लाभार्थियों के अकाउंट में सीधे पैसा जाता है और उन्हें लाभ प्राप्त होता है। आज एक बटन दबाते ही 460 करोड़ रुपये किसानों के खाते में पहुंच रहे हैं, बिचौलियों की भूमिका समाप्त हो गई। लखनऊ समेत प्रदेश के सभी जनपदों में लाभार्थी परिवारों को इन योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है।

उत्तर प्रदेश को मिलेगी बड़ी सौगात, ऐतिहासिक हो प्रधानमंत्री का कार्यक्रमः मुख्यमंत्री

लोक तंत्र की शान

लखनऊः मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शनिवार दोपहर मेरठ पहुंचे। उन्होंने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रमों की तैयारियों का जायजा लिया और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने आयोजन स्थल, रेलवे स्टेशन आदि का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि नमो भारत रैपिड रेल के विस्तार और मेरठ मेट्रो का शुभारंभ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के शहरी और औद्योगिक विकास में मील का पत्थर सिद्ध होगा। यह परियोजना न केवल तेज, सुरक्षित और आधुनिक परिवहन उपलब्ध कराएगी, बल्कि दिल्ली-एनसीआर और पश्चिमी यूपी के बीच आर्थिक, शैक्षणिक और औद्योगिक गतिविधियों को नई गति देगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कार्यक्रम में एक लाख से अधिक लोगों की सहभागिता संभावित है। इसकी महत्ता व बड़ी जनभागीदारी को देखते हुए सभी व्यवस्थाएं सुचारु, सुरक्षित और पूर्णतः व्यवस्थित हों। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम स्थल पर पार्किंग स्थल, यातायात प्रबंधन को प्रभावी बनाए रखने पर जोर दिया। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम स्थल व आसपास सीसीटीवी कैमरों की पर्याप्त व्यवस्था, बहुस्तरीय और समन्वित सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि सुरक्षा और सुगमता में किसी भी स्तर पर शिथिलता स्वीकार्य नहीं होगी।

12,930 करोड़ लागत की कई परियोजनाओं का उपहार देंगे प्रधानमंत्री –रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12,930 करोड़ से निर्मित दिल्ली में सराय काले खां से न्यू अशोक नगर तक (पांच किमी.), मेरठ साउथ से मोदीपुरम तक नमो भारत रैपिड रेल और मेट्रो रेल सेवा राष्ट्र को समर्पित करेंगे। पीएम मोदी मेरठ के मोहिउद्दीनपुर रैली ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में यह उपहार देंगे। प्रधानमंत्री शताब्दी नगर नमो भारत स्टेशन पर मेरठ मेट्रो और नमो भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। यहां से वे मेरठ साउथ स्टेशन तक मेट्रो का सफर करेंगे। प्रधानमंत्री मेरठ में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री के निरीक्षण के दौरान प्रदेश सरकार के राज्यमंत्री दिनेश खटिक, मेरठ के सांसद अरुण गोविल, महापौर हरिकांत अहलूवालिया, विधान परिषद सदस्य अश्विनी त्यागी, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिसौदिया समेत स्थानीय जनपद-पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे।

शिक्षक भवन पर ब्लाकों के अध्यक्ष - मंत्रियों की बैठक टी.ई.टी अनिवार्यता के विरोध में

लोक तंत्र की शान, देवेंद्र सिंह

सीतापुरः उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रांतीय उपाध्यक्ष - जिलाध्यक्ष रवींद्र दीक्षित ने सभी ब्लाकों के अध्यक्ष- मंत्रियों की बैठक बिजवार स्थित शिक्षक भवन पर बुलाई। बैठक में टी.ई.टी. अनिवार्यता के विरोध में प्रदेश से आये कार्यक्रम की जानकारी रवींद्र दीक्षित ने बैठक में आये सभी ब्लाकों के अध्यक्ष - मंत्रियों को दी। दिनांक 22 फरवरी 2026 को अपराह्न 2:00 बजे से 4:00 बजे तक एक साथ ट्विटर पर हैशटैग #अभियान संचालित किया जाएगा। दिनांक 23 फरवरी 2026 से 25 फरवरी 2026 तक विरोध स्वरुप सभी शिक्षक काली पट्टी बांधकर विद्यालय में शिक्षण कार्य करेंगे। दिनांक 26 फरवरी 2026 को अपराह्न 11:00 बजे से 2:00 बजे तक संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी के कार्यालय पर धरना देकर, बीएसए कार्यालय से दोपहर 2 बजे जिला अधिकारी कार्यालय तक पैदल मार्च करते हुए जिला अधिकारी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार को ज्ञापन प्रेषित किया जाएगा। मार्च के तीसरे सप्ताह में नई दिल्ली के रामलीला मैदान में महारैली करके भारत सरकार को ज्ञापन दिया जाएगा। रवींद्र दीक्षित ने सभी ब्लाकों के अध्यक्ष - मंत्री से वार्ता कर के सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया गया कि 26 फरवरी 2026 की सभी शिक्षक एक दिन का आकस्मिक अवकाश लेकर धरने में आएंगे। जिला मंत्री हंसराज वर्मा ने धरने में अधिक से अधिक संख्या में शिक्षको को धरने में उपस्थित रहे इसकी रूपरेखा तैयार करने के लिए सभी ब्लॉकों के अध्यक्ष मंत्रियों से कहा। हँसराज ने कहा कि प्रत्येक शिक्षक को धरने की जानकारी अपने ब्लॉक के पदाधिकारी या सोशल मीडिया के द्वारा पहुंचाई जाए। इस बैठक में नवीन श्रीवास्तव, रत्नेश मिश्रा, दिनेश मिश्रा, पवन सिंह, गिरजेश अवस्थी, अश्वनी सिंह, अजय सिंह, ज्ञान प्रकाश, शिवसागर वर्मा, सिद्धार्थ पटेल अजीत सिंह, उमेश यादव, नसीर अहमद, मदन लाल गौतम, महेश पाल, विनय गिहार, प्रदीप, शिवेन्द्र, प्रदीप मिश्रा, विवेक पण्डित आदि उपस्थित रहे।

विश्व हिंदू महासंघ भारत का दो दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन

लोक तंत्र की शान प्रवीण अग्रवाल जिला प्रभारी अमरोहा

अमरोहाः शनिवार को विश्व हिंदू महासंघ भारत का दो दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन अमरोहा के सेम्फोर्ड स्कूल में प्रथम दिवस संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ यज्ञ हवन और सरस्वती वंदना से हुआ। अधिवेशन में संस्थापक ब्रह्मलीन महंत अवैद्यनाथ जी महाराज को भारत रत्न देने की मांग पर विचार किया गया। अधिवेशन में प्रदेश महामंत्री भानु प्रताप सिंह, प्रदेश अध्यक्ष राकेश कुमार सिंह, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री कौशल पालीवाल, राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष अरुण सिंह साधु, और राष्ट्रीय संरक्षक देवेंद्र प्रताप तोमर ने भाग लिया। मातृशक्ति प्रकोष्ठ की ओर से अध्यक्ष श्रीमती निशा चौहान, प्रदेश महामंत्री तुलिका, प्रदेश मंत्री प्रीति प्रिया, और प्रदेश उपाध्यक्ष सीमा अग्रवाल ने सक्रिय सहभागिता निभाई। गौरक्षा प्रकोष्ठ के प्रदेश प्रभारी संजय और प्रदेश युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष डॉ आकाशवीर भी उपस्थित रहे। अधिवेशन में "राष्ट्र प्रथम" की भावना को मजबूत करने पर जोर दिया गया।

संपूर्ण समाधान दिवस में विधायक ने कृषक दुर्घटना के चेक वितरित किए

लोक तंत्र की शान प्रवीण अग्रवाल जिला प्रभारी अमरोहा

हसनपुरः शनिवार को सरकार की मंशा अनुसार लगाए जा रहे हैं संपूर्ण समाधान दिवस में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना बीमा योजना के तहत विधायक महेंद्र सिंह खड़कवंशी ने 45 लाख रुपए के चेक वितरित किए, जिसमें 9 में से मौके पर पांच मृतक आश्रितों को पांच पांच लाख के चेक दिए गए, इस मौके पर विधायक महेंद्र सिंह खड़कवंशी के साथ अपर जिलाधिकारी धिरेंद्र प्रताप सिंह, उप जिलाधिकारी हिमांशु उपाध्याय तथा तहसीलदार परमानंद श्रीवास्तव एवं पुलिस क्षेत्राधिकारी पंकज कुमार त्यागी भी मौजूद रहे, वहीं मृतक आश्रितों में ओगपुरा निवासी नौसिंह, खुरतीया निवासी रामनिवास, चकुनी निवासी अमिचंद, पिपलोती खुर्द निवासी शिवम सैनी, बस्काकला निवासी संतराम, तसिया निवासी नेपाल सिंह, फूलपुर बिझलपुर निवासी विनोद, रुद्रपुर निवासी जसपाल सिंह और शहबाजपुर गुर्जर निवासी रणवीर शामिल है, वही संपूर्ण समाधान दिवस में अपर जिलाधिकारी धिरेंद्र प्रताप सिंह ने फरियादियों की फरियाद को गंभीरतापूर्वक सुना मौके पर कुल 16 शिकायत दर्ज की गई जिसमें से 2 का मौके पर निस्तारण कर दिया गया, बाकी शिकायतों के निस्तारण के लिए संबंधित विभागों को गुणवत्ता पूर्वक समाधान के लिए निर्देश दिए गए, प्राप्त शिकतों में राजस्व विभाग की 6, पुलिस विभाग की 4, विकास विभाग की 2, पूर्ति विभाग की 1, और अन्य 3 शिकायते शामिल रही, इस दौरान वन रेंजर नरेश कुमार, अधिशासी अधिकारी विजयपाल सिंह, एसडीओ मिथिलेश यादव आदि सहित संबंधित हल्का लेखपाल एवं थानों के थाना अध्यक्ष मौजूद रहे।

महाविद्यालय चिरंजीलाल कॉलेज ऑफ़ एजुकेशन डगरोली में सात दिवसीय शिविर का हुआ शुभारंभ

लोक तंत्र की शान प्रवीण अग्रवाल जिला प्रभारी अमरोहा

हसनपुरः शनिवार को महाविद्यालय चिरंजीलाल कॉलेज ऑफ़ एजुकेशन डगरोली में राष्ट्रीय सेवा योजना की इकाई द्वारा सात दिवसीय विशेष शिविर के प्रथम दिन का उद्घाटन महाविद्यालय निदेशक पुनीत अग्रवाल ने गांव बोनावाली डगरोली में मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया। उन्होंने सभी स्वयंसेवियों को राष्ट्रीय सेवा योजना के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए कहां की हमारे विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से सरकार ने अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए , शिक्षा,स्वास्थ्य, रोजगार,कृषि, विपणन,तकनीक, उद्योग, खेलकूद आदि क्षेत्रों में भरपूर अवसर प्रदान किए हैं। व्यावहारिक रूप देने के लिए बहुमुखी राष्ट्रीय सेवा योजना का संचालन किया जाता है। जिसके माध्यम से महाविद्यालय स्तर पर सात दिवसीय विशेष शिविरों का आयोजन कर ग्राम एवं मोहल्ले स्तर पर विभिन्न प्रकार के स्वच्छता, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, विधिक जागरूकता, आपदा प्रबंधन जैसे कार्यक्रम द्वारा स्वयंसेवकों के साथ-साथ आम जनता को भी जागरूक किया जाता है इसमें विशेष स्वयंसेवियों को विश्वविद्यालय द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान किया जाता है इन विशेष स्वयंसेवियों को प्रमाण पत्र के आधार पर सरकारी सेवाओं में अधिभार मिलता है, वही कार्यक्रम अधिकारी राजकुमार ने स्वच्छता विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करते हुए कहा की स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत स्वच्छता सामुदायिक भागीदारी और सतत जीवन शैली का उत्सव है। इस अवसर पर डॉ राकेश आर्य ,मनोज कुमार शर्मा, विनोद गुप्ता ,अतुल शर्मा ,लोकेश कुमार ,जूही त्यागी, कोशिंदर कुमार ,शिवानी , नीरज ,राखी, सरस्वती ,मोनिका ,पूजा अनीता ,शीतल ,अनुराधा सहित सभी स्वयं सेवक उपस्थित रहे।

संक्षिप्त समाचार

खेसारी बोले, मैथिली ठाकुर को ज्ञान-अनुभव की कमी, शब्दों का चयन सोच-समझकर करना चाहिए

लोकतंत्र की शान : पटना। भोजपुरी इंडस्ट्री के चर्चित अभिनेता-गायक खेसारी लाल यादव ने गायिका मैथिली ठाकुर की ओर से लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव को 'दुर्योधन' और 'धृतराष्ट्र' कहे जाने के पर तीखी टिप्पणी की है। खेसारी ने कहा कि कम उम्र में यदि बड़ी उपलब्धि मिल जाती है तो कई बार व्यक्ति संतुलन खो देता है। ज्ञान-अनुभव की कमी में लोग ऐसे शब्दों का प्रयोग कर बैठते हैं। राजनीति में आने का मतलब यह नहीं है कि इंसानियत खत्म हो जाए। उन्होंने साफ कहा कि राजनीति में शालीनता और मर्यादा बेहद जरूरी है। तेजस्वी बड़े भाई के समान हैं और लालू जी पिता समान। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल उचित नहीं है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि वह किसी कलाकार पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करना चाहते। मैं कलाकार हूं, इसलिए मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन भाषा का चयन सोच-समझकर होना चाहिए। भोजपुरी गायक और भाजपा नेता मनोज तिवारी की ओर से हाल ही में निकाले गए एक एल्बम में खेसारी पर तंज कसने की चर्चा भी तेज है। इस पर उन्होंने कहा कि वह जहां हैं, उनके लिए बेहतर है और मैं जहां हूं, मेरे लिए बेहतर है। उनका मेरे साथ व्यक्तिगत रिश्ता है। मैं उन्हें बड़े भाई के तौर पर सम्मान देता हूं और जीवन भर देता रहूंगा। खेसारी ने कहा कि राजनेता अक्सर राजनीतिक भाषा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन दुनिया भर की बातें और इधर-उधर की चर्चा से बिहार का भला नहीं हो सकता। भोजपुरी अभिनेत्री काजल राघवानी ने हाल ही में कहा था कि वह फिर से खेसारी के साथ काम करना चाहती हूं। इस पर खेसारी ने कहा कि उनकी अपनी विचारधारा हो सकती है। मैं इतना बड़ा नहीं हूं कि किसी कलाकार को मना कर दूं। अगर अच्छा काम होगा तो जरूर साथ काम करेंगे।

सोशल मीडिया पर वायरल पटना जू का कुपोषित व्हाइट टाइगर लोगों का फूटा गुस्सा

लोकतंत्र की शान : पटना। इन दिनों सोशल मीडिया में व्हाइट टाइगर का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो काफी कमजोर दिख रहा है। उसकी हड्डियां निकल आई हैं। जिससे यह वीडियो बनाया है, वह आरोप लगा रहा है कि पटना जू प्रशासन द्वारा सही तरीके से व्हाइट टाइगर को खाना नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते उसकी ऐसी हालत हुई है। इस वीडियो को लेकर यह दावा किया जा रहा है कि यह पटना जू का है। सफेद बाघ की हालत ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो पर लोगों ने प्रशासन से तत्काल बेटरनरी जांच और बेहतर देखभाल की मांग की है। दूसरी ओर पटना जू प्रशासन का कहना है कि यह वायरल वीडियो पटना जू का है या नहीं इसकी जांच करवाई जा रही है। हम लोग अपने सभी जानवरों का खास तौर पर देखभाल करते हैं। उनकी समय-समय पर मेडिकल जांच भी होती है। बाघों को नियमित तौर पर खाना दिया जाता है। अभी पटना जू में 7 बाघ हैं, जिसमें 4 मेल और 3 फीमेल है। सभी को महिष मांस दिया जाता है। वहीं, इस वायरल वीडियो से अगर व्हाइट टाइगर के तबीयत खराब होने की अफवाह उड़ रही है तो हम उसकी जांच जरूर करवाएंगे। ठंड को देखते हुए बाघ के आहार में भी परिवर्तन लाया गया है। बाघ सिर्फ एक बार ही शाम 4 बजे खाना खाते हैं। ठंड के समय सभी बाघों को मिलाकर करीब 70 किलो मांस खाने में दिया जा रहा है, जो आम दिनों में 50 किलो ही रहता है। नाइट हाउस में बाघ के बैठने के लिए लकड़ी के प्लेटफार्म बनाए गए हैं, ताकि वह ठंडे फर्श पर न बैठे। बाघ के बाड़े में खासकर हीटर लगाया गया है। दिन के समय ये धूप में आराम करते हैं, लेकिन रात की ठंड से इनका सहारा हीटर बन रहे हैं। शरीर को गर्म रखने के लिए अंडा भी दिया जाता है।

पटना के खेतान मार्केट से कारोबारी लापता, रुपए का तगादा करने गया था बाजार

लोकतंत्र की शान : पटना। पटना के पीरबहोर इलाके में खेतान मार्केट के पास से एक 28 वर्षीय कारोबारी आदित्य लापता हो गया है। इस संबंध में उसके पिता संजय कुमार ने पिरबहोर थाना में शिकायत दर्ज कराई है। आवेदन के मुताबिक, उनका बेटा आदित्य कुमार गुरुवार शाम करीब 5 बजे खेतान सुपर मार्केट स्थित अपनी दुकान से रुपए का तगादा करने निकला था, लेकिन देर रात तक घर नहीं लौटा। परिजनों के अनुसार, गुरुवार की शाम 7:00 बजे जब आदित्य के मोबाइल पर कॉल करने पर फोन बंद मिला। पिता के मुताबिक, शाम करीब 6:30 बजे राजधानी मार्केट के एक दुकानदार से बात हुई थी, जिसने बताया कि आदित्य वहां से निकल चुका है। इसके बाद से उससे कोई संपर्क नहीं हो पाया। मिसिंग का केस दर्ज, सीसीटीवी खंगाल रही पुलिस पिरबहोर के थानेदार सज्जाद गद्दी ने बताया कि, आवेदन के आधार पर मिसिंग का केस दर्ज कर लिया गया है। फिलहाल युवक को ट्रेस किया जा रहा है और सीसीटीवी फुटेज खंगाला रही है। टेक्निकल इनपुट की मदद से खोजबीन की जा रही है। करोबारी की फैमिली कदमकुआं नवल किशोर रोड में रहती है। खेतान सुपर मार्केट की चौथी फ्लोर पर जय शीला क्रिएशन नाम से उनकी दुकान है। इसी दुकान से शाम के वक्त आदित्य पास के राजधानी मार्केट में गया था। खबर लिखे जाने तक आदित्य के बारे में कोई ठोस जानकारी पुलिस को नहीं मिल पाई थी। खोजबीन के लिए सीसीटीवी फुटेज और टेक्निकल इनपुट का सहारा लिया जा रहा है।

22 से 4 मार्च तक चलेगा फाल्गुन महोत्सव, 10 हजार से अधिक श्रद्धालु शोभायात्रा में होंगे शामिल

लोकतंत्र की शान : पटना। पटना में श्री श्याम फाल्गुन महोत्सव का भव्य आयोजन किया जाएगा। श्री श्याम सेवा ट्रस्ट न्यू बहादुरपुर की ओर से यह फाल्गुन महोत्सव का लगातार 30वां साल है। इसकी शुरुआत 22 फरवरी को ध्वजा निशान शोभायात्रा से होगी। इसमें देशी-विदेशी फूलों से सुसज्जित श्याम बाबा के रथ के साथ देश के अलग-अलग राज्यों से आई झांकी कलाकारों, भजन गायकों के साथ हाथों में बाबा का निशान लेकर हजारों श्याम भक्त शोभायात्रा निकालेंगे। इसमें सबसे आगे माथे पर जलती हुई सिगड़ी लेकर शामिल 51 महिलाएं आकर्षण का केंद्र होंगी। ट्रस्ट के अध्यक्ष विनोद थिरानी ने बताया कि यह शोभायात्रा दिन के 10 बजे बुद्धमार्ग स्थित श्री सत्यनारायण सेवा ट्रस्ट से निकलकर कोतवाली, डाकबंगला चौराहा, एग्जीबिशन रोड, पीरमुहानी, नाला रोड होते हुए न्यू बहादुरपुर स्थित श्री श्याम मंदिर पहुंचकर संपन्न होगा। शोभायात्रा में 10 हजार से अधिक श्रद्धालु भाग लेंगे। इसके बाद 26 फरवरी गुरुवार को श्याम मंदिर में अखंड पाठ, 27 फरवरी शुक्रवार को अखंड ज्योति, बाबा का भव्य श्रृंगार और रात्रि जागरण होगा। जबकि 28 फरवरी शनिवार को द्वादशी ज्योति और भंडारा प्रसाद का आयोजन होगा। 28 फरवरी को ही दिन में न्यू बहादुरपुर स्थित श्याम मंदिर परिसर के सामने स्थित श्री श्याम भवन में रक्तदान शिविर होगा। मां वैष्णो देवी सेवा समिति और मां ब्लड सेंटर के सहयोग से आयोजित इस रक्तदान शिविर में बड़ी संख्या में समाज के लोग रक्तदान करेंगे। इसके बाद बुधवार 4 मार्च की शाम 4 बजे से रंगारंग होली मिलन के साथ चटपटी संध्या का भी आयोजन होगा। इस मौके पर समाज के लोग जुटकर एक-दूसरे को होली की शुभकामनाएं देंगे।

एआई समिट विवाद, पटना में राहुल गांधी का पुतला फूंका

लोकतंत्र की शान : पटना। नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित 'AI समिट' के दौरान यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन पर सियासत गरमा गई है। इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने पटना में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। भाजपा कार्यकर्ता प्रदेश कार्यालय से जुलूस की शक्ल में निकले और पैदल मार्च करते हुए इनकम टैक्स गोलंबर पहुंचे। जहां कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस सांसद और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उनका पुतला दहन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे कुम्हरार विधायक संजय गुप्ता ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि, भारत मंडपम जैसे प्रतिष्ठित स्थल पर, जहां अंतरराष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञ और प्रतिनिधि मौजूद थे, वहां यूथ कांग्रेस द्वारा टी-शर्ट खोलकर किया गया प्रदर्शन अशोभनीय है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और राहुल गांधी की यह हरकत राष्ट्रीय सम्मान के खिलाफ है। अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में इस प्रकार का व्यवधान डालना देश की वैश्विक मंच पर शर्मसार करने जैसा है।

अग्नि पीड़ितों से मिले सांसदः हर संभव मदद और सरकारी सहायता का दिया भरोसा

लोकतंत्र की शानः सुमन सिंह कटिहार

कटिहारः कटिहार जिले के कुर्सेला हाट में बीते दिनों देर शाम लगी भीषण आग की घटना ने सैकड़ों परिवारों को झकझोर कर रख दिया है। इस भयावह अग्निकांड में सैकड़ों दुकानें जलकर राख हो गईं,जिससे करोड़ों रुपये की संपत्ति का नुकसान होने का अनुमान है।वही कटिहार के सांसद तारिक अनवर कुर्सेला पहुंचकर अग्नि पीड़ित दुकानदारों से मुलाकात की और घटनास्थल का जायजा लिया। सांसद ने पीड़ित दुकानदारों से मिलकर उनकी पीड़ा सुनी और हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि यह घटना अत्यंत दुखद और हृदयविदारक है। इस कठिन समय में हम सभी पीड़ित दुकानदार भाइयों के साथ खड़े हैं। जिन लोगों की वर्षों की मेहनत कुछ ही घंटों में राख हो गई,उनके दर्द को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता,उन्होंने राज्य सरकार से मांग किया है कि सभी अग्नि पीड़ितों को शीघ्र और उचित मुआवजा दिया जाए,ताकि वे दोबारा अपने व्यवसाय को खड़ा कर सकें। उन्होंने प्रशासन से क्षति का त्वरित आकलन कर राहत राशि उपलब्ध कराने की अपील की। इस दौरान सांसद ने क्षेत्र में दमकल व्यवस्था की कमी पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि आग लगने की स्थिति में यदि समय पर दमकल पहुंचती तो नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता था। उन्होंने आश्वस्त किया कि कुर्सेला सहित कटिहार जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में दमकल की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए संबंधित विभाग से बात की जाएगी, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं पर तुरंत काबू पाया जा सके। मौके पर मौजूद कटिहार जिला कांग्रेस अध्यक्ष सुनील कुमार यादव ने भी घटना को बेहद दुखद जताते हुऐ कहा कि इस अग्निकांड ने सैकड़ों परिवारों की आजीविका छीन ली है। इस संकट की घड़ी में पूरी कांग्रेस पार्टी पीड़ितों के साथ है और उन्हें हर स्तर पर सहयोग दिया जाएगा,उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों ने बताया कि आग इतनी तेजी से फैली कि दुकानदारों को सामान निकालने तक का मौका नहीं मिला। फिलहाल प्रशासन द्वारा नुकसान का आकलन किया जा रहा है और राहत कार्य जारी है। कुर्सेला हाट का यह अग्निकांड जिले के सबसे बड़े हादसों में से एक माना जा रहा है। अब पीड़ितों की निगाहें सरकार और प्रशासन की ओर टिकी हैं कि उन्हें कब तक राहत और मुआवजा मिल पाता है। मौके पर किसान कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष दिलीप विश्वास, शहनवाज खान,कुरसेला प्रखंड अध्यक्ष राजीव कुमार,बरारी प्रखंड अध्यक्ष सिमरनजीत सिंह,संजय सुमन,अकबर अंसारी,सत्यनारायण चौधरी, शमशाद आलम, अशोक मंडल सहित कई कांग्रेस नेता एवं स्थानीय जनप्रतिनिधि भी मौजूद थें।

कटिहार के कुर्सेला में बर्ड फ्लू रोकथाम के लिए चलाया गया संघन विसंक्रमण अभियान

लोकतंत्र की शान, सुमन सिंह कटिहार

कटिहार : कटिहार जिले के कुरसेला प्रखंड में कौवों की आकस्मिक मृत्यु (Crow death) के बाद एवियन इन्फ्लूएंजा (Avian Influenza - बर्ड फ्लू) के नियंत्रण और रोकथाम के लिए जिला प्रशासन और पशुपालन विभाग पूरी तरह सतर्क है। इसी क्रम में प्रभावित क्षेत्र में पुनः स्वच्छता और विसंक्रमण (Resanitization) का व्यापक कार्य किया गया। इस विशेष अभियान को जिला रैपिड रिस्पांस टीम (District RRT) और IAHP पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन सास्थान बिहार पटना की टीम द्वारा अंजाम दिया गया। क्षेत्र में संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए टीम ने सुरक्षा के कड़े मानकों का पालन करते हुए पूरे इलाके को सैनिटाइज किया। इस अभियान को पशु स्वास्थ्य एवं उत्पादन संस्थान के विशेषज्ञों की टीम ने किया,जिसमें मुख्य रूप से डॉ० दीपक कुमार,डॉ० प्रिया राज और डॉ० राऊत कविता अनिल शामिल थे।टीम के सदस्यों ने प्रभावित क्षेत्र का मुयायना किया और वैज्ञानिक तरीके से विसंक्रमण की प्रक्रिया पूरी की ताकि वायरस के प्रसार को रोका जा सके। विभाग द्वारा स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।

विधानसभा में 'हाथी' वाला तंज, 'बंदर' से पलटवार, सम्राट-पप्पू के बीच भाषाई जंग

लोकतंत्र की शान, पटना

डिप्टी सीएम और गृहमंत्री सम्राट चौधरी ने विधानसभा में बिना नाम लिए सांसद पप्पू यादव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज पुलिस के डर से हाथी भी बीमार होकर हॉस्पिटल जाना चाहता है। इसपर सांसद पप्पू यादव ने पटलवार किया और सोशल मीडिया X पर पोस्ट कर लिखा- 'नाबालिग था, अब बंदर बन गया है। इस बंदर के हाथ में बिहार है। सम्राट चौधरी और पप्पू यादव के बयान पर राजनीति गर्मा गई है। बीजेपी ने पप्पू यादव के बयान पर कहा कि सांसद ने भाषाई मर्यादा को तार-तार किया है। वहीं, राजद और कांग्रेस ने दोनों नेताओं के बयान को गलत बताया है।

हाथी बनाम बंदर से गरमाई राजनीतिः सम्राट चौधरी ने बिहार विधानसभा में कहा कि, 'दिल्ली से लोग पटना एयरपोर्ट पर उतरते हैं और कहते हैं कि बिहार पुलिस एक चींटी भी नहीं मार सकती। लेकिन, जब वही व्यक्ति अपने इस बयान को देने के दो घंटे के भीतर गिरफ्तार होते हैं, तो कहते हैं कि 'मैं तो बीमार हो गया हूं। बिहार में तो अब हाथी भी पुलिस के डर से बीमार होकर अस्पताल जाना चाहता है।' सम्राट चौधरी के बयान पर पलटवार करते हुए सांसद पप्पू यादव ने सोशल मीडिया 'एक्स' पर लिखा- 'नाबालिग था, अब बंदर बन गया है। इस बंदर के हाथ में बिहार है। स्वाभिमान की पगड़ी उतार कमीशन बटोरने के लिए पगड़ी को गमछा बना लिया।' पप्पू यादव के पोस्ट पर बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा ने कहा कि, 'जब व्यक्ति के पास जवाब नहीं होता तो ऐसे शब्दों का चयन करते हैं। बीजेपी इसकी कड़ी निंदा करती है और पप्पू यादव से सार्वजनिक माफी की मांग करती है। भारतीय राजनीति में इस तरह की भाषा की कोई जगह नहीं है।' सम्राट चौधरी और पप्पू यादव के बयान पर राजद प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि हाल के दिनों में राजनीति में भाषाई गिरावट आई है। सता पक्ष के जरिए जिस तरह से बयान दिए जा रहे हैं, वह कहीं ना कहीं मुद्दों से भटकाने की कोशिश के तहत किया जा रहा है। नीट छात्रा रेप-मौत मामले पर सरकार स्तर से जो न्याय मिलना चाहिए, वह मिल नहीं रहा है। इस कारण लोगों में गुस्सा है। राजनीति जीवन में कोई भी व्यक्ति हो, उन्हें जनता के हितों की बात और जनता के सवालों पर जवाब देना चाहिए, जिससे जनता का विश्वास बने और जनता के हित में काम हो।' कांग्रेस प्रवक्ता आसित नाथ तिवारी ने कहा कि आपकी परवरिश और आपकी शिक्षा जैसे हुई है, वैसा ही आपकी भाषा में दिखता है।

नगर निगम की सामान्य बोर्ड बैठक में विकास पर मंथन,जल जमाव, स्वच्छता और वार्ड भवन निर्माण को लेकर बड़े फैसले

लोकतंत्र की शान, सुमन सिंह कटिहार

कटिहारः कटिहार नगर निगम की महापौर उषा देवी अग्रवाल की अध्यक्षता में शनिवार को नगर निगम के सभागार में सामान्य बोर्ड की बैठक आयोजित की गई। बैठक में पूर्व उपमुख्यमंत्री-सह-सदर विधायक तारकेश्वर प्रसाद,डिप्टी मेयर मंजूर खान,नगर आयुक्त संतोष कुमार समेत नगर निगम से जुड़े सभी पार्षद,अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। बैठक का केंद्र बिंदु शहर का विकास और नागरिक सुविधाओं में सुधार लाना,शहर की सबसे बड़ी जलजमाव कि गंभीर समस्या पर चर्चा हुई तथा जलनिकासी व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। साथ ही स्वच्छता व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए नियमित कचरा उठाव सुनिश्चित करने और प्रमुख सड़कों पर स्ट्रीट लाइट की मरम्मत एवं नई लाइट लगाने का निर्णय लिया गया। सड़क और नाला निर्माण को लेकर भी ठोस रणनीति बनाई गई तथा जर्जर सड़कों और नालों के कायाकल्प के लिए चरणबद्ध योजना लागू की जाएगी। 20 वार्डों में नए वार्ड भवनों के निर्माण कि मंजूरी दी गई जबकि पुराने और जर्जर सामुदायिक भवनों के मरम्मत एवं जीर्णोद्धार का भी प्रस्ताव पारित हुआ। इसके अलावा कबीर अंत्येष्टि योजना के तहत जरूरतमंद परिवारों को मृत्यु के बाद दो हजार रुपये की तत्काल प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया गया ताकि कठिन समय में उन्हें आर्थिक सहारा मिल सके। बैठक में मेयर ऊषा देवी अग्रवाल ने कहा कि लिए गए फैसलों को जमीनी स्तर पर तेजी से लागू किया जाएगा ताकि शहर को एक बेहतर और सुविधाजनक नगर के रूप में विकसित किया जा सके। बैठक में स्वच्छता पदाधिकारी,वार्ड पार्षद प्रमोद महतो,बिट्टू घोष,निक्कू सिंह,कुमेंद्र प्रताप सिंह,संजय महतो,मनोज राय, दिनेश पांडे,उमेश पासवान,संतोष देवी,चांदनी देवी,कैलाश शर्मा सहित सभी वार्ड पार्षद व निगम कर्मी मौजूद थे।

महान कवि सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला' की जयंती सह अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के पावन अवसर पर एक गरिमामय एवं भावपूर्ण समारोह का आयोजन किया गया

लोकतंत्र की शान

डॉ. सी. वी. रमन विश्वविद्यालय, वैशाली की साहित्यिक एवं सांस्कृतिक पहल वनमाली सृजन पीठ, वैशाली तथा राष्ट्रीय बज्जिका भाषा परिषद के संयुक्त तत्वावधान में आज विश्वविद्यालय परिसर में महान कवि सूर्यकांत त्रिपाठी 'निराला' की जयंती सह अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के पावन अवसर पर एक गरिमामय एवं भावपूर्ण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की प्रमुख विशेषता रही "बज्जिका वार्षिकी 2026" का भव्य लोकार्पण, जिसे राष्ट्रीय बज्जिका भाषा परिषद, हाजीपुर द्वारा औपचारिक रूप से जारी किया गया। बज्जिका को एक सशक्त लोकभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने के उद्देश्य से संपूर्ण कार्यक्रम का संचालन बज्जिका लोकभाषा में ही किया गया, जिसने आयोजन को विशिष्ट गरिमा और भाषाई आत्मीयता प्रदान की। समारोह की दूसरी मुख्य विशेषता भव्य "कवि सम्मेलन" रहा, जिसमें आमंत्रित कवियों ने बज्जिका, हिंदी और मातृभाषा की महिमा पर ओजस्वी, भावपूर्ण एवं चिंतनशील रचनाओं का पाठ किया। कविताओं में लोकजीवन की सजीवता, सांस्कृतिक अस्मिता और भाषाई गौरव की अनुगूंज स्पष्ट रूप से परिलक्षित हुई। श्रोताओं ने तालियों की गड़गड़ाहट से कवियों का उत्साहवर्धन किया, जिससे संपूर्ण सभागार साहित्यिक ऊर्जा से आलोकित हो उठा। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में श्री ओंकार प्रसाद सिंह, प्रो. ब्रह्मदेव प्रसाद कार्यी, श्री वैशिष्ट्य राय वैशिष्ट्य, श्री देवेंद्र राकेश तथा श्री ज्वाला संध्या पुष्प की गरिमामयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम की अध्यक्षता विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. समित तिवारी ने की। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में कुलपति डॉ. समित तिवारी ने निराला के साहित्यिक अवदान को रेखांकित करते हुए उनके रचनात्मक वैभव, सामाजिक चेतना एवं भाषिक संवेदनशीलता पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने मातृभाषाओं के संरक्षण एवं संवर्धन को सांस्कृतिक अस्मिता की आधारशिला बताते हुए युवा पीढ़ी से अपनी भाषा और साहित्य के प्रति सजग एवं समर्पित रहने का आह्वान किया। विश्वविद्यालय के हिंदी विभागाध्यक्ष डॉ. विनोद कुमार शर्मा ने बज्जिका की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, उसकी भाषिक विशेषताओं तथा निराला की रचनाओं की सारगर्भित व्याख्या प्रस्तुत की। कृषि विभाग के अंतिम वर्ष के छात्र दिवाकर कुमार तिवारी ने अपनी स्वरचित कविता का प्रभावशाली पाठ कर श्रोताओं को भावविभोर कर दिया। समारोह में उपस्थित विद्वानों एवं साहित्यप्रेमियों ने बज्जिका भाषा के संरक्षण, संवर्धन एवं अकादमिक प्रतिष्ठा के लिए सामूहिक प्रयास की आवश्यकता पर बल दिया। कार्यक्रम का वातावरण भाषा, साहित्य और संस्कृति के प्रति गहन श्रद्धा एवं संवेदनशीलता से ओत-प्रोत रहा।कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका वनमाली सृजन पीठ, वैशाली के संयोजक श्री रिशु कुमार की थी। अंत में डॉ सुशील जमरियार के धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यक्रम का सफल समापन हुआ।

महापौर ने स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत व्यक्तिगत शौचालय के लिए कार्यदेश-सह- एकरारनामा वितरण किया

लोकतंत्र की शान, सुमन सिंह कटिहार

कटिहारः नगर निगम सभागार कक्ष में शुक्रवार को महापौर उषा देवी अग्रवाल की अध्यक्षता में स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के अन्तर्गत व्यक्तिगत शौचायल हेतु 59 लाभुकों को कार्यादेश- सह- इकरारनामा वितरण किया गया। इसके तहत पहले क़िस्त में फिफ्थ लेवल शौचालय के निर्माण के बाद लाभुकों को पहले क़िस्त के सात हजार पांच रुपए दिए जायेंगे तथा शौचालय के निर्माण पूर्ण होने बाद द्वितीय किस्त में 4500 सौ रुपए दिए जायेंगे। इस मौके पर उप नगर आयुक्त संतोष कुमार,उप महापौर मंजूर खान,स्वच्छता पदाधिकारी,वार्ड पार्षद एवं निगम कर्मी मौजूद थे।

पटना में बगीचे से अज्ञात युवक का शव मिला

लोकतंत्र की शान, पटना

पटना के बाढ़ थाना क्षेत्र के बेढना गांव के पास एक बगीचे में शनिवार सुबह अज्ञात युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। शव की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। सूचना मिलने पर आसपास के गांवों से लोग मौके पर जमा हो गए। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है।

सुबह खेत गए लोगों ने देखा शव, पुलिस को बुलायाः स्थानीय निवासी अजय कुमार ने बताया कि, वह सुबह करीब साढ़े छह बजे शौच के लिए खेत की ओर गए थे। तभी उनकी नजर जमीन पर बेसुध पड़े एक युवक पर पड़ी। पहले उन्हें लगा कि युवक नशे में सो रहा होगा, लेकिन पास जाकर देखने पर उसका चेहरा पीला और आंखें सफेद दिखाई दीं। स्थिति को समझने के बाद उन्हें अनहोनी की आशंका हुई। इसके बाद वह तुरंत घर लौटे और ग्रामीणों को इसकी जानकारी दी। यह खबर गांव में तेजी से फैल गई और देखते ही देखते घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा हो गई।

अभी नहीं हुई शव की पहचानः अजय कुमार ने बताया कि बीती रात गांव के पास दो अलग-अलग बारातें आई थीं। आशंका जताई जा रही है कि मृतक उन्हीं बारातों में से किसी एक का सदस्य हो सकता है।

नीट छात्रा मौत केस-सीबीआई ने मामी से की पूछताछ

लोकतंत्र की शान ,पटना

बोली-हॉस्टल संचालिका केस सेटल करने आई थी, पुलिस ने थप्पड़ मारा

पटना के NEET छात्रा रेप–मौत मामले में छात्रा की मामी से CBI ने पूछताछ की है। इस दौरान मामी ने जांच एजेंसी को कई अहम जानकारियां दीं। मामी ने CBI से कहा कि प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली जाए, क्योंकि वहां से महत्वपूर्ण सुराग मिल सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने आरोप लगाया कि जब बच्ची जिंदगी और मौत से जूझ रही थी, तब हॉस्टल की संचालिका नीलू अग्रवाल ने पैसे का ऑफर दिया था। मामी के मुताबिक, मौके पर मौजूद एक महिला सिपाही ने नील अग्रवाल को थप्पड़ भी मारा था।

संचालिका पर पैसे देकर सेटल करने की कोशिश का आरोपः छात्रा मामी ने CBI को बताया, 'जब उनकी भांजी की सांसे चल रही थी, उसी दौरान हॉस्टल संचालिका हॉस्पिटल नीलू अग्रवाल प्रभात मेमोरियल अस्पताल आई थी। उसने छात्रा की मां के सिर पर हाथ फेरा। सिर को सहलाते हुए कहा- 'आपकी बेटी को तो हम बचा नहीं पाए, जो पैसा लेना है ले लीजिए।' जांच टीम के सामने उन्होंने सवाल उठाया, 'जब हमारी भांजी की सांसे उस वक्त चल रही थी तो ऐसी बातें क्यों की? रुपयों का ऑफर परिवार को क्यों दिया? ये बातें पटना पुलिस की SIT को भी बताई गई थी, लेकिन SIT ने नीलम अग्रवाल से पूछताछ नहीं की। उसी दौरान वहां मौजूद एक महिला सिपाही ने नीलू को थप्पड़ भी मारा था। ये सब हॉस्पिटल के कैमरे में कैद हुआ है। इसलिए वहां के फुटेज की जांच होनी चाहिए।'

गयाजी में छात्रा की मामी से की पूछताछः इस मामले की जांच करते हुए CBI की टीम गुरुवार को गयाजी गई और मामी से पूछताछ की थी। क्योंकि, जब छात्रा का प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था, तब मामी उस दरम्यान वहां मौजूद थीं। SIT के कार्रवाई के बारे में मामी ने जांच एजेंसी को बताया कि हॉस्टल संचालिका से उन लोगों ने सख्ती से पूछताछ की ही नहीं। उल्टा चित्रगुप्त नगर थाना ले जाकर बांड भरवाकर उसे छोड़ दिया।

परिवार ने खुद के पैसों से लगवाए कैमरेः छात्रा के परिवार को दो बार धमकी मिल चुकी है। दोनों बार घर में धमकी भरा लेटर फेंका गया है। इसके बाद से परिवार के सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे थे। पारिवारिक सूत्रों के अनुसार, घर में CCTV कैमरा लगाने की बात हुई। इसके लिए सरकारी स्तर पर कोई मदद नहीं मिली। परिवार ने खुद से 4 CCTV खरीदा है और उसे अलग-अलग एंगल से इंस्टॉल करवाया है। सुरक्षा के नाम पर पुलिस की तरफ से 3 चौकीदार को लगाया गया है। इसमें एक की दिन में तो बाकी दो की ड्यूटी रात में होती है।

छात्रा के इलाज का क्रॉस वेरिफिकेशन कर रही CBIः सूत्रों के अनुसार छात्रा के हुए इलाज का CBI की टीम क्रॉस वेरिफिकेशन कर रही है। वो इस बात की जांच कर रही है कि छात्रा को इलाज के लिए जिन-जिन हॉस्पिटल में ले जाया गया था, क्या उन जगहों पर इलाज सही हुए थे?

संक्षिप्त समाचार

फरीदाबाद : शेयर मार्केट में निवेश के नाम पर लाखों की ठगी, दो आरोपी गिरफ्तार

लोकतंत्र की शान : फरीदाबाद। शेयर मार्केट में निवेश कर मोटा लाभ कमाने का लालच देकर लाखों रुपये की ठगी करने के मामले में साइबर थाना एनआईटी की टीम ने दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपितों की पहचान उत्तरप्रदेश निवासी हरदेव रावत व वरिष्ठ चाहर के रूप में हुई है। पुलिस प्रवक्ता ने शनिवार को बताया कि सेक्टर-22, फरीदाबाद निवासी एक व्यक्ति ने साइबर थाना एनआईटी में शिकायत दी थी कि 6 जुलाई 2025 को उसे व्हाट्सएप के माध्यम से एक ऐप-बेस्ड इन्वेस्टमेंट ग्रुप से जोड़ा गया। फिर उसका एक ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाया गया और निवेश संबंधी मार्गदर्शन देने के लिए एक अन्य ग्रुप में जोड़ा गया। ग्रुप में उसे 2-3 महीनों में 850 प्रतिशत तक मुनाफा कमाने का लालच दिया गया। झांसे में आकर शिकायतकर्ता ने विभिन्न ट्रांजेक्शनों के माध्यम से ठगों द्वारा बताए गए खातों में कुल 50 लाख 60 हजार रुपये निवेश कर दिए। कुछ समय बाद उसके अकाउंट में लगभग तीन करोड़ रुपये दर्शाए जाने लगे और जब राशि निकालने का प्रयास किया तो निकासी नहीं हो सकी। इस संबंध में संपर्क करने पर आरोपियों ने 61 लाख रुपये कमीशन के रूप में जमा कराने की मांग की। शिकायत के आधार पर साइबर थाना एनआईटी में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। पूछताछ में सामने आया कि वरिष्ठ चाहर ने अमान हुसैन का खाता खुलवाया हुआ था तथा उसने यह खाता आगे अमन कौशल को दिया था और अमन कौशल ने इस खाता आगे हरदेव को दे दिया। वरिष्ठ चाहर व हरदेव दोनों 12वीं पास है। दोनों आरोपितों को आज अदालत में पेश कर तीन दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। अमान हुसैन खाताधारक व अमन कौशल को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।

फरीदाबाद : सिंगापुर में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी, मास्टरमाइंड गिरफ्तार

लोकतंत्र की शान : फरीदाबाद। सिंगापुर में नौकरी दिलाने के नाम पर लाखों रुपए की ठगी करने के एक मामले में साइबर थाना सेंट्रल की टीम ने मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है। पुलिस प्रवक्ता ने शनिवार को बताया कि ईस्माइलपुर फरीदाबाद निवासी एक व्यक्ति ने साइबर थाना सेंट्रल में दी अपनी शिकायत में बताया कि 11 अगस्त 2025 को उसके पास एक अंजान नंबर से फोन आया जिसने अपने आपको एशिया कंसलटेंट से बताया और कहा कि सिंगापुर स्थित आई टी कंपनी में जॉब का आफर है। फिर शिकायतकर्ता का ऑनलाईन मीटिंग के माध्यम से साक्षात्कार लिया गया और ठगो ने प्रोफाईल वेरिफिकेशन एंव वीजा प्रोसेसिंग के नाम पर शिकायतकर्ता से दो लाख 41 हजार 103 रुपये विभिन्न खातों में ट्रांसफर करवा लिये। लेकिन शिकायतकर्ता को कोई नौकरी नही मिली। शिकायत पर साइबर थाना सेंट्रल में संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया। पूछताछ में सामने आया कि तुषार ने अपने एक अन्य साथी के साथ बरेली उत्तर प्रदेश में कमरा किराये पर लिया हुआ था, जहां पर वह ठगी का कारोबार चलता था। आरोपी कॉलर व इंटरव्यू लेने का काम करता था। ठगी के कार्य के लिये उसने अन्य व्यक्तियों को भी रखा हुआ था। वह एमबीए पास है और उस पर दिल्ली क्षेत्र में ठगी का एक अन्य मामला भी दर्ज है। आरोपी को अदालत में पेश कर चार दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है।

हिसार : बीमा कर्मी बताकर साइबर ठगों ने सेवानिवृत सूबेदार से कर डाली 15 लाख से ज्यादा की ठगी

लोकतंत्र की शान : हिसार। खुद को बीमा कंपनी का कर्मचारी बताकर पॉलिसी की बकाया राशि ब्याज सहित लौटाने का झांसा देकर साइबर ठगों ने सेवानिवृत सूबेदार से 15 लाख से अधिक की ठगी कर ली। ठगी का शिकार हुए लगभग 69 वर्षीय रिटायर्ड सूबेदार करण सिंह शहर के कैंट क्षेत्र में रहते हैं। साइबर पुलिस को दर्ज करवाई शिकायत में सूबेदारकरण सिंह ने शनिवार को कहा कि उन्होंने वर्ष 2010 में मैक्स न्यूयॉर्क लाइफ इंश्योरेंस की आठ लाख रुपए की पॉलिसी ली थी, जो 2020 में पूरी हुई। उन्हें उम्मीद से कम रकम मिली थी। इसी बात का फायदा उठाते हुए पिछले वर्ष 22 सितंबर को सीमा नामक एक महिला ने फोन किया और कहा कि उनकी पॉलिसी का बाकी पैसा कंपनी में जमा है, जो वापस मिल सकता है। इसके बाद राजीव शर्मा नामक व्यक्ति ने खुद को कंपनी एजेंट बताकर संपर्क किया और कहा कि पॉलिसी की कुल 13 लाख 28 हजार रुपए की राशि ब्याज सहित बनती है, लेकिन इसके लिए पहले रजिस्ट्रेशन फीस जमा करनी होगी। ऐसा झांसा देते हुए आरोपियों ने अलग-अलग तरह से विभिन्न बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर करवाए। सबसे पहले 17 अक्टूबर 2025 को 17 हजार 928 रजिस्ट्रेशन फीस के लिए रुपए लिए। इसके बाद पिछले वर्ष 31 अक्टूबर को कोड जनरेट शुल्क के लिए 44 हजार 980, 7 नवंबर को एडिशनल अमाउंट रिलीज शुल्क के 87 हजार 884, 21 नवंबर को एक लाख 52 हजार 400, 28 नवंबर को 92 हजार 017, दो दिसंबर को 92 हजार 17 रुपये, 10 दिसंबर को एक लाख 66 हजार 826, 26 दिसंबर को 2 लाख 35 हजार 339 के अलावा इस वर्ष 9 जनवरी 2026 को दो लाख रुपये, 12 जनवरी को 2 लाख 70 हजार रुपये और 15 जनवरी को एक लाख 56 हजार 943 की राशि खातों में डलवा ली। इस प्रकार कुल 15 लाख 16 हजार 338 रुपए आरोपियों ने अलग-अलग बहानों जैसे ऑडिट चार्ज, कोड, सरकारी शुल्क, अतिरिक्त लाभ आदि के नाम पर वसूल लिए। जब पीड़ित को शक हुआ तो आरोपियों ने नया पैंतरा अपनाया। संगीता और चिंतामणि नाम से फोन कर खुद को जीवन बीमा सुधार केंद्र, हैदराबाद का अधिकारी बताया। उन्होंने दावा किया कि एजेंट ने गलत कागजात बना लिए हैं और पूरी राशि करीब 18.40 लाख रुपए वापस दिलाई जाएगी, लेकिन पहले और शुल्क देना होगा। शिकायतकर्ताने अपनी जमा पूंजी, पेंशन पर लिए गए 3.30 लाख रुपए के पर्सनल लोन और पड़ोसियों से उधार लेकर रकम जमा कराई। इसके बावजूद न तो पॉलिसी का पैसा मिला और न ही जमा कराई गई राशि वापस हुई। उल्टा आरोपी और पांच लाख रुपये की मांग करने लगे। जब पीड़ित ने अपने छोटे बेटे को पूरी बात बताईतो उसे साइबर ठगी का शक हुआ। इसके बाद राष्ट्रीय साइबर क्राइम पोर्टल (एनसीसीआरपी) पर शिकायत दर्ज कराई गई। पुलिस ने केस दर्ज करके छानबीन आरंभ कर दी है।

पंचायत सचिव की गलती, जुर्माना लोक सेवा केन्द्र को

» मामला सीधी जनपद के ग्राम पंचायत उकरहा का
» सीईओ जिला पंचायत के पत्र ने बढ़ाई धड़कन

लोकतंत्र की शान

सीधी। जिले के जनपद पंचायत सीधी अंतर्गत ग्राम पंचायत उकरहा में चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां सरपंच का चुनाव लड़ने के लिए अनिल पटेल ने सचिव भगवानदीन पटेल से साठगांठ कर वोटरो को लुभाने के लिए सरकार की पेंशन योजना में ही सेंध लगा दी थी। मजे की बात यह रही कि जिस उद्देश्य से अनिल पटेल एवं सचिव भगवानदास पटेल ने फर्जीवाड़े की कहानी रची थी उसमें उन्हें सफलता भी मिल गई, आगामी चुनाव में ग्राम पंचायत के सरपंच पद पर अनिल पटेल ने अपनी पत्नी को मैदान में उतारा और चुनाव जीत गए। यह हम नहीं कह रहे हैं बल्किइस मामले को लेकर कराई गई जांच में खुलासा हुआ है, वहीं सीईओ जिला पंचायत द्वारा जारी आदेश भी इस बात की पुष्टि कर रहा है। अब इस मामले में जांच उपरांत सीईओ जिला पंचायत शैलेन्द्र सिंह सोलंकी ने लोक सेवा केन्द्र चुरहट के संविदाकार सहित कर्मचारियों को भी लपेटे में ले लिया है। उल्लेखनीय हैं कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत सीधी के पत्र कमांक 2097/ज.पं. / पेंशन / 2023 सीधी, दिनांक 27.07.2023 के द्वारा लेख किया गया है कि ग्राम पंचायत उकरहा के अपात्र पेंशनधारियों की जाँच कार्यालयीन पत्र कमांक 5493 दिनांक 27.12.2022 के द्वारा तीन सदस्यीय समिति गठित की जाकर कराई गई जिसमें पाया गया कि 173 पेंशनधारी सामाजिक सुरक्षा पेंशन के मापदण्ड के विपरीत होने के कारण अपात्र किया जाकर प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है। उक्त 173 अपात्र पेंशनधारियों में से 02 हितग्राहियों की पेंशन स्वीकृत उपरांत खाते में नही गयी एवं 22 पेंशनधारियों कल्याणी (विधवा) होने के कारण राष्ट्रीय वृद्ध पेंशन योजना से पेंशन प्राप्त कर रहे थे जो परीक्षण उपरान्त उक्त 22 हितग्राहियों की पेंशन कल्याणी पेंशन में शामिल कर पेंशन पुनः स्वीकृत की गयी जिससे 149 हितग्राही अपात्र पेंशन प्राप्त कर रहे थे जिनकी पेंशन बंद कर दी गयी है उक्त अपात्र पेंशनधारियों के द्वारा 642300/- कुल पेंशन जॉच प्रतिवेदन अनुसार वसूली योग्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। प्रकरण का अनुशीलन करने पर पाया गया कि 149 हितग्राही अपात्र पेंशन प्राप्त कर रहे थे जिनकी पेंशन बंद कर दी गयी है उक्त अपात्र पेंशनधारियों के द्वारा 642300/- कुल पेंशन जॉच प्रतिवेदन अनुसार वसूली योग्य पाया गया है। उक्त प्रकरण को म०प्र० पंचायतराज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा-89 के तहत विचरण में लिया गया है। सुनवाई दिनांक 20.01.2026 के दौरान प्रदीप सिंह तत्कालीन प्रबंधक लोक सेवा केन्द्र चुरहट द्वारा लिखित जबाव प्रस्तुत किया गया। जिसमें उनके द्वारा लेख किया गया है कि पीआरओ यमुना प्रसाद एवं राजेश प्रजापति द्वारा हितग्राही अनिल पटेल अथवा अन्य व्यक्तियों के साथ आवेदन प्रक्रिया के दौरान अन्यत्र लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से अनियमितता की स्थित निर्मित हुई है। जबकि यह साफ है कि अधिकांश आवेदकों के फॉर्म में मोबाइल नंबर सरपंच पति अनिल पटेल का डाला गया है जो उनकी चुनावी तैयारी एवं मतदाताओं को आकर्षित करने वाली चाल है।

तत्कालीन प्रबंधक पर घूम रही सक की सुई

लोक सेवा केन्द्र चुरहट के तत्कालीन प्रबंधक प्रदीप सिंह के कथन को लेकर यह माना जा रहा है कि इनके द्वारा पुरानी रंजिश को भुनाने के लिए जानबूझकर लोक सेवा केन्द्र को लपेटे में लिया गया है। बताया गया है कि तत्कालीन कलेक्टर मुजीबुर्रहमान खान द्वारा शिकायकर्ता अधिवक्ता ओ.पी. मिश्रा उपाध्यक्ष अधिवक्ता संघ चुरहट द्वारा प्रस्तुत आवेदन अनुसार लोक सेवा केन्द्र चुरहट के इंचार्ज प्रदीप कुमार पटेल पर लगे अभद्रता व गाली गलौच की शिकायत कराने के निर्देश दिए गए थे, जिसकी जांच एसडीएम चुरहट द्वारा की गई थी, एसडीएम कि रिपोर्ट पर कलेक्टर द्वारा प्रदीप सिंह को हटाने का आदेश जारी किया गया था। उस दौरान जांच टीम के समक्ष लोक सेवा केन्द्र के कर्मचारियों द्वारा प्रबंधक की अनियमितता को लेकर खुलासा किया था, जिसके चलते वह इन लोगों से नाराज चल रहे थे और जिला पंचायत सीईओ को अपने बयान में इस तरह की जानकारी दी गई है जिससे केन्द्र के सभी कर्मचारियों पर भी कार्यवाही हो सके।

केन्द्र के कर्मचारियों को बनाया गया इशारा

ग्राम पंचायत उकरहा में पेंशन योजना का लाभ दिलाने के लिए फर्जी दस्तावेज तैयार करने वाले इस मामले में लोक सेवा केन्द्र चुरहट के संविदाकार अजय सिंह, पीआरओ यमुना प्रसाद पाण्डेय एवं राजेश कुमार प्रजापति को भी वसूली की नोटिस भेजी गई है, जबकि यह संस्था सिर्फ आवेदन को ऑनलाइन करने के लिए अधिकृत है, ऐसे में लोक सेवा केन्द्र चुरहट के संविदाकार सहित कर्मचारियों को दोषी ठहराना सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। इस संबंध में विभागीय सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार लोक सेवा अधिनियम 2010 के तहत रोस्टर अनुसार सोमवार से शुक्रवार तक हर दिन प्राधिकारी अधिकारियों की ड्यूटी रहती हैं, जिसमें सोमवार को महिला बाल विकास अधिकारी, मंगलवार को तहसीलदार, बुधवार को वन परिक्षेत्र अधिकारी, गुरुवार को बीआरसी शिक्षा तथा शुक्रवार को मुख्य नगर परिषद अधिकारी रहते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि आवेदन की स्वीकृति लोक सेवा नहीं करता है, ऐसे में उसे दोषी ठहराया जाना समझ से परे है।

पंडित अरुण शुक्ला पत्रकारिता पुरस्कार से सम्मानित हुए आशीष रैकवार, यशभारत परिवार ने किया अभिनंदन

लोकतंत्र कि शान हसन रसीद जिला ब्यूरो चीफ जबलपुर कटनी मध्य प्रदेश

कटनी। कटनी यश भारत संस्करण के सब एडिटर आशीष रैकवार को कल 20 फरवरी को जबलपुर में आयोजित पंडित अरुण शुक्ला पत्रकारिता पुरस्कार एवं सम्मान समारोह में स्मृति चिन्ह, शॉल, श्रीफल और पुरस्कार राशि से सम्मानित किया गया। पत्रकार आशीष रैकवार को मिली यह उपलब्धि कटनी के पत्रकारिता जगत के लिए गौरव की बात है। समारोह में देश के वरिष्ठ पत्रकार एन के सिंह, वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट, जबलपुर के महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू, कुलपति पीके मिश्रा, एडिशनल एसपी पल्लवी शुक्ला, आईपीएस सिद्धार्थ चौधरी, नगर निगम प्रशासक श्री अहिरवार सहित अन्य अतिथियों की मौजूदगी रही। इस गरिमामय समारोह में प्रदेश शासन के केबिनेट मंत्री राकेश सिंह और राज्यसभा सांसद विवेक तनख़ा ने वर्चुअल संदेश के जरिए शुभकामनाएं दी। पत्रकार आशीष रैकवार को मिली इस उपलब्धि पर समूचा यशभारत परिवार गर्वित है। आज द्वारका सिटी रोड बरगवां कटनी स्थित कार्यालय में स्टाफ के सदस्यों ने आशीष रैकवार का तिलक वंदन और पुष्पहारों से स्वागत कर उज्जवल भविष्य की आत्मीय शुभकामनाएं दी। आशीष रैकवार ने सभी साथियों का आभार व्यक्त किया। इस मौके पर यशभारत के स्थानीय संपादक आशीष सोनी, पत्रकार संजय खरे, विज्ञापन प्रभारी कृष्णकुमार ठाकुर, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव आलोक त्रिपाठी, पूर्व पार्षद शिल्पी सोनी की उपस्थिति रही।

वैवाहिक कार्यक्रम में चली लाठी, तीन घायल

» शहर के खुशी पैलेस के समीप हुई वारदात

लोकतंत्र की शान

सीधी। शहर के पड़रा गांव में शुक्रवार रात बारात के दौरान अचानक तनावपूर्ण स्थिति बन गई। जानकारी के अनुसार बारात खुशी पैलेस के पास से गुजर रही थी, तभी घराती और बराती पक्ष के बीच किसी बात को लेकर विवाद शुरू हो गया। जहा देखते ही देखते कहासुनी ने उग्र रूप ले लिया और दोनों पक्षों के लोगों के बीच लाठी-डंडे चलने लगे। वही इस झड़प में तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि कई अन्य को मामूली चोटें आईं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बारात में शामिल लोग डीजे की धुन पर नाचते-गाते आगे बढ़ रहे थे। माहौल उत्सवपूर्ण था, लेकिन अचानक किसी बात पर दोनों पक्षों के बीच कहासुनी होने लगी। कुछ ही मिनटों में विवाद इतना बढ़ गया कि मौके पर अफरा-तफरी मच गई। महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी इस हंगामे से अछूते नहीं रहे। स्थानीय लोगों ने बीच-बचाव की कोशिश की, तब जाकर स्थिति धीरे-धीरे नियंत्रण में आई। विवाद की जानकारी देते हुए एक स्थानीय व्यक्ति ने बताया कि बारात सामान्य रूप से गुजर रही थी, तभी अचानक मारपीट शुरू हो गई। उनके अनुसार, विवाद का सटीक कारण स्पष्ट नहीं हो सका, परंतु झगड़ा काफी उग्र था और कई लोग लहूलुहान नजर आए। घायलों को तत्काल प्राथमिक उपचार के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। इस घटना के संबंध में सिटी कोतवाली थाना प्रभारी अभिषेक उपाध्याय थाना प्रभारी कोतवाली ने बताया कि किसी भी पक्ष द्वारा आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि यदि शिकायत मिलती है, तो मामले की जांच कर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आज आयोजित प्रेस वार्ता में देश एवं प्रदेश से जुड़े विभिन्न गंभीर जनहित मुद्दों को प्रमुखता से उठाया गया

लोकतंत्र की शान हसन रसीद जिला ब्यूरो चीफ जबलपुर कटनी मध्य प्रदेश

सबसे पहले भारत-अमेरिका ट्रेड डील के मुद्दे पर कांग्रेस नेताओं ने कहा कि यह समझौता देशहित के बजाय अमेरिकी दबाव में किया जा रहा प्रतीत होता है। ऐसी नीतियाँ देश के किसानों, लघु उद्योगों, व्यापारियों एवं आम उपभोक्ताओं पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकती हैं। कांग्रेस ने स्पष्ट कहा कि भारत की आर्थिक नीतियाँ स्वदेशी हितों के अनुरूप हों, न कि किसी बाहरी दबाव में। इसके पश्चात छिंदवाड़ा में कथित रूप से कफ सिरप सेवन से हुई दुखद घटना पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ला से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की मांग की गई। कांग्रेस ने कहा कि दवाओं की गुणवत्ता और स्वास्थ्य व्यवस्था पर नियंत्रण सुनिश्चित करना सरकार की प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसी क्रम में इंदौर के भगीरथपुरा क्षेत्र में दूषित जल पीने से लगभग 35—40 लोगों की दर्दनाक मौत की घटना को अत्यंत गंभीर प्रशासनिक लापरवाही बताते हुए मंत्री कैलाश विजयवर्गीय तथा संबंधित नगर प्रशासन की जवाबदेही तय करने की मांग की गई। कांग्रेस ने कहा कि नागरिकों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना सरकार का मूल कर्तव्य है, जिसमें इस प्रकार की विफलता अक्षम्य है। प्रेस वार्ता में यह भी कहा गया कि मंत्री विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी के लिए कथित रूप से प्रयुक्त आपत्तिजनक शब्द अत्यंत निंदनीय हैं। कांग्रेस ने इसे भारतीय सेना, महिला सम्मान और राष्ट्र की गरिमा से जुड़ा विषय बताते हुए ऐसे बयान पर तत्काल कार्रवाई एवं इस्तीफे की मांग की। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार के प्रति पूर्व में कहे गए आपत्तिजनक शब्दों की भी कड़ी निंदा की गई। कांग्रेस ने कहा कि लोकतंत्र में वैचारिक मतभेद स्वीकार्य हैं, लेकिन व्यक्तिगत एवं असम्मानजनक टिप्पणी किसी भी रूप में उचित नहीं है।

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत

वैदिक मंत्रोच्चार से 39 कन्याओं का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ

लोकतंत्र की शान हसन रसीद जिला ब्यूरो चीफ जबलपुर कटनी मध्य प्रदेश

मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत आज जनपद पंचायत कटनी में सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया प्रारंभ में ढोल नगाड़े एवं आतिशबाजी सहित सभी दूल्हों की बारात निकाली गई जनपद पंचायत कटनी द्वारा बारात की धूमधाम से अगवानी की गई इसके पश्चात वैदिक मंत्रोच्चार से 39 कन्याओं का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ विवाह पश्चात श्री जगदीश उर्मलिया जी द्वारा सभी जोड़ों को दीवाल घड़ी उपहार स्वरूप प्रदाय की गई कार्यक्रम में श्री जगदीश उर्मलिया उपाध्यक्ष जनपद पंचायत कटनी, श्री प्रमोद चतुर्वेदी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, श्री प्रदीप सिंह मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद कटनी ,दुर्गा मौसी जनपद सदस्य,श्री नितिन पांडे मंडलअध्यक्ष, प्रीति श्रीवास्तव सामाजिक सुरक्षा अधिकारी,श्रीमती वर्षा जैन, बलराम दाहिया,जग्गी पटेल, श्वेता बहरे आदि अधिकारी कर्मचारियों एवं जन प्रतिनिधियों की उपस्थिति रही

केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा कमेटी के प्रधान जत्थेदार जगदीश सिंह झीडा, एसपी ओबेरॉय और अन्य मैंबर साहिबान ने किया लैब का उद्घाटन

» एसपी ओबेरॉय नेक दिल इंसानः मनोहर लाल खट्टर
» एसपी ओबेरॉय पूरी निष्ठा से निभा रहे समाज के प्रति अपना दायित्वः जत्थेदार जगदीश सिंह झीडा

लोकतंत्र की शान, राजेंद्र करनाल की रिपोर्ट

करनालः केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि सरबत दा भला चैरिटेबल ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष एसपी ओबेरॉय नेक दिल इंसान है। वे सदा मानवता की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। एसपी ओबेरॉय निस्वार्थ भाव से मानव सेवा में जुटे हैं। केंद्रीय मंत्री आज हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के अधीन गुरुद्वारा श्री मंजी साहिब पातशाही पहली करनाल में सरबत दा भला चैरिटेबल द्वारा स्थापित की गई लैब के उद्घाटन अवसर पर बोल रहे थे। इससे पहले केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष एसपी ओबेरॉय, हरियाणा सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के प्रधान जत्थेदार जगदीश सिंह झीडा, सीएम श्री नायब सिंह सैनी के ओएसडी डॉ प्रबलीन सिंह, तख्त श्री पटना साहब के पूर्व जत्थेदार सिंघ साहिब इकबाल सिंह, बाबा जोगा सिंह नानकसर, बाबा जोगा सिंह तरावड़ी, बाबा सुखा सिंह, पूर्व प्रधान महंत करमजीत सिंह, हरियाणा कमेटी की कार्यकारिणी समिति मेंबर पलविंदर सिंह, जत्थेदार करनैल सिंह निम्नाबाद ने लैब का उद्घाटन किया। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हमें हमेशा समाज सेवा के लिए तत्पर रहना चाहिए। जिस तरह से एसपी ओबेरॉय मानव सेवा निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं, वह अपने आप में एक मिसाल है। एसपी ओबेरॉय ने पहुंचे हुए अतिथियों का आभार जताते हुए कहा कि मानव सेवा करना वे अपना कर्तव्य समझते हैं। उन्होंने संगत की मांग पर गुरुद्वारा साहिब में एक डेंटल क्लिनिक और फिजियोथेरेपी केंद्र स्थापित करने की घोषणा भी की। उन्होंने संगत को आश्वस्त किया कि जगह का प्रबंध होते ही फिजियोथेरेपी के केंद्र और डेंटल क्लिनिक यहां शुरू कर दिया जाएगा।

विधानसभा घेराव में ज्यादा से ज्यादा कांग्रेसजनों से पहुंचने की अपील

» मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर 24 फरवरी को होगा विधानसभा घेराव

लोकतंत्र की शान

सीधी। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर 24 फरवरी 2026 को प्रातः 11 बजे जवाहर चौक भोपाल में आयोजित विधानसभा घेराव कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु जिला कांग्रेस कमेटी सीधी के अध्यक्ष ज्ञान सिंह ने जिले के समस्त कांग्रेस पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं से अधिकतम संख्या में शामिल होने की अपील की है। ज्ञान सिंह ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ अब निर्णायक संघर्ष का समय आ गया है। भारत—अमेरिका ट्रेड डील किसानों, मजदूरों और छोटे व्यापारियों के हितों पर सीधा प्रहार है, जिससे कृषि व्यवस्था और आर्थिक आत्मनिर्भरता प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि मनरेगा में नाम परिवर्तन और नियमों में बदलाव कर गरीबों के काम के कानूनी अधिकार को कमजोर किया जा रहा है। यह ग्रामीण गरीबों और मजदूर वर्ग के साथ अन्याय है। ज्ञान सिंह ने आरोप लगाया कि उपमुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री राजेंद्र शुक्ल के कार्यकाल में हुए कफ सिरप कांड की नैतिक जिम्मेदारी तय नहीं की गई। इसी प्रकार मंत्री विजय शाह द्वारा महिला सेना अधिकारी एवं महिलाओं पर की गई अभद्र टिप्पणी अत्यंत निंदनीय है। वहीं मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से जुड़े दूषित जलप्रदाय प्रकरण में हुई मौतों पर अब तक ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। कांग्रेस पार्टी इन कलंकित मंत्रियों के तत्काल इस्तीफे की मांग करती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश आर्थिक बदहाली, बेरोजगारी, महंगाई और कानून व्यवस्था की गिरती स्थिति से जूझ रहा है। किसान, मजदूर, युवा और आमजन सभी वर्ग परेशान हैं। ऐसे समय में कांग्रेस पार्टी जनता की आवाज को बुलंद करने के लिए विधानसभा घेराव कर लोकतांत्रिक तरीके से विरोध दर्ज कराएगी। ज्ञान सिंह ने जिले के सभी वरिष्ठ नेतागण ,जिला पदाधिकारी, ब्लॉक अध्यक्षों, नगर अध्यक्षों, मंडलम/सेक्टर प्रभारियों, युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस, एनएसयूआई, सेवादल एवं अन्य अनुषांगिक संगठनों से आह्वान किया कि वे अधिकतम संख्या में 24 फरवरी को भोपाल पहुंचकर कार्यक्रम को ऐतिहासिक और सफल बनाएं। उन्होंने कहा कि यह संघर्ष केवल एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि किसानों, मजदूरों और आमजन के अधिकारों की रक्षा का व्यापक आंदोलन है। अब चुप रहने का समय नहीं है अन्याय के खिलाफ आवाज बुलंद करने का समय है।

संक्षिप्त समाचार

एमपी में 20 जिलों में बारिश-आंधी का अलर्ट

नई दिल्ली/भोपाल/जयपुर/लखनऊ। देश के कई हिस्सों में आज से मौसम में बदलाव दिखा है। मध्य प्रदेश में साइक्लोनिक सर्कुलेशन (चक्रवात) और टर्फ की एक्टिविटी की वजह से 4 दिन तक आंधी-बारिश का अलर्ट है। एक दिन पहले भी 20 से ज्यादा जिलों में बारिश हुई। राजस्थान में तापमान चढ़ने के साथ ही सर्दी घटने लगी है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में अगले एक सप्ताह मौसम साफ रहेगा। तापमान बढ़ने से दिन में गर्मी बढ़ेगी। 20 फरवरी को 6 शहरों का दिन का तापमान 30°C से ज्यादा रहा। न्यूनतम तापमान 11°C से 17°C के बीच है। हरियाणा में मौसम लगातार बदल रहा है। आज राज्य के अधिकांश शहरों में सुबह घना कोहरा छाया। हिसार में विजिबिलिटी करीब 50 मीटर से कम रही। मौसम विभाग के मुताबिक सबसे कम तापमान 8.5°C नारनौल का रहा, सबसे अधिक 29.9°C पलवल का रहा। पहाड़ों पर हल्की बारिश और बर्फबारी का दौर जारी है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में 22 फरवरी को बारिश और बर्फबारी का अलर्ट जारी किया है। वहीं कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में आज भारी बारिश की आशंका जताई है।

दिल्ली में कार की टक्कर से डिलीवरी बॉय की मौत

बेंगलुरु। दिल्ली में शुक्रवार देर रात तेज रफ्तार कार की टक्कर से डिलीवरी बॉय की मौत हो गई। हादसा रात 3.26 बजे सुभाष नगर मेट्रो रेड लाइट के पास राजौरी गार्डन की ओर जाने वाली सड़क पर हुआ। पुलिस के मुताबिक घटना में हेम शंकर (25) की मौत हुई है। वो रघुबीर नगर का रहने वाला था। हेम शंकर जेप्टो में काम करता था। टक्कर के उसकी इलेक्ट्रिक स्कूटी पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। पुलिस ने बताया कि घटना के बाद हेम शंकर को डीडीयू अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आरोपी कार ड्राइवर मोहित कुमार (27) को गिरफ्तार किया गया है। कार भी जब्त है। घटना के चश्मदीद का कहना है कि जब यह हादसा हुआ, तब कार की स्पीड 150 किमी की थी। आरोपियों ने टक्कर मारने के बाद मौके से भागने की कोशिश भी की थी। 20 फरवरी को भी कार ड्राइवर ने शकरपुर इलाके में सड़क किनारे मौजूद 5 रेहड़ियों को टक्कर मारी थी। इस घटना में भी 3 लोग घायल हुए थे। जनकपुरी इलाके में तेज रफ्तार कार सेंट्रो की टक्कर से 6 साल की बच्ची की मौत हुई थी। उसकी नानी गई। घटना 17 फरवरी की सुबह करीब 7.40 बजे की है। इसमें बच्ची की नानी मर्सी जेवियर भी गंभीर घायल हुई। उन्होंने बताया था कि मैं नातिन को ई-रिक्शा से स्कूल छोड़ने जा रही थी। तभी तेज रफ्तार कार ने हमारे रिक्शे को टक्कर मारी। मुझे कुछ समझ आता उससे पहले मैं सड़क पर गिर गई। जब होश आया तो मेरी नातिन मेरे पास पड़ी थी। मेरा हाथ खून से भीगा था।

गुजरात हाईकोर्ट बोला-मायके गई पत्नी को थप्पड़ मारना क्रूरता नहीं

नई दिल्ली। गुजरात हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा कि पत्नी के बिना बताए मायके में रात रुकने पर पति द्वारा थप्पड़ मारने की एक घटना को क्रूरता नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने एक पुराने मामले में पति को आरोपों से बरी कर दिया। जस्टिस गीता गोपी ने आदेश में कहा कि क्रूरता साबित करने के लिए लगातार और असहनीय मारपीट के ठोस सबूत जरूरी हैं। आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में यह भी दिखाना होगा कि आरोपी के कृत्य और आत्महत्या के बीच नजदीकी कारण संबंध था। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में ऐसा संबंध साबित नहीं हुआ।

क्या है पूरा मामलाः यह फैसला दिलीपभाई मंगलाभाई वरली की अपील पर आया। उन्होंने सेशंस कोर्ट के 2003 के फैसले को चुनौती दी थी। सेशंस कोर्ट ने मई 1996 में पत्नी की आत्महत्या के मामले में उन्हें दोषी ठहराते हुए धारा 306 में सात साल और धारा 498ए में एक साल की सजा सुनाई थी। अपीलकर्ता की ओर से धवल व्यास ने दलील दी कि आरोप सामान्य थे और दहेज मांग या उकसाने का कोई सबूत नहीं है। उन्होंने कहा कि विवाद पति के रात में बैंजो बजाने के लिए बाहर जाने और देर से लौटने को लेकर होता था। राज्य की ओर से ज्योति भट्ट ने सजा बरकरार रखने की मांग की। हाई कोर्ट ने कहा कि अभियोजन लगातार क्रूरता, मेडिकल रिकॉर्ड या पूर्व शिकायतें पेश नहीं कर सका। कोर्ट ने माना कि ट्रायल कोर्ट ने पर्याप्त सबूत के बिना सजा दी थी।

10 चैटिंग ऐप्स से अश्लील वीडियो कॉल, 2.5 करोड़ ठगे

शिवपुरी। मध्यप्रदेश के शिवपुरी में ऑनलाइन चैटिंग और वीडियो कॉल के जरिए अश्लील वीडियो रिकॉर्ड कर देशभर में लोगों को "डिजिटल अरेस्ट" का डर दिखाकर ब्लैकमेल करने वाले बड़े साइबर गिरोह का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। गिरोह अब तक ढाई करोड़ रुपए से ज्यादा की ठगी कर चुका है। गिरोह HIIU, TOKKI, MIKA, ELOELO, GAGA, HANI, SUGO, COMMECTO, HITSU, HONEY और COMET जैसे ऐप्स का इस्तेमाल कर रहा था। ये ऐप्स एपीके फाइल के जरिए आसानी से डाउनलोड हो जाते हैं। ऑनलाइन चैटिंग की तलाश में लोग इन्हें इंस्टॉल कर लेते थे, जिसका फायदा आरोपी उठाते थे। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 32 नामजद आरोपियों में से 20 को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से 7 कार, 1 बाइक, 29 मोबाइल, 16 एटीएम कार्ड, 7 बैंक पासबुक, एक मकान की रजिस्ट्री और 1.20 लाख रुपए नकद सहित करीब 1 करोड़ 7 लाख रुपए का माल जब्त किया गया है। एसपी अमन सिंह राठौड़ ने बताया कि आरोपी महिलाओं के नाम से फर्जी व्हाट्सएप अकाउंट बनाते थे। ऑनलाइन चैटिंग के इच्छुक लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते। अश्लील बातचीत और वीडियो कॉल करते। पूरी कॉल और चैट की रिकॉर्डिंग कर लेते। फिर खुद को पुलिस अधिकारी बताकर कॉल करते। बलात्कार, चाइल्ड पोर्नोग्राफी जैसे गंभीर अपराधों में फंसाने की धमकी देते। "डिजिटल अरेस्ट" और केस सेटलमेंट के नाम पर रकम ट्रांसफर करवा लेते। सामाजिक बदनामी और कानूनी कार्रवाई के डर से कई पीड़ित बड़ी रकम भेज देते थे।

बिग-बी ने एमपी के नागदा को गांव कहा, केस दर्ज

उज्जैन। कौन बनेगा करोड़पति के 23 दिसंबर 2025 को प्रसारित एपिसोड में मध्यप्रदेश के नागदा को लेकर की गई टिप्पणी पर विवाद खड़ा हो गया है। शो के होस्ट अमिताभ बच्चन द्वारा नागदा को पानी की समस्या से जूझता छोटा सा गांव बताए जाने पर स्थानीय स्तर पर आपत्ति दर्ज कराई गई है। इस मामले में नागदा के ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास (JMFC) न्यायालय में परिवाद दायर किया गया। न्यायालय ने परिवाद स्वीकार करते हुए प्रकरण को सीआईएस (Case Information System) में दर्ज करने और संबंधित थाने से प्रतिवेदन (रिपोर्ट) प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। दरअसल, किसी भी सिविल या आपराधिक प्रकरण को अदालत में प्रस्तुत किए जाने पर उसे CIS में रजिस्टर किया जाता है। इसके बाद पिटीशन को कोर्ट द्वारा स्वीकार (एक्सेप्ट) किया हुआ माना जाता है। मामले की अगली सुनवाई 9 अप्रैल को निर्धारित की गई है। स्थानीय निवासी एवं अधिवक्ता लक्ष्मण सुंदरा ने अमिताभ बच्चन के साथ-साथ सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इंडिया के सीईओ गौरव बैनर्जी के खिलाफ भी अपराध पंजीबद्ध करने की मांग को लेकर आवेदन प्रस्तुत किया है। अब अगली सुनवाई के बाद न्यायालय आगे की कार्रवाई तय करेगा। प्रकरण की पैरवी कर रहे अधिवक्ता राजेश मंडवारिया (आलोट) और दीपमाला अवाना (नागदा) का कहना है कि इतने बड़े राष्ट्रीय कार्यक्रम में नागदा शहर के बारे में भ्रामक जानकारी दी गई, जिससे शहर की छवि प्रभावित हुई है। अधिवक्ता जैना श्रीमाल के अनुसार, कार्यक्रम में नागदा को छोटा गांव और पानी संकटग्रस्त बताया गया, जबकि यह तथ्यात्मक रूप से गलत है।

ट्रम्प बोले- ट्रेड डील में कोई बदलाव नहीं

अमेरिकी अधिकारी ने कहा- 10% टैरिफ ही लगेगा

एजेंसी, वॉशिंगटन डीसी

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के दुनियाभर के देशों पर लगाए गए टैरिफ को रद्द कर दिया है। इसके कुछ घंटे बाद ही ट्रम्प ने फिर से 10% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। ऐसे में भारत पर लगे टैरिफ को लेकर यह भी सवाल उठ रहा है कि भारत को 18% टैरिफ देना होगा या 10%। इसकी दो वजहें हैं- राष्ट्रपति ट्रम्प ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि भारत के साथ ट्रेड डील पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यह पहले की तरह आगे बढ़ेगी। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक, व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने बताया ब्रिटेन, भारत और यूरोपीय संघ सहित अमेरिका के साथ व्यापार समझौते करने वाले देशों को अब धारा 122 के तहत 10% वैश्विक टैरिफ का ही सामना करना पड़ेगा, न कि उस टैरिफ दर का जिस पर उन्होंने पहले बातचीत की थी। BBC की रिपोर्ट सही मानें तो भारत पर कुल टैरिफ 18% घटकर 10% रह

जाएगा, जबकि ट्रम्प का बयान 18% टैरिफ की ओर इशारा कर रहा है। टैरिफ पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले और ट्रम्प की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भारत सरकार ने कहा है कि वह पूरे मामले को ध्यान से देख रही है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने शनिवार को कहा कि अमेरिकी प्रशासन ने जो भी नए कदम उठाए हैं, उनके भारत पर क्या असर पड़ सकते हैं, इसका आकलन किया जा रहा है। मंत्रालय के अनुसार, शुक्रवार को आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले और ट्रम्प की प्रेस कॉन्फ्रेंस को नोट किया गया है। अमेरिका की ओर से कुछ फैसलों की घोषणा भी की गई है। सरकार इन सभी घटनाक्रमों को समझ रही है, ताकि यह तय किया जा सके कि इनका भारत और दोनों देशों के व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ सकता है।

ट्रेड डील फरवरी के अंत तक फाइनल होगीः वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले शुक्रवार मीडिया से बात की थी। तब उन्होंने बताया था कि अमेरिका के साथ 'अंतरिम व्यापार समझौता' फरवरी के अंत तक फाइनल हो जाएगा। मार्च में इस पर हस्ताक्षर होंगे, वहीं अप्रैल से ये समझौता पूरी तरह लागू हो जाएगा। इसके साथ ही आने वाले कुछ महीनों में भारत दुनिया के बड़े देशों साथ व्यापारिक समझौतों पर अंतिम मुहर लगाएगा। अप्रैल में ब्रिटेन और ओमान के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट शुरू होने की उम्मीद है। 23 फरवरी से भारत और अमेरिका के अधिकारी अमेरिका में तीन दिनों की अहम बैठक करेंगे। इस बैठक का मकसद 7 फरवरी को जारी 'जॉइंट स्टेटमेंट' के आधार पर कानूनी ड्राफ्ट तैयार करना है।

अजित पवार के भतीजे का आरोप- प्लेन क्रैश बड़ी साजिश

एजेंसी, नई दिल्ली/बारामती/मुंबई

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद पवार गुट) के विधायक रोहित पवार ने शनिवार को अजित पवार के प्लेन क्रैश पर फिर सवाल उठाए। उन्होंने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्क्रीन पर डेटा और फोटो दिखाए। उन्होंने कहा कि ब्लैक बॉक्स को लेकर शक जताया जा रहा था। उनके मुताबिक, दुर्घटना के समय सिर्फ एक धमाका नहीं हुआ था, बल्कि कई धमाके हुए थे। विमान में सामान रखने वाली जगह पर अतिरिक्त पेट्रोल के डिब्बे रखे गए थे, जिससे आग भड़की। सभी पहलुओं की गहराई से जांच होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि अगर साजिश की बात करें तो यह दो तरह की हो सकती है, राजनीतिक या व्यावसायिक। अभी यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि इस मामले में किस तरह की साजिश शामिल है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की 28 जनवरी को बारामती में प्लेन क्रैश में मौत हो गई थी। यह प्लेन VSR कंपनी का था।

रोहित बोले- पीएम मोदी और गृह मंत्री शाह न्याय दिलाएंः रोहित ने आरोप लगाया है कि अजित

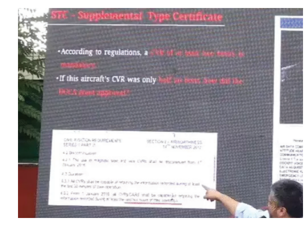

▢ दुर्घटना के समय कई धमाके हुए थे, विमान में पेट्रोल के डिब्बे रखे गए थे

पवार प्लेन क्रैश के मामले को कुछ लोग कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को लेटर लिखा है। मैं आपसे केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू के मामले में तुरंत कार्रवाई करने का निवेदन करता हूं। कंपनी VSR और उनकी पार्टी के बीच संबंधों को लेकर गंभीर सवाल उठे हैं। इन संबंधों की जांच किसी स्वतंत्र और निष्पक्ष एजेंसी से कराई जानी चाहिए, जरूरत हो तो अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों की मदद भी ली जाए। आपने हमेशा अजित दादा और उनके देश के प्रति योगदान का सम्मान किया है।

हिमाचल सीएम सुक्खू की तबीयत बिगड़ी

एजेंसी, शिमला

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू आज दिल्ली में बीमार पड़ गए। वह दिन में करीब 12 बजे उपचार के लिए AIIMS दिल्ली पहुंचे। टेस्ट कराने के बाद सीएम सुक्खू वापस हिमाचल सदन लौट आए हैं। अब उनका स्वास्थ्य ठीक बताया जा रहा है और तेजी से सुधार हो रहा है। हालांकि, सीएम के स्वास्थ्य को लेकर मेडिकल बुलेटिन का अभी इंतजार है।

सूचना के अनुसार- सीएम सुक्खू के पेट में सुबह के वक्त अचानक दर्द उठा। जैसे ही दर्द तेज हुआ तो वह सीएम अस्पताल पहुंचे, जहां उनका उपचार शुरू हुआ और टेस्ट करवाए गए। सूत्रों के अनुसार- सीएम के सभी टेस्ट ठीक बताए जा रहे हैं। डॉक्टरों ने उन्हें आराम करने की सलाह दी है।

सीएम सुक्खू काफी समय से पैंक्रियाज और पेट में इन्फेक्शन की समस्या से जूझ रहे हैं। सीएम 2 बार आईजीएमसी शिमला और एक बार एम्स दिल्ली में इलाज करवा चुके हैं। डॉक्टरों ने सीएम

को आराम करने की सलाह दी है। अब वह हिमाचल सदन में आराम कर रहे हैं। बता दें कि सीएम सुक्खू कांग्रेस हाईकमान के साथ बीते कल रखी गई मीटिंग में शामिल होने के लिए दिल्ली गए थे। सीएम शुक्रवार सुबह शिमला से पहले श्रीनगर गए। शाम के वक्त वह श्रीनगर से सीधे दिल्ली पहुंचे।

दिल्ली में बीते कल 5 बजे के बाद कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ एक मीटिंग में शामिल हुए। इसमें रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट बंद करने, हिमाचल कांग्रेस संगठन और सेब पर इम्पोर्ट ड्यूटी घटाने को लेकर चर्चा की गई। आज सुबह उनका केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कांग्रेस हाईकमान से मिलने का प्रोग्राम था।

बस-वैन में आमने-सामने की भिड़ंत, 5 की मौत

एजेंसी, भिंड

भिंड में शुक्रवार देर रात बस और वैन आमने-सामने भिड़ गए। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हैं। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वैन पूरी तरह पिचक गई। उसमें सवार लोग अंदर ही फंस गए। हादसा गोहद चौराहा थाना अंतर्गत छींमका गांव के पास नेशनल हाईवे-719 पर रात 2.30 बजे हुआ। गोहद चौराहा थाना प्रभारी मनीष धाकड़ के अनुसार, ईको वैन ग्वालियर से सवारियों को लेकर भिंड की ओर आ रहा था, जबकि बस भिंड से ग्वालियर की ओर जा रही थी। हादसे में चार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। एक ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ा। वहीं, घायलों को एम्बुलेंस से ग्वालियर रेफर किया गया। जयारोग्य हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है।

हादसे में मरने वाले सभी लोगों की पहचान हुईः टीआई मनीष धाकड़ ने बताया कि सभी मृतकों की पहचान हो गई है। इनमें प्रदीप प्रजापति पुत्र रामप्रकाश, उसका भांजा अतुल शिवहरे निवासी फूप और जगदीश भदौरिया निवासी स्योड़ा गांव अकोड़ा और आनंद भदौरिया पुत्र मुकेश भदौरिया निवासी परसोना गांव हैं। वैन चालक की पहचान गोहद के इटाली गांव के रहने वाले भरत तिवारी के रूप में हुई।

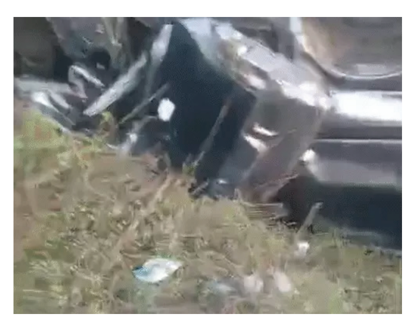

जिस जगह हादसा हुआ, वहां अंधा मोड़ः पुलिस परिजन का पता लगाने के लिए दस्तावेजों और वाहन नंबर के आधार पर जांच कर रही है। जिस जगह हादसा हुआ, वहां अंधा मोड़ है। हो सकता है दोनों वाहन तेज रफ्तार में हों। हादसे की जांच जारी है। दोनों वाहनों को सड़क से हटाकर यातायात बहाल कर दिया गया है।

आखिर निर्दोष लोग कब तक मरते रहेंगे- कालिदास महाराजः भिंड हादसे पर संत समिति के जिला अध्यक्ष कालिदास महाराज ने कहा कि लगातार सड़क हादस हो रहे हैं, लेकिन ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। आखिर निर्दोष लोग कब तक यूं ही जान गंवाते रहेंगे। केवल आश्वासन से काम नहीं चलेगा।

चौड़ीकरण और सुरक्षा को लेकर आंदोलन की घोषणाः उन्होंने कहा कि जब

▢ भिंड में नेशनल हाईवे पर गाड़ी के परखच्चे उड़े, यात्री अंदर ही फंस गए, 6 लोग गंभीर

सड़क निर्माण और चौड़ीकरण का काम शुरू ही नहीं हुआ तो हाईवे पर टोल वसूली किस आधार पर की जा रही है। कालिदास महाराज ने घोषणा की कि हाईवे चौड़ीकरण और सुरक्षा को लेकर अब आर-पार की लड़ाई लड़ी जाएगी। उन्होंने कहा कि 27 तारीख को जिलेभर के समाजसेवी और आंदोलनकारी मेहगांव के हनुमान मंदिर पर एकत्रित होकर आंदोलन की औपचारिक शुरुआत करेंगे। यह सिर्फ एक दिन का प्रदर्शन नहीं होगा, बल्कि जब तक हाईवे विस्तार और सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होती, तब तक चरणबद्ध और तेज आंदोलन जारी रहेगा।

2 साल से संत समाज के नेतृत्व में आंदोलनः नेशनल हाईवे-719 चार विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरता है। इस पर लगातार हो रहे हादसों को लेकर 2 साल से संत समाज के नेतृत्व में आंदोलन हो रहा है। आंदोलनकारी जुलाई 2025 में केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से भी मुलाकात कर चुके हैं। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया भी इस हाईवे के अपग्रेडेशन के लिए कई बार कह चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है।

मायावती-अखिलेश बोले- एआई समिट में कांग्रेस का प्रदर्शन गलत, भाजपा का देशभर में प्रदर्शन

एजेंसी, नई दिल्ली/मुंबई/गुजरात

सपा प्रमुख अखिलेश यादव और बसपा चीफ मायावती ने दिल्ली के भारत मंडपम में AI समिट में शुक्रवार को कांग्रेस के प्रदर्शन को गलत बताया है। अखिलेश ने कहा जब दुनियाभर से डेलीगेट्स आये हो तो ऐसा हंगामा नहीं करना चाहिए। सरकार से लड़ाई हमारा इंटर्नल मामला है, फॉरेन डेलीगेट्स के सामने हमारे देश का अपमान होता है। मायावती ने X पर लिखा- कांग्रेस का प्रदर्शन निन्दनीय है। अगर यह सम्मेलन अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का नहीं होता तो अलग बात थी, लेकिन AI समिट के दौरान ऐसा व्यवहार करना चिन्ता की बात है। इधर, कांग्रेस के AI समिट में हंगामा करने के विरोध में भाजपा ने दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, तेलंगाना और जम्मू-कश्मीर में प्रदर्शन किया।

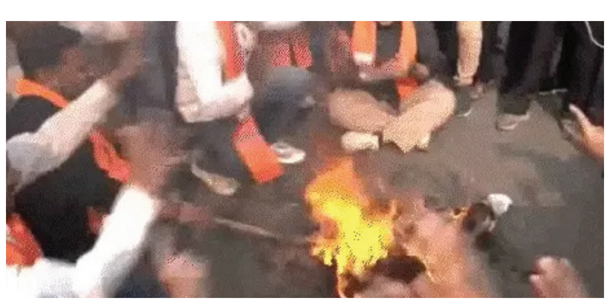

◆ महाराष्ट्र में राहुल को काले झंडे दिखाए

मुंबई के मुलुंड में भाजपा कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के काफिले को काले झंडे दिखाए। उधर, AI समिट में हंगामा करने वाले कांग्रेस के चारों कार्यकर्ताओं को आज पटियाला कोर्ट में पेश किया गया। पुलिस ने कोर्ट में कहा कि प्रदर्शन करने वाले नेपाल के Gen-Z आंदोलन से प्रेरित थे। यह प्रदर्शन एक बड़ी साजिश का हिस्सा था। हंगामे के दौरान कई ग्लोबल लीडर्स और टेक इंडस्ट्री के एक्सपर्ट वहां मौजूद थे। पुलिस ने कहा कि यह जांच करनी है कि आरोपियों ने PM मोदी की फोटो वाली टी-शर्ट किससे छपवाई। इसके अलावा उनके मोबाइल फोन भी बरामद करने हैं। इसके बाद न्यायिक मजिस्ट्रेट रवि ने चारों आरोपियों को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया।

भारत मंडपम में यूथ कांग्रेस ने हंगामा कियाः 20 फरवरी को दिल्ली स्थित भारत मंडपम में इंडियन यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को AI समिट 2026 में भारत-अमेरिका ट्रेड डील के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के कई वीडियो भी सामने आए थे। इसमें 10 से ज्यादा कार्यकर्ता हाथ में सफेद रंग की टी-शर्ट लिए हुए थे। टी-शर्ट पर PM मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की फोटो लगी है। उस पर लिखा है- PM इज कॉम्प्रोमाइज्ड। गिरफ्तार लोगों ने बिहार से यूथ कांग्रेस के नेशनल सेक्रेटरी कृष्ण हरि, बिहार में IYC स्टेट सेक्रेटरी कुंदन यादव, उत्तर प्रदेश में IYC स्टेट प्रेसिडेंट अजय कुमार और तेलंगाना से नरसिम्हा यादव शामिल हैं।

केंद्रीय मंत्री नड्डा ने सोलन में नई वैक्सीन लॉन्च की

एजेंसी, कसौली

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा ने आज (शनिवार को) हिमाचल प्रदेश के सोलन जिला स्थित केंद्रीय अनुसंधान संस्थान (CRI) कसौली में नई वैक्सीन लांच की। उन्होंने CRI में टीटनेस और एडल्ट डिफ्थीरिया (Td) वैक्सीन का शुभारंभ किया।

इस दौरान जेपी नड्डा ने कहा कि यह स्वदेशी वैक्सीन सीआरआई के प्रयासों से बनी है। यह नई वैक्सीन किशोरों और वयस्कों के साथ साथ गर्भवती महिलाओं को भी टीटनेस और डिफ्थीरिया से सुरक्षा प्रदान करेगी। Td वैक्सीन, टीटनेस टॉक्सॉइड (TT) वैक्सीन की जगह लेने के लिए डिजाइन की गई है, जिससे डिफ्थीरिया के खिलाफ सुरक्षा भी सुनिश्चित हो सके।

जेपी नड्डा ने कहा कि भारत ने ड्रग्स, दवाओं और वैक्सीन बनाने में वर्ल्ड लीडर के रूप में स्थापित किया है। इसमें सीआरआई कसौली का बहुत बड़ा रोल है। सीआरआई कसौली का 120 सालों का इतिहास है। Td वैक्सीन अब यूनिवर्सल इम्युनाइजेशन प्रोग्राम (UIP) के तहत उपलब्ध करवाई जाएगी।

टीटनेस एक बैक्टीरियल संक्रमण है, जो क्लॉस्ट्रिडियम टेटानी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है।

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रम्प के टैरिफ रद्द किए, भारत पर 18% भी टैरिफ खत्म

एजेंसी, वॉशिंगटन डीसी

अमेरिका में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के दुनियाभर के देशों पर लगाए गए टैरिफ को रद्द कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले से भारत पर लगा 18% रेसिप्रोकल टैरिफ भी अब अवैध घोषित हो गया है। दरअसल, ट्रम्प ने राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए IEEPA कानून का इस्तेमाल कर अप्रैल 2025 में दुनिया के करीब 100 देशों से पर टैरिफ लगाने का ऐलान किया था। सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से फैसला सुनाते हुए कहा कि ट्रम्प को IEEPA कानून का इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं है। यह अधिकार राष्ट्रपति को नहीं, सिर्फ संसद को है। कोर्ट के इस फैसले के 3 घंटे के बाद ट्रम्प ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने दुनियाभर के देशों पर नए कानून (सेक्शन-122) का

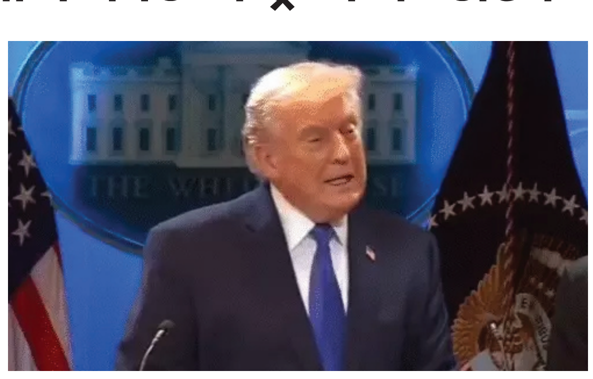

इस्तेमाल कर 10% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है।

24 फरवरी से लागू होगा 10% टैरिफः ट्रम्प ने एक आदेश पर हस्ताक्षर कर दुनियाभर के देशों पर 10% का टैरिफ लगा दिया है। यह टैरिफ 24 फरवरी से लागू हो जाएगा। BBC की रिपोर्ट के मुताबिक, व्हाइट हाउस के एक अधिकारी ने बताया ब्रिटेन, भारत और यूरोपीय यूनियन समेत अमेरिका के साथ व्यापार समझौते करने वाले देशों को अब 10% टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। यानी कि भारत पर अब टैरिफ 18% की जगह घटकर 10% रह जाएगा। उन्होंने टैरिफ को अवैध बताने वाले जजों की भी आलोचना की। ट्रम्प ने कहा- मुझे कोर्ट के कुछ जजों पर शर्म आ रही है। वे देश के लिए कलंक हैं, उनमें हमारे देश के लिए सही काम करने की हिम्मत नहीं है।

◆ नाराज ट्रम्प ने 10% नया टैरिफ लगाया, जजों को कलंक कहा

भारत के साथ ट्रेड डील पर ट्रम्प ने कहा कि, इस डील में कोई बदलाव नहीं होगा। पीएम मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं।

सुप्रीम कोर्ट के रद्द किए गए टैरिफ लागू करने के लिए मुझे संसद की जरूरत नहीं है। मैं इन्हें राष्ट्रपति के मिले अधिकारों के जरिए लागू कर सकता हूं। सुप्रीम कोर्ट में रिफंड को लेकर कोई साफ बात नहीं कही गई है। इसलिए अमेरिकी सरकार किसी भी कंपनी को टैरिफ के रूप में वसूला गया पैसा वापस नहीं करेगी। जज ने बहुत ही घटिया फैसला सुनाया है। मुझे लगता है कि अब इस मामले पर अगले दो साल तक कोर्ट में मुकदमा चलेगा। हम अगले 5 साल तक कोर्ट में ही रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विदेशी ताकतों का असर पड़ा है। अगर टैरिफ नहीं लगाए गए, तो विदेशी देश कुछ उद्योगों में अमेरिका से आगे निकलते रहेंगे। टैरिफ लगाने का यह कदम कई साल पहले के राष्ट्रपतियों को उठा लेना चाहिए था। उन्होंने हमारे देश को कमजोर होने दिया और दूसरे देशों को फायदा उठाने दिया।

सेक्शन 122 के जरिए नया टैरिफ लगाएंगे ट्रम्पः सेक्शन 122 अमेरिका के एक कानून का हिस्सा है, जिसे ट्रेड एक्ट ऑफ 1974 कहा जाता है। यह कानून अमेरिकी राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि अगर देश को अचानक व्यापार घाटे या आर्थिक संकट का खतरा हो, तो वे तुरंत आयात पर टैरिफ लगा सकते हैं। इसके तहत राष्ट्रपति बिना लंबी जांच प्रक्रिया के अस्थायी तौर पर टैरिफ लगा सकते हैं। आमतौर पर यह टैरिफ 150 दिनों तक लागू रह सकता है। इस दौरान सरकार स्थिति की समीक्षा करती है और आगे का फैसला लेती है। NBC न्यूज के मुताबिक दुनिया के सभी व्यापारिक साझेदार देशों पर 10% का एक जैसा ग्लोबल टैरिफ लगाने का मतलब होगा कि जिन देशों पर ज्यादा टैरिफ लगा है वह खुद घट जाएगा। कुछ उत्पादों को छूट दी गई है, जैसे कुछ कृषि उत्पाद (बीफ, टमाटर, संतरा), महत्वपूर्ण खनिज, दवाइयां, कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स और पैसेंजर वाहन। ट्रम्प प्रशासन ने कहा कि यह टैरिफ पुराने वाले की जगह लेगा और वे अधिक पैसा कमाने की कोशिश जारी रखेंगे।

भारत में स्मार्ट और प्रीपेड बिजली मीटर- वैधानिक स्थिति, विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 47(5),और राज्य नियामक आयोगों का दृष्टिकोण -एक समग्र विश्लेषण

एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं

» स्मार्ट एवं पूर्वभुगतान विद्युत मीटर-विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 47(5) और राज्य विद्युत नियामक आयोगों की भूमिका

» परंपरागत बिज़ली मीटर से स्मार्ट/प्रीपेड मीटर तक का परिवर्तन,विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 47(5) कानूनी रेखा-राज्य विद्युत नियामक आयोगों के विनियमों आदेशों का गहन परीक्षण आवश्यक -एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र

गोंदिया - वैश्विक स्तरपर पारंपरिक मीटर व्यवस्था से उन्नत डिजिटल मीटरिंग प्रणाली की ओर पूरी दुनियाँ चल पड़ी है।पिछले कुछ वर्षों से भारत देश के अनेक राज्यों में पारंपरिक विद्युत मीटरों को हटाकर उन्नत डिजिटल अथवा पूर्वभुगतान मीटर लगाए जाने की प्रक्रिया तेज़ हुई है। अनेक स्थानों से समाचार प्राप्त हुए हैं कि विद्युत विभागों के कर्मचारी उपभोक्ताओं की सहमति के बिना पुराने मीटरों को हटाकर नए पूर्वभुगतान या डिजिटल मीटर स्थापित कर रहे हैं,जिसके कारण जनसामान्य में असंतोष और विरोध की स्थिति उत्पन्न हुई है। इस परिस्थिति ने एक महत्वपूर्ण विधिक प्रश्न को जन्म दिया है,क्या भारत में ऐसा कोई वैधानिक प्रावधान है जो इन मीटरों को अनिवार्य रूप से लागू करने की अनुमति देता हो? मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं क्रि इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 47(5),केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा बनाए गए नियमों तथा राज्य विद्युत नियामक आयोगों द्वारा जारी विनियमों और दर आदेशों का गहन परीक्षण आवश्यक है। पिछले कुछ वर्षों में भारत में पारंपरिक (पोस्टपेड/एक्यूरेटेड) मीटरों के स्थान पर स्मार्ट मीटर और स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का अभियान तेज़ी से बढ़ा है। इसका मुख्य उद्देश्य बिजली वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति सुधारना, एग्रीगेट टेक्निकल एंड कमर्शियल नुकसान घटाना, वास्तविक- समय डेटा आधारित बिलिंग करना और उपभोक्ताओं को बिजली उपयोग नियंत्रण का विकल्प देना रहा है। इस रणनीति का बड़ा ढांचा रेवाम्पड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम के तहत है, जिसमें हजारों लाख स्मार्ट मीटर के रोलआउट का लक्ष्य रखा गया है,लेकिन सैद्धांतिक और ऐतिहासिक पैमाने पर मीटर बदलना अनिवार्य है या वैकल्पिक है,इस पर बहस जारी है।बहुत-सी मीडिया रिपोर्टों और उपभोक्ता विरोध के बीच,यह समझना ज़रूरी है कि कानूनी-नियामक आधार क्या कहता है, विशेषकर विद्युत अधिनियम, 2003 का प्रावधान धारा 47(5) और राज्य विद्युत नियामक आयोग के नियमन/आदेशों के संदर्भ में। इस आर्टिकल के माध्यम से चर्चा करेंगे। साथियों बात अगर हम विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 47(5):वास्तविक विधिक आशय को समझने की करें तो, विद्युत अधिनियम, 2003 भारत में विद्युत क्षेत्र का मूल कानून है। इसकी धारा 47 मुख्यतः सुरक्षा जमा से संबंधित है।धारा 47(5) का आशय यह है कि यदि कोई उपभोक्ता पूर्वभुगतान मीटर के माध्यम से विद्युत आपूर्ति प्राप्त करने के लिए सहमत होता है, तो वितरण अनुज्ञाधारी उससे सुरक्षा जमा राशि नहीं ले सकता। यहाँ दो महत्वपूर्ण बिंदु उभरते हैं,पहला, यह प्रावधान उपभोक्ता को विकल्प देता है। दूसरा,यह प्रावधान वितरण कंपनी को यह अधिकार नहीं देता कि वह सभी उपभोक्ताओं पर पूर्वभुगतान मीटर अनिवार्य रूप से लागू करे।अर्थात् धारा 47(5) का उद्देश्य उपभोक्ता के हित में विकल्प प्रदान करना है, न कि अनिवार्यता थोपना। यदि कानून की भाषा का शाब्दिक और उद्देश्यपरक विश्लेषण किया जाए, तो स्पष्ट होता है कि इसमें कहीं भी यह नहीं कहा गया कि प्रत्येक उपभोक्ता को पूर्वभुगतान या डिजिटल मीटर स्वीकार करना ही होगा,उसे ऑप्शन जरूर होगा।

साथियों बात अगर हम क्या किसी भी राज्य के राज्य विद्युत वितरण नियम,इस अधिनियम से ऊपर हो सकते हैं? विधिक सिद्धांत की कसौटी इसको समझने की करें तो, भारतीय विधि व्यवस्था का एक मूल सिद्धांत है कि अधीनस्थ नियम, विनियम या आदेश मूल अधिनियम के विपरीत नहीं हो सकते। यदि अधिनियम में कोई अनिवार्यता नहीं दी गई है,तो नियम बनाकर उसेअनिवार्य नहीं बनाया जा सकता।केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण ने मीटर स्थापना और संचालन से संबंधित विनियम जारी किए हैं, जिनमें उन्नत मीटर प्रणाली को प्रोत्साहित किया गया है। किंतु यह विनियम अधिनियम की सीमाओं के भीतर ही प्रभावी हो सकते हैं। यदि अधिनियम उपभोक्ता को विकल्प देता है, तो नियम बनाकर उस विकल्प को समाप्त नहीं किया जा सकता। इस प्रकार, केवल प्रशासनिक सुविधा या वित्तीय सुधार के आधार पर उपभोक्ता की वैधानिक स्वतंत्रता को बिलकुल सीमित नहीं किया जा सकता। साथियों बात अगर हम राज्य विद्युत नियामक आयोगों की भूमिका और अधिकार क्षेत्र को समझने की करें तो प्रत्येक राज्य में एक राज्य विद्युत नियामक आयोग स्थापित है।इन आयोगों का दायित्व है,विद्युत दरों का निर्धारण करना,वितरणकंपनियों के कार्यों की निगरानी करना, उपभोक्ता हितों की रक्षा करना, नियम एवं विनियम बनाना, किन्तु इन आयोगों की शक्ति भी विद्युत अधिनियम, 2003 से ही प्राप्त होती है।अतः वे ऐसे नियम नहीं बना सकते जो अधिनियम की मूल भावना के विरुद्ध हों।अब प्रश्न उठता है क्या किसी राज्य आयोग ने ऐसा कोई विनियम या दर आदेश जारी किया है जो सभी उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट अथवा पूर्व भुगतान मीटर अनिवार्य करता हो?उपलब्ध सार्वजनिक अभिलेखों के आधार पर यह स्पष्ट है कि अधिकांश राज्यों में ऐसे विनियम प्रारूप स्तर पर तैयार किए गए हैं, या केवल प्रोत्साहन स्वरूप व्यवस्था की गई है। पूर्णतःसार्वभौमिक अनिवार्यता लागू करने वाला स्पष्ट,व्यापक और बाध्यकारी विनियम अभी तक व्यापक रूप से लागू नहीं हुआ है। साथियों बात अगर हम विभिन्न राज्यों की स्थितिः नीतिगत प्रोत्साहन बनाम वैधानिक अनिवार्यता इसको समझने की करें तो,देश के कई राज्यों में वितरण कंपनियों ने प्रशासनिक आदेशों के माध्यम से नए कनेक्शनों पर उन्नत मीटर लगाने की प्रक्रिया प्रारंभ की है। कुछ राज्यों में सरकारी कार्यालयों और संस्थानों में पहले चरण में इन मीटरों की स्थापना की गई है। कुछ स्थानों पर सभी नए उपभोक्ताओं के लिए स्मार्ट मीटर अनिवार्य करने का निर्णय लिया गया है।परंतु यहाँ एक महत्वपूर्ण भेद समझना आवश्यक है, प्रशासनिक निर्णय और वैधानिक अनिवार्यता में अंतर है।यदि कोई वितरण कंपनी अपने स्तर पर आदेश जारी करती है, तो वह तभी वैध होगा जब उसे राज्य विद्युत नियामक आयोग की स्वीकृति प्राप्त हो और वह अधिनियम के अनुरूप हो। यदि आयोग ने विधिवत विनियम बनाकर, सार्वजनिक परामर्श के बाद, अधिनियम की सीमाओं के भीतर अनिवार्यता घोषित की हो,तभी उसे पूर्ण वैधानिक बल प्राप्त होगा।अब तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार,अधिकतर राज्यों में स्मार्ट मीटरिंग को नीति स्तरपर बढ़ावा दिया गया है, किंतु इसे पूर्ण रूप से सभी उपभोक्ताओं के लिए बाध्यकारी घोषित करने का स्पष्ट और निर्विवाद उदाहरण सीमित या विवादास्पद है। साथियों बात अगर हम उपभोक्ता अधिकार और सहमति का प्रश्न को समझाने की करें तो, भारतीय संविधान उपभोक्ता को विधि द्वारा संरक्षित अधिकार प्रदान करता है। विद्युत सेवा एक आवश्यक सार्वजनिक सेवा है। यदि किसी उपभोक्ता की सहमति के बिना उसका मीटर बदला जाता है, और उसे ऐसी प्रणाली में डाला जाता है जिससे उसका सेवा अधिकार प्रभावित होता हो, तो यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध हो सकता है।कई स्थानों पर उपभोक्ता संगठनों ने यह तर्क दिया है कि,धारा 47(5) विकल्प देती हैअनिवार्यता उपभोक्ता अधिकार का हनन है,सुरक्षा जमा की वापसी एवं भुगतान प्रणाली में पारदर्शिता सुनिश्चित होनी चाहिए न्यायालयों में दायर याचिकाओं में भी यही तर्क प्रस्तुत किया गया है कि यदि अधिनियम विकल्प देता है, तो उसे प्रशासनिक आदेश से बिलकुल ही समाप्त नहीं किया जा सकता। साथियों बात अगर हम आर्थिक और प्रशासनिक तर्क बनाम विधिक सीमाएँ इसको समझने की करें तो,सरकार और वितरण कंपनियाँ यह तर्क देती हैं कि उन्नत मीटर प्रणाली से,राजस्व संग्रहण सुधरेगा,चोरी एवं तकनीकी हानि कम होगी, बिलिंग त्रुटियाँ घटेंगीउपभोक्ता वास्तविक समय में खपत देख सकेंगे, ये तर्क आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। किंतु किसी भी आर्थिक या तकनीकी लाभ को लागू करने से पूर्व विधिक वैधता आवश्यक है।विधिक प्रक्रिया में सार्वजनिक परामर्श,पारदर्शिता और न्यायसंगतता अनिवार्य तत्व हैं।यदि अनिवार्यता लागू करनी है तो,स्पष्ट विनियम बने,उपभोक्ताओं को सुनवाई का अवसर मिले,संक्रमण अवधि दी जाए,सुरक्षा और डेटा गोपनीयता के मानक सुनिश्चित किए जाएँ। साथियों बात अगर हम क्या कोई राज्य आयोग ने पूर्ण अनिवार्यता लागू की है? इसको समझने की करें तो उपलब्ध सार्वजनिक अभिलेखों और विनियमों के परीक्षण से यह निष्कर्ष निकलता है कि, अधिकांश राज्यों ने स्मार्ट मीटरिंग को प्रोत्साहित किया है। कुछ राज्यों ने नए कनेक्शनों पर इसे लागू करने का निर्णय लिया है। कई राज्यों में प्रारूप विनियम तैयार किए गए हैं।किंतु सभी उपभोक्ताओं पर बिना विकल्प के पूर्ण अनिवार्यता लागू करने वाला व्यापक और निर्विवाद विनियम व्यापक रूप से लागू नहीं हुआ है।अर्थात् वर्तमान स्थिति मिश्रित है नीतिगत प्रोत्साहन अधिक है,परंतु वैधानिक अनिवार्यता सीमित या विवादाधीन है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि भारत के किसी भी प्रमुख राज्य विद्युत नियामक आयोग ने सार्वजनिक रूप से एक नियम/आदेश जारी नहीं किया है, जो हर उपभोक्ता पर स्मार्ट/प्रेपेड मीटर लागू करना अनिवार्य करे। अधिकांश मामलों में नियमन वैकल्पिक उपयोग, नए कनेक्शनों पर सिफारिश या उत्पादन-लागत सहायता/टाइमलाइन जैसे विषयों पर केंद्रित है।कई न्यायालयिक मामलों और पीआईएल (जैसे बॉम्बे हाईकोर्ट , कर्नाटका हाईकोर्ट) में यह तर्क दिया गया है कि उपभोक्ता की सहमति के बिना मीटर को बदलना या उसे प्रीपेड फार्मेट में स्विच करना नियमों के विरुद्ध है। विशेष रूप से, कुछ न्यायालयों ने यह स्पष्ट किया कि धारा 47(5) सुरक्षा जमा संबंधी प्रावधान देती है, न कि मामूली से अनिवार्यता हालाँकि सुप्रीमकोर्ट के एक मामले में यह भी पाया गया कि जब उपभोक्ता स्वेच्छा से प्रीपेड मीटर अपनाता है,तो उसकी सुरक्षा जमा राशि को वापस करना आवश्यक है, इसका मतलब यह है कि वैकल्पिक उपयोग को सटीक मान्यता दी जाती है,न कि जबरन लागू करना। साथियों बात अगर हम इस मुद्दे कोअंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में समझने की करें तो,विश्व के अनेक देशों में उन्नत मीटर प्रणाली लागू की गई है। किंतु वहाँ भी इसे चरणबद्ध ढंग से, व्यापक जनपरामर्श और विधिक स्पष्टता के साथ लागू किया गया। उपभोक्ता अधिकार, डेटा सुरक्षा, पारदर्शिता और शिकायत निवारण तंत्र को पहले स्थापित किया गया, तत्पश्चात अनिवार्यता लागू की गई।भारत में भी यदि इस दिशा में स्थायी और निर्विवाद व्यवस्था स्थापित करनी है, तो वही मार्ग अपनाना होगा। अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे क्रि,विद्युतअधिनियम, 2003 की धारा 47(5) पूर्वभुगतान मीटर को विकल्प के रूप में मान्यता देती है, अनिवार्यता के रूप में नहीं।राज्य विद्युत नियामक आयोगों को अधिनियम की सीमाओं में रहकर नियम बनाने होते हैं।अधिकांश राज्यों में स्मार्ट मीटरिंग को नीति स्तर पर प्रोत्साहन मिला है, किंतु सर्वव्यापी अनिवार्यता का स्पष्ट और निर्विवाद उदाहरण सीमित है।प्रशासनिक आदेश और वैधानिक विनियम में अंतर है।उपभोक्ता सहमति, पारदर्शिता और विधिक प्रक्रिया का पालन अनिवार्य है।इसलिए वर्तमान विधिक स्थिति यह दर्शाती है कि स्मार्ट या पूर्वभुगतान मीटर का व्यापक प्रसार हो रहा है,किंतु इसे पूर्णतःऔर सार्वभौमिक रूप से बाध्यकारी घोषित करने के लिए स्पष्ट विधिक आधार, पारदर्शी प्रक्रिया और न्यायसंगत विनियमन आवश्यक है।यदि भविष्य में कोई राज्य आयोग स्पष्ट रूप से अनिवार्यता घोषित करता है, तो वह तभी वैध मानी जाएगी जब वह,अधिनियम की भावना के अनुरूप हो उपभोक्ता अधिकारों की रक्षा करे विधिक चुनौती की कसौटी पर खरी उतरे इस प्रकार, वर्तमान स्थिति को समझने के लिए केवल प्रशासनिक घोषणाओं पर नहीं, बल्कि अधिनियम, विनियम और न्यायिक व्याख्या पर ध्यान देना आवश्यक है।

-संकलनकर्ता लेखक - क्रर विशेषज्ञ स्तंभकार साहित्यकार अंतरराष्ट्रीय लेखक चिंतक कवि संगीत माध्यमा सीए(एटीसी) एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानीं गोंदिया महाराष्ट्र
9284141425

जहाँ हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा है और सारा का सारा है

लेखक - डॉ. प्रवीण दाताराम गुगनानी

कश्मीर की वर्तमान स्थिति को लेकर हमारा समूचा भारत राष्ट्र चिंतित रहा है। इस राष्ट्रीय चिंता का ही प्रकटीकरण था 22 फरवरी 1994 को पूर्व प्रधानमंत्री की नरसिंहराव सरकार द्वारा संसद में पारित 'कश्मीर संकल्प'। इस संकल्प में भारत का राजनीतिक पक्ष-विपक्ष, समस्त नागरिकों का मानस सम्मिलित था। यह संकल्प राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की चिंता, भावना व विचार से प्रेरित था। संसद में पारित इस प्रस्ताव में यह संकल्प किया गया था कि - "पाकिस्तान के कब्जे वाला POJK जम्मू कश्मीर और भारत का अभिन्न अंग था, है और सदैव रहेगा। पाकिस्तान ने 1947-48 के बाद से ही भारत के इस बड़े भूभाग पर कब्जा कर रखा है। इस प्रस्ताव के जरिये यह संकल्प लिया गया था कि पाकिस्तान के अवैध कब्जे में लद्दाख और जम्मू कश्मीर की जो हमारी भूमि है उसे हम हर स्थिति में वापस लेंगे। यह संकल्प दिवस POJK, POTL के साथ COTL की मुक्ति का संकल्प दिवस भी है। वस्तुतः जम्मू-कश्मीर और लद्दाख का कुल क्षेत्रफल लगभग 2,22,236 वर्ग किमी है। इसमें से POJK यानि पाकिस्तान अधिक्रांत जम्मू कश्मीर का क्षेत्रफल 13,297 वर्ग किमी है। POJK में जम्मू-कश्मीर क्षेत्र के मीरपुर-मुजफ्फराबाद, भीम्बर, कोटली जैसे नगर सम्मिलित हैं, जो कभी हिन्दू बहुल हुआ करते थे। जबकि POTL अर्थात (पाकिस्तान अधिक्रांत क्षेत्र लद्दाख) में गिलगित और बाल्टिस्तान सम्मिलित हैं। यह क्षेत्र खनिज संपदा से लबालब है। POTL का कुल क्षेत्रफल लगभग 64817 वर्ग किमी है। PoJK और POTL मूल रूप से जम्मू कश्मीर का ही एक भाग है, जिसकी सीमाएं पाकिस्तान के पंजाब, उत्तर-पश्चिम, अफगानिस्तान के वखान गलियारे, चीन के शिनजियांग क्षेत्र और लद्दाख के पूर्व क्षेत्र से होकर गुजरती हैं। गिलगित-बाल्टिस्तान (POTL) में 1480 सोने की खदानें हैं, जिनमें से 123 में अयस्क है, जहाँ सोने की मात्रा दक्षिण अफ्रीका की विश्व प्रसिद्ध खदानों से कई गुना अधिक है। चीन अधिक्रांत लद्दाख क्षेत्र अर्थात COTL का संभावित एरिया 37 हजार वर्ग किमी है और इसमें 5,180 किमी शक्सगाम का एरिया पाकिस्तान ने 1963 में Sino-Pak एग्रीमेंट के तहत दे दिया था। यानि चीन के कब्जे में कुल क्षेत्रफल 42,735 वर्ग किलोमीटर है। COTL में सिर्फ अक्साई चीन नहीं बल्कि ट्रांस काराकोरम ट्रैक्ट और मिंसर भी शामिल है। यहाँ से मुख्यतः कई नदियाँ निकलती हैं। जैसे गलवान नदी, चिपचैप नदी और कार्स जैसी आदि-आदि नदियाँ निकलती हैं। लेकिन इनमें कार्कस नदी सबसे बड़ी नदी है, जो कि उत्तर की ओर जाती है और इसे ब्लैक जेड रिवर कहते हैं। भारत का यह महत्वपूर्ण भाग आज चीन के नियंत्रण में है।

वस्तुतः 1947 में देश के विभाजन के कुछ महीनों बाद ही पाकिस्तानी सेना ने 22 अक्टूबर 1947 को जम्मू-कश्मीर पर आक्रमण कर दिया था। इस आक्रमण में पाकिस्तानी सैनिकों ने हजारों की संख्या में निर्दोष हिंदूओं (प्रमुखतः सिक्ख समुदाय) का जघन्य नरसंहार किया था और प्राचीन मंदिरों, गुरुद्वारों आदि हिंदू स्थलों का विध्वंस किया था। बाद में इन हिंदुओं के अपमान के उद्देश्य से इन कब्जाए गए धार्मिक स्थलों का अपमानजनक प्रयोग भी किया गया था। इन घटनाओं के बाद बड़ी संख्या में हिंदू बंधु अपने कश्मीर से पलायन को विवश हो गये थे। विगत लगभग आठ दशकों से POJK स्थित हमारे ऐतिहासिक मंदिरों, गुरुद्वारों और बौद्ध मठों को पाकिस्तानी आतताइयों ने चुन-चुन कर विध्वंस करने का काम किया है। PoJK पर पाकिस्तान का 76 वर्षों से अवैध नियंत्रण है। आज समूचे भारत राष्ट्र सहित, PoJK के विस्थापितों की यह मांग है कि पाकिस्तान के अवैध कब्जे में जो हमारा कश्मीर है उसे वापस लिया जाए और PoJK विस्थापितों को उनका अधिकार लौटाया जाए। पूर्व प्रधानमंत्री पी.वी नरसिम्हा राव का कार्यकाल जम्मू-कश्मीर के लिए अनेक उतार-चढ़ाव वाला था।

रॉबर्ट बैडेन-पावेल की प्रेरणा से सेवा और नेतृत्व का संदेशः स्काउट संस्थापक दिवस

लेखक - सुनील कुमार महला

22 फरवरी को स्काउट संस्थापक दिवस या संस्थापक दिवस (फाउंडर्स डे) के रूप में मनाया जाता है। वास्तव में यह दिवस स्काउट आंदोलन के संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट बैडेन-पावेल की जयंती के रूप में मनाया जाता है तथा स्काउट्स और गाइड्स के लिए विशेष महत्व रखता है।यह दिन उनकी पत्नी तथा विश्व प्रमुख गाइड ओलेव बैडेन-पॉवेल का भी जन्मदिन होता है। पाठकों को बताता चलूं कि भारत में इसे अक्सर विश्व चिंतन दिवस (वर्ल्ड थिंकिंग डे) के साथ जोड़कर भी देखा जाता है। पाठकों को बताता चलूं कि स्काउट्स प्यार से संस्थापक को बी.पी. भी कहते हैं।इस दिन स्काउट और गाइड अपने नियम और प्रतिज्ञा(स्काउट प्रॉमिस)को दोहराते हैं तथा करोड़ों स्काउट यूनिफॉर्म पहनकर समाज सेवा के कार्य करते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो इस दिन स्काउट और गाइड्स द्वारा सामुदायिक सेवा, रक्तदान, धन जुटाने, ध्वजारोहण और रैलियां आयोजित की जाती हैं। इस दिवस का महत्व यह है कि यह दिवस स्काउटिंग के उन मूल्यों (अनुशासन, देशभक्ति, सेवा) को पुनर्जीवित करता है, जो युवाओं को भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करते हैं। यदि हम यहां पर स्काउटिंग,जिसे शांति और भाईचारे का उत्सव भी कहा जाता है, के इतिहास पर नजर डालें तो उपलब्ध जानकारी के अनुसार स्काउटिंग की शुरुआत एक प्रयोगात्मक कैंप से हुई थी। दरअसल, लॉर्ड बेडन पॉवेल ने इंग्लैंड के ब्राउंसी द्वीप पर वर्ष 1907 में पहला कैंप लगाया था। गौरतलब है कि स्काउटिंग की शुरुआत किसी खेल या शौक के रूप में नहीं हुई थी। बैडेन-पॉवेल ने अपने सैन्य अनुभवों से प्रेरणा लेकर युवाओं में चरित्र निर्माण और आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए यह आंदोलन शुरू किया था। पाठकों को बताता चलूं कि स्काउट सैल्यूट के पीछे भी एक अर्थ है। दरअसल,तीन उंगलियों वाला स्काउट सलाम तीन मूल सिद्धांतों क्रमशः ईश्वर और देश के प्रति कर्तव्य, दूसरों की मदद तथा स्काउट नियमों के पालन का प्रतीक है। उल्लेखनीय है कि दुनिया भर के स्काउट्स एक-दूसरे से बाएं हाथ (लेफ्ट हैंड) से हाथ मिलाते हैं। इसके पीछे का तर्क यह है कि बायां हाथ दिल के करीब होता है और यह गहरी मित्रता और विश्वास का प्रतीक है। इसके अलावा, युद्ध के समय योद्धा अपना बचाव करने वाली ढाल (शील्ड) बाएं हाथ में रखते थे; बाएं हाथ से हाथ मिलाने का मतलब था ढाल को नीचे रखना, जो सामने वाले पर पूर्ण विश्वास को दर्शाता है। पाठकों को यह जानकर आश्चर्य होगा कि चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग एक ईगल स्काउट थे। वे अपने साथ चंद्रमा पर स्काउटिंग का बैज भी ले गए थे। रिकॉर्ड के अनुसार, चंद्रमा पर जाने वाले 12 अंतरिक्ष यात्रियों में से 11 किसी न किसी रूप में स्काउटिंग से जुड़े रहे थे। बहुत कम लोग ही यह बात जानते होंगे कि स्काउट जो गले में स्कार्फ पहनते हैं, वह सिर्फ वर्दी का हिस्सा नहीं है, बल्कि इसके पीछे कुछ वैज्ञानिक तथ्य भी हैं। दरअसल, इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि आपातकालीन स्थिति में इसका उपयोग पट्टियों (बैंडजेज) के रूप में, खून रोकने के लिए, या झुलसे हुए हाथ को सहारा देने के लिए किया जा सके। स्काउट के पास स्कार्फ को बांधने वाला एक छल्ला होता है,जिसे वोगल कहा जाता है। गांठ बांधना (नोटिंग) स्काउटिंग का मुख्य हिस्सा है। इतना ही नहीं, स्काउट बेल्ट अक्सर चमड़े या मजबूत कपड़े की होती है, जिसमें हुक लगे होते हैं ताकि जरूरत पड़ने पर भारी सामान या औजार लटकाए जा सकें। वहीं, बैज स्काउट की दक्षता, उसकी रैंक और उसके द्वारा सीखे गए कौशलों (जैसे प्राथमिक चिकित्सा, तैराकी, खाना बनाना) को दर्शाते हैं।जब स्काउट कैंपिंग या ट्रेकिंग पर होते हैं, तो उनके पास एक सर्वाइवल किट मौजूद होती है, जिसमें क्रमशः रस्सी (टेंट लगाने, पुल बनाने या किसी को बचाने में प्रयोग), चाकू या पेननाइफ;सीटी(संकट के समय संकेत देने के लिए) तथा कंपास और नक्शा भी मौजूद होता है। इसके अलावा,आपातकालीन सामग्री में क्रमशः फर्स्ट एड बॉक्स,माचिस या फ्लिंट तथा टॉर्च,व्यक्तिगत डायरी और पेन भी प्रत्येक स्काउट के पास होते हैं।स्काउटिंग इतनी प्रसिद्ध रही है कि फिल्मों तक में इसका प्रभाव देखने को मिलता है। पाठकों को बताता चलूं कि प्रसिद्ध फिल्म निर्माता स्टीवन स्पीलबर्ग ने अपनी फिल्म इंडियाना जोन्स के मुख्य किरदार को एक स्काउट के रूप में दिखाया था क्योंकि वे स्वयं एक स्काउट थे और फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्हें अपने पुराने अनुभवों से काफी मदद मिली थी। बहरहाल, यहां यह भी गौरतलब है कि आज स्काउटिंग दुनिया के लगभग हर देश में मौजूद है और करोड़ों युवा इससे जुड़े हैं। वैश्विक स्तर पर इसे वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्काउट मूवमेंट संचालित करता है।स्काउट का प्रसिद्ध आदर्श वाक्य बी प्रिपेयर्ड यानी कि सदैव तैयार रहो (उपस्थिति और विवेक) प्रत्येक स्काउट कोजीवन के हर क्षेत्र में मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार रहने की प्रेरणा देता है। कहना ग़लत नहीं होगा कि आज स्काउटिंग सबसे बड़ा स्वैच्छिक युवा संगठन है। दूसरे शब्दों में कहें तो भारत स्काउट्स एंड गाइड्स देश का सबसे बड़ा गैर-राजनीतिक, वर्दीधारी युवा संगठन माना जाता है। बहरहाल, यदि हम यहां पर अपने देश भारत की बात करें तो भारत विश्व के सबसे बड़े स्काउट सदस्य देशों में से एक है और आज स्कूल आधारित स्काउटिंग कार्यक्रमों के कारण सदस्य संख्या लगातार बढ़ती रहती है।महामारी, आपदा राहत और सामाजिक अभियानों में स्काउट-गाइड की बड़ी भूमिका रही है। दिलचस्प तथ्य यह है कि भारत का स्काउट संगठन विश्व के 170 से अधिक देशों के स्काउट आंदोलन से जुड़ा हुआ है तथा इसका कार्य क्षेत्र क्रमशः चरित्र निर्माण, सामुदायिक सेवा, आपदा राहत, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य जागरूकता और नेतृत्व प्रशिक्षण है। पाठकों को बताता चलूं कि भारत में स्काउट-गाइड आंदोलन से लगभग 60 लाख से अधिक बच्चे और युवा (विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों और आयोजनों के संदर्भ में) जुड़े हुए बताए जाते हैं । इसकी स्थापना के बारे में यदि हम यहां पर बात करें तो वर्तमान संगठन का गठन 1950 में हुआ (स्काउट) और 1951 में गाइड संगठन के एकीकरण के बाद पूर्ण रूप से बना।भारत में स्काउटिंग का संचालन मुख्य रूप से भारत स्काउट्स एंड गाइड्स (बीएसजी) द्वारा किया जाता है, जो देश का राष्ट्रीय स्काउट-गाइड संगठन है।

भारत का भाग्य,भविष्य और भय के बीच खड़ा कृत्रिम बुद्धिमत्ता युग

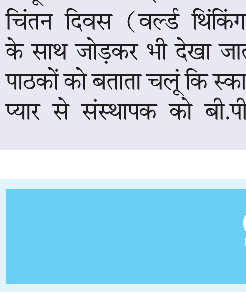

लेखक-विनोद कुमार सिंह

नई दिल्ली के भारत मंडपम में 16 से 20 फरवरी 2026 तक आयोजित एआई इम्पैक्ट सम्मेलन भारत के आधुनिक इतिहास में एक निर्णायक क्षण के रूप में दर्ज किया जाएगा।यह केवल एक अन्तराष्ट्रीय तकनीकी सम्मेलन नहीं था,बल्कि एक सभ्यतागत घोषणा थी - कि भारत अब अपनी नियति कृत्रिम बुद्धिमत्ता की शक्ति से गढ़ना चाहता है।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के नेतृत्व में यह आयोजन भारत की उस महत्त्वाकांक्षा का प्रतीक बना, जिसमें तकनीक विकास का साधन नहीं,बल्कि राष्ट्र-निर्माण का दर्शन बन रही है।प्रधानमंत्री मोदी ने उद्घाटन भाषण में जिस आत्म विश्वास से कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता भारत का भाग्य और भविष्य है,वह कथन किसी राजनीतिक भाषण से अधिक एक रणनीतिक उद्घोष था।यह उस भारत की आवाज़ थी,जो औपनिवेशिक युग में औद्योगिक क्रांति से वंचित रहा, जिसने सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति में सेवा क्षेत्र तक स्वयं को सीमित रखा,और अब तीसरी बड़ी तकनीकी क्रांति—कृत्रिम बुद्धिमत्ता - में नेतृत्व की आकांक्षा रखता है। मोदी सरकार के लिए एआई केवल तकनीकी उपकरण नहीं,बल्कि विकसित भारत 2047 के स्वप्न का मुख्य इंजन है।जिस प्रकार बीसवीं सदी में रेल,बिजली और सड़क राष्ट्र-निर्माण की आधारशिला बने, उसी प्रकार इक्कीसवीं सदी में डेटा, एल्गोरिद्म और सुपरकंप्यूटिंग को राष्ट्रीय बुनियादी ढाँचे के रूप में देखा जा रहा है।प्रधानमंत्री ने एआई को "डिजिटल स्वराज" का मार्ग बताया - एक ऐसा स्वराज जिसमें भारत तकनीक का उपभोक्ता नहीं, बल्कि निर्माता और नियंता होगा। अश्विनी वैष्णव का दृष्टिकोण इस स्वप्न को संस्थागत ढाँचा देने का प्रयास है।उन्होंने एआई को राष्ट्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर की संज्ञा देते हुए कहा कि भारत को अपने स्वयं के फाउंडेशन मॉडल,राष्ट्रीय डेटा ग्रिड और सुपरकंप्यूटिंग क्षमता विकसित करनी होगी।उनका मानना था कि एआई भारत के लिए वही भूमिका निभाएगा, जो बीसवीं सदी में रेलवे और बिजली ने निभाई—देश को जोड़ने और गति देने की भूमिका। एआई इम्पैक्ट सम्मेलन में कई रणनीतिक घोषणाएँ की गईं, जो भारत के तकनीकी भविष्य की दिशा निर्धारित करती हैं।सरकार ने राष्ट्रीय एआई कंप्यूट ग्रिड, स्वदेशी भाषा मॉडल,सरकारी सेवाओं में एआई के व्यापक उपयोग,स्वास्थ्य और शिक्षा में डिजिटल प्लेटफॉर्म, स्मार्ट शहरों और रक्षा प्रणालियों में एआई आधारित समाधान विकसित करने की प्रतिबद्धता दोहराई। भारत को एआई अनुसंधान, स्टार्टअप और उद्योग का वैश्विक केंद्र बनाने के लिए नीति,वित्त और अवसंरचना के समन्वित प्रयासों की घोषणा की गई।इस सम्मेलन की एक प्रमुख उपलब्धि विदेशी निवेश को आकर्षित करने की दिशा में थी। वैश्विक टेक कंपनियों, निवेश फंडों और बहुराष्ट्रीय निगमों ने भारत के एआई पारिस्थितिकी तंत्र में निवेश की रुचि दिखाई।डेटा सेंटर,क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, सेमीकंडक्टर, चिप डिजाइन और एआई स्टार्टअप में अरबों डॉलर के निवेश प्रस्तावों की चर्चा हुई।भारत को एआई निर्माण और अनुसंधान का वैश्विक हब बनाने के लिए कई अंतरराष्ट्रीय साझेदारियों की घोषणा की गई। यह संकेत है कि वैश्विक पूंजी भारत को अगली तकनीकी क्रांति का महत्वपूर्ण केंद्र मान रही है। विदेशी निवेश के साथ रोजगार की संभावनाएँ भी इस सम्मेलन का केंद्रीय विषय रहीं।सरकार और उद्योग जगत का दावा है कि एआई भारत में लाखों नई नौकरियाँ पैदा करेगा - डेटा वैज्ञानिक, एआई इंजीनियर, साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ, चिप डिजाइनर, डिजिटल सेवा प्रदाता और तकनीकी प्रशिक्षक जैसे क्षेत्रों में। साथ ही, एआई आधारित स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और प्रशासनिक सेवाओं में नए प्रकार के रोजगार उत्पन्न होंगे। यह आशा व्यक्त की गई कि भारत की विशाल युवा जनसंख्या को एआई युग के लिए कौशल प्रदान कर वैश्विक कार्यबल का नेतृत्व करने के लिए तैयार किया जाएगा। परंतु इतिहास हमें सिखाता है कि हर तकनीकी क्रांति अवसरों के साथ विस्थापन भी लाती है। औद्योगिक क्रांति ने पारंपरिक कारीगरों को विस्थापित किया, सूचना क्रांति ने डिजिटल डिवाइड को जन्म दिया, और एआई क्रांति मानव श्रम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा कर रही है।मशीनें न केवल शारीरिक श्रम, बल्कि बौद्धिक श्रम भी करने लगी हैं।पत्रकारिता, बैंकिंग, कानून,शिक्षा,चिकित्सा और प्रशासन जैसे क्षेत्रों में एआई का प्रवेश तेजी से हो रहा है।आम आदमी के मन में यह भय स्वाभाविक है कि कहीं यह तकनीक उसकी आजीविका न छीन ले।सरकार कौशल विकास और पुनः प्रशिक्षण की बात करती है, परंतु भारत जैसे विशाल और विविध समाज में यह कार्य कितना प्रभावी होगा, यह एक खुला प्रश्न है। ग्रामीण,असंगठित और कम शिक्षित श्रमिक वर्ग के लिए एआई युग में समायोजन आसान नहीं होगा।

दुबई टेनिस चैंपियनशिप

कोको गॉफ को हराकर फाइनल में एलिना स्वितोलिना

दुबई (एजेंसी)। यूक्रेन की स्टार टेनिस खिलाड़ी एलिना स्वितोलिना ने दुबई टेनिस चैंपियनशिप के महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में अमेरिका की कोको गॉफ को तीन सेटों के कड़े मुकाबले में हराकर फाइनल में जगह बना ली। तीन घंटे तीन मिनट तक चले इस रोमांचक मैच में स्वितोलिना ने 6-4, 6-7 (13), 6-4 से जीत दर्ज की। मुकाबले के दौरान उन्होंने कई मैच प्वाइंट गंवाए, लेकिन निर्णायक सेट में दमदार वापसी कर जीत अपने नाम की।

- **मैराथन टाई-ब्रेक के बाद जबरदस्त वापसी-** दूसरे सेट का टाई-ब्रेक बेहद रोमांचक रहा, जिसे स्वितोलिना 13-15 से हार गईं। इसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और तीसरे सेट में संयम व आक्रामक खेल का बेहतरीन संतुलन दिखाते हुए मुकाबला जीत लिया। यह दुबई में उनका तीसरा फाइनल है और 2018 के बाद पहला।
- **भावुक हुई स्वितोलिना-** मैच के बाद कोर्ट पर दिए इंटरव्यू में स्वितोलिना ने कहा, उस लड़ाई के बाद मेरे पास शब्द नहीं थे। मैं पूरी ताकत झोंक रही थी और ऐसे खेल रही थी जैसे कल है ही नहीं। आप सभी के समर्थन के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। कुछ सालों बाद यहां फिर से फाइनल में होना और उस खूबसूरत ट्रॉफी को उठाने का मौका मिलना बहुत खास है। इस जीत के साथ स्वितोलिना ने डब्ल्यूटीए टूर स्तर पर कोको गॉफ के खिलाफ अपना हेड-टू-हेड रिकॉर्ड 3-2 कर लिया है। अब वह फाइनल में अमेरिका की जेसीका पेगूला से भिड़ेंगी।

ऑस्ट्रेलिया ने टी-20

वर्ल्डकप में आखिरी मैच जीता

ओमान को 9 विकेट से हराया, मार्श-हेड ने 93 रन जोड़े, जम्पा को 4 विकेट

पल्लेकेले (एजेंसी)। ऑस्ट्रेलिया ने टी-20 वर्ल्ड कप 2026 जीत के साथ खत्म किया। टीम ने शुक्रवार को आखिरी ग्रुप स्टेज मैच में ओमान को 9 विकेट से हरा दिया। कैंडी के पल्लेकेले स्टेडियम में पहले बैटिंग करने उतरी ओमान 104 रन पर सिमट गई। मिचेल मार्श और ट्रैविस हेड ने 93 रन की पार्टनरशिप कर कंगारू टीम को जीत दिला दी। ऑस्ट्रेलिया के लिए गेंदबाजी में लेग स्पिनर एडम जम्पा ने 4 विकेट लिए। ग्लेन मैक्सवेल और जैवियर बार्टलेट को 2-2 विकेट मिले। कप्तान मार्श ने फिफ्टी लगाई, वहीं ट्रैविस हेड 32 रन बनाकर आउट हुए। ओमान के लिए वसीम अली ने सबसे ज्यादा 32 रन बनाए।

ऑस्ट्रेलिया को 2 हार मिली

ऑस्ट्रेलिया की टीम ग्रुप-बी में श्रीलंका और जिम्बाब्वे के खिलाफ हार कर बाहर हो गई। टीम ने आयरलैंड और ओमान को हराया, लेकिन ये अगले राउंड में पहुंचने के लिए काफी नहीं था। टीम 2009 के बाद पहली बार ग्रुप स्टेज को भी पार नहीं कर सकी।

टी20 विश्व कप के सुपर आठ मुकाबला

भारत- अफ्रीका में टक्कर आज

- सेमीफाइनल की ओर कदम बढ़ाने उतरेगी भारतीय टीम
- साउथ अफ्रीका 2024 फाइनल का हिसाब बराबर करना चाहेगी

अहमदाबाद (एजेंसी)। ग्रुप चरण में अपने चारों मैच जीतने वाली भारतीय टीम को टी20 विश्व कप के सुपर आठ में रविवार को दक्षिण अफ्रीका की कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। भारत ने खिताब बचाने की अपनी दावेदारी को मजबूत किया है, लेकिन उसकी असली परीक्षा अब शुरू होगी। दक्षिण अफ्रीका की टीम के पास कगिसो रबाडा, लुंगी एनगिडी, मार्को यानसेन, केशव महाराज और एडेन मार्करम के रूप में मजबूत गेंदबाजी आक्रमण है जो मौजूदा चैंपियन भारत की कड़ी परीक्षा लेने के लिए तैयार है।

भारत को बल्लेबाजी में करना होगा सुधार- भारत और दक्षिण अफ्रीका की टीमें पिछले दो महीनों में छठी बार एक-दूसरे के खिलाफ खेलेंगी और यह देखना बाकी है कि रविवार को कौन सी टीम परिस्थितियों का बेहतर फायदा उठाएगी। भारतीय टीम को ग्रुप चरण में खास चुनौती का सामना नहीं करना पड़ा लेकिन वह इस बात से अच्छी तरह वाकिफ है कि उसकी बल्लेबाजी में काफी सुधार की जरूरत है।

मजबूत है गेंदबाजी आक्रमण

भारत को एक बात जो खतरनाक टीम और अब भी खिताब का प्रबल दावेदार बनाती है, वह है उसका गेंदबाजी आक्रमण जिसमें जसप्रीत बुमराह और वरुण चक्रवर्ती के महत्वपूर्ण आठ ओवर शामिल हैं। पहले चरण में पाकिस्तान सहित कोई भी अन्य टीम भारतीय गेंदबाजों का सहजता से सामना नहीं कर पाई थी। वरुण ने चार मैचों में नौ विकेट लिए हैं और उन्होंने 5.16 की शानदार इकोनॉमी रेट से गेंदबाजी की है। बुमराह ने जो तीन मैच

बल्लेबाजों को निभानी होगी जिम्मेदारी- भारतीय टीम के लिए भले ही अभिषेक की फॉर्म चिंता का विषय बनी हुई है, लेकिन पहले चरण में तिलक की लचर बल्लेबाजी को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। पाकिस्तान के खिलाफ उन्होंने 24 गेंदों में 25 रन, नामीबिया के खिलाफ 21 गेंदों में 25 रन और नीदरलैंड के खिलाफ 27 गेंदों में 31 रन बनाए। इस तरह से वह अभी तक अधिकतर मैच में रन बनाने के लिए संघर्ष करते रहे। टूर्नामेंट में उनका स्ट्राइक रेट 120 से थोड़ा ऊपर है जो उनके करियर के स्ट्राइक रेट 141 से काफी कम है।

न्यूजीलैंड-पाकिस्तान

ओपनिंग से नंबर 4 पर पहुंचे बाबर आजम

- *हेड कोच हेसन ने बताई रणनीति में बदलाव की वजह*

कोलंबो (एजेंसी)। पाकिस्तान टीम सुपर 8 के अपने पहले मुकाबले से पहले रणनीतिक बदलावों को लेकर चर्चा में है। खासतौर पर बाबर आजम की भूमिका को लेकर हेड कोच माइक हसन का बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ग्रुप स्टेज में बाबर का प्रदर्शन उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा, जिसके बाद उन्हें ओपनिंग से हटाकर नंबर चार पर भेजने का फैसला किया गया।

ग्रुप स्टेज में बाबर का फीका प्रदर्शन- ग्रुप चरण के चार मुकाबलों में बाबर आजम ने सिर्फ 66 रन बनाए। औसत- 22, स्ट्राइक रेट- 115.78; टी20 जैसे फॉर्मेट में यह आंकड़े टीम की जरूरत के मुताबिक नहीं माने जा रहे हैं। खासकर पावरप्ले में उनका स्ट्राइक रेट 100 से कम रहा, जो टीम मैनेजमेंट की चिंता का बड़ा कारण बना।

रणनीतिक बदलाव

21 फरवरी को होने वाले मैच से पहले प्री-मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में माइक हेसन ने साफ कहा कि बाबर खुद अपने आंकड़ों से वाकिफ हैं। हेसन ने कहा- पावरप्ले में उनका स्ट्राइक रेट 100 से कम रहा है। इसलिए यह वह भूमिका नहीं है जिसकी हमें यहां जरूरत है। हेसन के मुताबिक, एशिया कप के बाद ही यह योजना बनाई गई थी कि बाबर को मिडिल ऑर्डर में भेजा जाए, ताकि वह जरूरत पड़ने पर पारी को संभाल सकें और टीम को स्थिरता दे सकें।

नॉट द बेस्ट पर्सन -बयान क्यों हुआ वायरल- हेसन का चार शब्दों वाला बयान — नाट द बेस्ट पर्सन सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया। उन्होंने कहा कि 12वें ओवर के बाद जब तेजी से रन बनाने की जरूरत होती है, तब बाबर उस भूमिका के लिए सबसे उपयुक्त खिलाड़ी नहीं हैं।

पाकिस्तान को मात्र 56 रन पर किया ढेर

राइजिंग स्टार्स एशिया कप के फाइनल में पहुंचा बांग्लादेश

बैंकॉक (थाईलैंड) (एजेंसी)। बांग्लादेश की महिला टीम ने पाकिस्तान को सिर्फ 56 रन पर आउट कर राइजिंग स्टार्स एशिया कप सेमीफाइनल में 54 रन से बड़ी जीत हासिल करते हुए फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली। बांग्लादेश की कप्तान फहीमा खातून के ऑल-राउंड प्रदर्शन और संजीदा अख्तर मेघला के 3 विकेट की मदद से उन्हें जीत मिली। पाकिस्तान महिला टीम की शानदार बॉलिंग की वजह से बांग्लादेश ने 20 ओवर में 110 रन बनाए। अब बांग्लादेश रविवार को टेर्डथाई क्रिकेट ग्राउंड पर फाइनल में भारत से भिड़ेगा।

पाकिस्तान ए महिला टीम ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग करने का फैसला किया। बांग्लादेश के लिए इश्मा तंजीम और शमीमा सुल्ताना ने पारी की शुरुआत की। उनकी शुरुआत धीमी रही, पावर प्ले 27/1 पर खत्म हुआ, चौथे ओवर में सुल्ताना 13 गेंदों पर 13 रन बनाकर वहीदा अख्तर की गेंद पर आउट हो गईं। 10 ओवर के बाद पाकिस्तान मजबूत स्थिति में था, बांग्लादेश का स्कोर 44/3 था। इश्मा तंजीम 23 गेंदों पर 12 रन बनाकर अनोशा नासिर की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गईं और सरमिन सुल्ताना 20 गेंदों पर 15 रन

बनाकर ओमैमा सोहेल की गेंद पर आउट हुईं।

खातून टीम की अकेली शानदार बैट्समैन थीं जो आठवें ओवर से लेकर इनिंग्स के आखिर तक क्रीज पर टिकी रहीं और 32 गेंदों पर 5 बाउंड्री की मदद से 40 रन बनाकर नॉट-आउट रहीं। पाकिस्तान की तरफ से यह शानदार बॉलिंग का प्रदर्शन था, जिसने बांग्लादेश को 20 ओवर में 110/8 के छोटे से टोटल पर रोक दिया।

उम्मीद थी कि पाकिस्तान आसानी से जीत जाएगा, लेकिन बंगाल टाइग्रेसेस के प्लान कुछ और थे। उन्होंने शानदार शुरुआत की, फरिहा त्रिसना ने तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर ओपनर इमान नासिर को 12 गेंदों पर सिर्फ 4 रन के स्कोर पर आउट किया। तीन ओवर के बाद पाकिस्तान का स्कोर 8/1 था। अगले ओवर में संजीदा अख्तर मेघला ने हुरैना सज्जाद को बिना खाता खोले आउट कर दिया। पावरप्ले तक पाकिस्तान का स्कोर 21/2 हो गया। पावरप्ले के बाद खातून ने शवाल जुल्फिकार को 17 गेंदों पर 14 रन पर बोल्ड कर दिया। खातून जबरदस्त फॉर्म में थीं। उन्होंने पहले नौवें ओवर की तीसरी गेंद पर गुल रुख (2) को रन आउट किया और फिर आखिरी गेंद पर सोहेल को आउट किया।

छह साल के शीर्ष पर पहुंच सकता है सऊदी अरब से तेल का आयात

नई दिल्ली, एजेंसी। भारत इस महीने सऊदी अरब से छह साल से अधिक समय में सबसे अधिक कच्चे तेल का आयात करने जा रहा है। रूस से कच्चे तेल की खरीदारी कम करने के लिए अमेरिका के भारत पर लगातार दबाव बनाने के कारण यह स्थिति उत्पन्न हुई है। केप्लर के प्रमुख अनुसंधान विश्लेषक सुमित रितोलिया के अनुसार, सऊदी अरब से तेल की आपूर्ति बढ़कर 10 लाख से 11 लाख बैरल प्रतिदिन होने की संभावना है। यह नवंबर, 2019 के बाद से उच्च स्तर होगा। यह रूस के अनुरूप है, जिससे दोनों आपूर्तिकर्ताओं के बीच का अंतर काफी हद तक कम हो जाएगा। यूक्रेन पर आक्रमण के बाद भारत की ओर से रूसी तेल की खरीद बढ़ाने के कारण यह अंतर काफी बढ़ गया था।

भारत पर अमेरिकी दबाव इस महीने की शुरुआत में तब ज्यादा हो गया, जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत एक व्यापार समझौते के तहत रूसी तेल की खरीदारी बंद करने पर सहमत हो गया है। हालांकि, भारत ने इस दावे पर सार्वजनिक रूप से कोई सीधा जवाब नहीं दिया है। अगर तेल का प्रवाह 12 लाख बैरल प्रतिदिन तक पहुंचता है तो रूस इस महीने भी भारत का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बना रहेगा, लेकिन शिपमेंट में और भी गिरावट आने का अनुमान है।

2022 में यूक्रेन पर हुए आक्रमण के बाद भारत रूसी तेल का एक प्रमुख खरीदार बनकर उभरा, क्योंकि ओपेक और अन्य उत्पादक देश रूस को अपने तेल की कीमतों में भारी छूट देनी पड़ी। ऐसा इसलिए, क्योंकि अधिकांश अन्य खरीदार मॉस्को से जुड़ी ऊर्जा से दूर भाग रहे थे। भारत ने तब प्रतिदिन 20 लाख बैरल रूसी तेल आयात किया था।

रूस से और घटेगा आयात

केप्लर ने कहा, अगले महीने रूस से आयात में और कमी आ सकती है।यह आयात प्रतिदिन 8 से 10 लाख बैरल के बीच रहेगा। यूरोपीय संघ के लगाए गए प्रतिबंधों के बाद रूसी कच्चे तेल पर पूरी तरह निर्भर नायरा एनर्जी की ओर से संचालित रिफाइनरी में अप्रैल एवं मई के दौरान रखरखाव कार्य के कारण होने वाले बंद से आयात की मात्रा में और भी कमी आने की आशंका है। रूस के लिए भारत में अपनी हिस्सेदारी खोना यूक्रेन युद्ध के बाद यूरोप से विस्थापित हुए उसके तेल के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार को कमजोर कर देता है।

चर्चित डिफेंस कंपनी ने हिमांशी थर्मल में 49 प्रतिशत हिस्से का अधिग्रहण किया, 4 प्रतिशत चढ़ा शेयर

पारस डिफेंस ने क्या कुछ बताया, शेयरों का हो चुका हैं बंटवारा

मुंबई, एजेंसी। पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजी के शेयरों की कीमतों में 4 प्रतिशत से अधिक की तेजी देखने को मिली। इस उछाल के पीछे की वजह अधिग्रहण से जुड़ी एक खबर है। पारस डिफेंस ने हिमांशी थर्मल में 49 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीद लिया है।

बीएसई में पारस डिफेंस का शेयर 630.30 रुपये के लेवल पर खुला था। दिन में यह स्टॉक 4 प्रतिशत से अधिक की तेजी के साथ 657.80 रुपये के इंट्रा-डे हाई पर पहुंच गया। हालांकि, इसके बाद थोड़ी सी नरमी देखने को मिली। जिसकी वजह से कंपनी के शेयरों का भाव 644 रुपये के स्तर पर आ गया।

कंपनी ने एक्सचेंज को दी जानकारी में बताया है कि उन्होंने हिमांशी थर्मल सॉल्यूशंस में 49 प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल की है। कंपनी ने बताया है कि यह रणनीतिक विस्तार के लिए काफी मददगार रहने वाला है। बीते एक महीने के दौरान कंपनी के शेयरों की कीमतों में 2.52 प्रतिशत की तेजी आई है। वहीं, एक साल में कंपनी के शेयरों का भाव 42 प्रतिशत बढ़ा है। इस दौरान सेंसेक्स इंडेक्स में 9.31 प्रतिशत की तेजी आई है। कंपनी का 52 वीक हाई 971.80 प्रतिशत है। वहीं, 52 वीक लो लेवल 401 रुपये है। कंपनी का मार्केट कैप 5167 करोड़ रुपये का है। दिसंबर तिमाही के दौरान पारस डिफेंस की कुल सेल्स 106.35 करोड़ रुपये रहा है। जोकि सालाना आधार पर 23.99 प्रतिशत अधिक है। एक साल पहले इसी तिमाही में पारस डिफेंस का सेल्स 85.77 करोड़ रुपये रहा था। अक्टूबर से दिसंबर 2025 के दौरान कंपनी का नेट प्रॉफिट 18.21 करोड़ रुपये रहा था। दिसंबर तिमाही में डिफेंस कंपनी का ई बी आई टी डी ए 28.49 करोड़ रुपये रहा है। 2025 में कंपनी के शेयरों का बंटवारा हुआ था। तब कंपनी ने एक शेयर को दो हिस्सों में बांट दिया था। जिसके बाद कंपनी के शेयरों की फेस वैल्यू 10 रुपये से घटकर 5 रुपये प्रति शेयर हो गया था।

अकाउंट में पैसे नहीं तब भी निकाल सकेंगे 10 हजार, मोदी सरकार की खास स्कीम

नईदिल्ली, एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल की लोकप्रिय योजनाओं में से एक जनधन अकाउंट खोलना भी रहा है। इस योजना के तहत अकाउंटहोल्डर को ना सिर्फ इंश्योरेंस कवर मिलता है बल्कि ओवरड्राफ्ट लिमिट की भी सुविधा है। बता दें कि ओवरड्राफ्ट एक फाइनेंशियल सुविधा है, इसके द्वारा आप अपने बैंक अकाउंट से तब भी पैसे निकाल जब उसमें पैसे ना हों। जनधन खाताधारक को ओवरड्राफ्ट लिमिट 10 हजार रुपये तय है। आइए इस योजना के बारे में विस्तार से जान लेते हैं।

जनधन अकाउंट, खाताधारक की विविध वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें शून्य-शेष खाते, बीमा वाले रुपे डेबिट कार्ड, ओवरड्राफ्ट ऑप्शन जैसी सुविधाएं शामिल हैं। यह पहल लाभार्थियों को बेहतर वित्तीय स्थिरता के लिए अन्य सरकारी कार्यक्रमों से भी जोड़ती है। बता दें कि करीब 11 साल पहले नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल में इसकी शुरुआत हुई थी। स्टैंडर्ड बैंक खाता खोलने के लिए पात्र है, वह बेसिक बचत बैंक जमा खाता (बीएसबीडीए) भी खोल सकता है। इस प्रकार के खाते में न्यूनतम शेष राशि रखने की जरूरत नहीं होती है। ट्रांजैक्शन बैंक शाखाओं, एटीएम और बैंकिंग सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से किए जा सकते हैं। इसमें प्रति माह निकासी चार है। वहीं, औपचारिक कानूनी दस्तावेजों के बिना व्यक्तियों के लिए, छोटे खाते खोले जा सकते हैं। ये 12 महीनों के लिए वैध होते हैं और यदि पहले वर्ष के भीतर आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज के लिए आवेदन का प्रमाण प्रस्तुत किया जाता है, तो 12 महीनों के लिए और बढ़ाया जा सकता है। खाताधारक को दुर्घटना बीमा के साथ रुपे डेबिट कार्ड भी मिलता है। सभी लाभार्थियों को 2 लाख बीमा कवर मिलना अनिवार्य है। हालांकि, 28 अगस्त 2018 से पहले खोले गए खातों के लिए 1 लाख के दुर्घटना बीमा कवर का प्रावधान है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक सैयद ज़की हैदर के लिए इरानीयन आर्ट प्रिंटर्स 1534 कासिमजान स्ट्रीट दरियागंज नई दिल्ली 11006 से मुद्रित कराकर, 2684 गली काले खां कूचा चलान दरियागंज नई दिल्ली 02 से प्रकाशित किया।
संपादक : सैयद ज़की हैदर- हैड ऑफिस :- एफ19/4 सेकेंड फ्लोर नफीश रोड जामिया नगर दिल्ली- 110025., सम्पर्क सूत्र :- 9911371802, 9810383593
जितेन्द्र कुमार बिस्वाल ब्यूरो चीफ उड़ीसा/ गोविंद कनोडिया/ पटना/ सैय्यद यूसुफ अली नक़वी-पॉलिटिकल एडिटर। ई-मेल:- (LOKTANTRAKISHAAN@GMAIL.COM

किसी भी प्रकार के विवाद हेतु निपटारे के लिए केवल दिल्ली न्यायालय ही मान्य होगी।
नोट- किसी भी समाचार/आलेख पर दावा प्रति दावा/आपत्ति समाचार प्रकाशन के 15 दिनों के अन्तराल तक ही मान्य होगा। समाचार पत्र में प्रकाशित आलेख से संपादक/प्रकाशक का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

क्षेत्रीय कार्यालय अनवार मंजिल नया टोला गंज नंबर 01 बेतिया/ बिहार/ पिन नंबर 84 5438/>> संवाददाता, सना खान/(डॉ. अमानुल हक) स्थानीय संपादक/बिहार)